



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]
No. 232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ ASADHA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिवेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया मूल की अथवा वहां से निर्यातित “बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर” के आयातों पर लगे पाटन-रोधीशुल्कों से संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच।

A. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 15/9/2015-डीजीएडी.—1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनिशिया मूल की अथवा वहां से (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) निर्यातित निर्यातित “बांसफाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटन-रोधी जांच शुरू की थी जिसके फलस्वरूप दिनांक 5 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और अनन्तिम शुल्क लगाया था।

2. यतः प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम में दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनिशिया मूल की अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित “बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर” के आयातों पर सुनिश्चियात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 76/2010-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चियात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे।

3. और यतः कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम और दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 76/2010-सीमा-शुल्क द्वारा लगाए गए सुनिश्चियात्मक पाटन-रोधी शुल्क को चुनौती देते हुए अपीलें दायर की थीं। माननीय सीईएसटीएटी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग की दलीलों की गहन सुनवाई करने

के बाद आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की निर्णय-पश्चात् और सुनवाई करने, यदि कोई हो, और ऐसे निर्णय पश्चात् सुनवाई करने के परिणामस्वरूप यदि अंतिम परिणाम में कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता हो, तो उसे करने के लिए, इस मामले को वापस प्राधिकारी को भेज दिया था। प्राधिकारी ने दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए अपने पूर्व अंतिम परिणाम की संपुष्टि करते हुए दिनांक 10 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/6/2009-डीजीएडी द्वारा निर्णय पश्चात् अपना अंतिम परिणाम जारी किया था।

4. यतः घरेलू उद्योग की ओर से भारतीय मानव निर्मित फाईबर उद्योग संघ (जिसे आगे याचिकादाता कहा गया है) द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है। इसके एक सदस्य, मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मात्र उत्पादक (जिसे आगे याचिकादाता कंपनी कहा गया है) है और उसने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक सूचना प्रदान की है।

5. इस तथ्य से संतुष्ट होते हुए कि याचिकादाता ने निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, प्राधिकारी ने दिनांक 22 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/9/2015-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 37/2015-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की वैधता को 25 जुलाई, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।

B. क्रिया-विधि

6. इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2015 को एक अधिसूचना संख्या 15/9/2015-डीजीएडी जारी की थी जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी।
- (2) प्राधिकारी ने पत्र के साथ अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देशों में सभी जात निर्यातिकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग संघों (जिनके ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की थी और उन्हें पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था।
- (3) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों के जात निर्यातिकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति प्रदान की थी। अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आवेदन पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी।
- (4) संबद्ध देशों के निर्यातिकों/उत्पादकों को भेजी गई पत्र और निर्यातिक की प्रश्नावली की प्रति, जात निर्यातिकों/उत्पादकों की सूची सहित भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी।
- (5) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित जात निर्यातिकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए उनको निर्यातिक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. पी. टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस
2. पीटी इंडो भारत रेयन
3. हेब्रेई जिगाओ केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
4. हुब्रेई केमिकल फाईबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
5. सतेरी (जिआंगसी) केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड
6. चाईना जिआंगसू आयोयांग टेक्नालॉजी कार्पोरेशन लिमिटेड
7. चिक हेलोन कंपनी लिमिटेड
8. किसनजियांग फुलिदा फाईबर कंपनी लिमिटेड
9. तांगशान सानयू केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी
10. शानडोग यामेई टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड

(6) भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातिक के रूप में निम्नलिखित कंपनियों ने निर्यातिक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

2. तांगशान सानयू यायूंडा फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
3. तांगशान सानयू युप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
4. बिरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य
5. पी.टी.इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया
6. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया

(7) प्राधिकारी ने अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातों/उपभोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों को प्रेषित की थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे नियम 6 (4) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से अवगत करा दें:-

1. पल्लव टेक्सटाईल्स
2. पल्लीपलयम स्पिनर्स
3. श्री चेरान सिन. इंडिया लिमिटेड
4. केसर मल्टी यार्न मिल लिमिटेड
5. गिन्नी फिलेमेंट्स लिमिटेड
6. जिमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
7. पी.वी.टेक्सटाईल्स लिमिटेड
8. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
9. सूर्यलय स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
10. श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड
11. स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीएलसी)
12. राजस्थान टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसिएशन
13. नार्दन इंडिया टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसिएशन
14. दि सिंथेटिक्स एंड रेयन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रामोशन कांउसिल (एसआरटीपीसी)
15. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन

(8) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. सूर्यलय स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
2. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
3. श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड
4. पी.वी.टेक्सटाईल्स लिमिटेड
5. जिमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
6. मेगनम स्पिनिंग मिल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
7. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन

(9) जांच की कार्रवाई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने भी निवेदन किए हैं/पत्र लिखे हैं, हालांकि उन्होंने प्रश्नावली के विस्तृत उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्तमान निर्धारण करने के लिए इन पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को भी ध्यान में रखा गया है:-

1. कन्फेडरेशन इंडिया टेक्सटाईल इंडस्ट्री (सीआईटीआई)

2. टेक्सटाईल कंजूमर फाउंडेशन (एनजीओ)

3. दि सिंथेटिक्स एंड रेयन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रामोशन कांउसिल (एसआरटीपीसी)

4. अरविंद लिमिटेड लाल भाई गुप्त

5. स्पेन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

6. विक्टरी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

7. चोला स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

8. पवथल स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

9. जेपीपी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

10. अरुणाचला गांडुडर टेक्सटाईल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड (एजीटी मिल्स)

11. एपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(10) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2014 से शुरू होकर मार्च, 2015 (12 महीनों के लिए) तक की है। तथापि, क्षति की जांच अवधि को अप्रैल, 2011 से लेकर जांच अवधि की समाप्ति तक माना गया है, अर्थात् इसमें अप्रैल, 2011 – मार्च, 12, अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013– मार्च, 2014 और जांच अवधि शामिल है।

(11) जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आंकड़े प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आमूचना और सांचियकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। डीजीसीआईएंडएस से उक्त सूचना प्राप्त हो गई है। प्राधिकारी ने इस निर्णय के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विश्वास किया है।

(12) प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सके।

(13) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपी) और डीजीएडी में संगत क्रिया-विधियों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण और बिक्री की लागत के आधार पर गैर-क्षति कीमत का आकलन किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन-रोधी शुल्क, पाटन मार्जिन से कम लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(14) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए 19 जनवरी, 2016 को मौखिक सुनवाई की थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों/प्रदान की गई सूचना का खंडन करने/प्रत्युत्तर देने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

(15) मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से विचार प्रकट करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रकट किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का निदान, प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक माना गया है, इस अंतिम परिणाम की अधिसूचना में कर दिया गया है।

(16) प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए अनुबंध-3 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर जितना संभव हो सका है, घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन-रोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(17) जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों की जांच की गई है। प्रतिवादी नियर्तकों और आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की विस्तार से जांच की गई है।

(18) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें।

(19) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर उसे इस अंतिम परिणाम में रिकार्ड किया है।

(20) निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से निहित प्रकटन विवरण 27.06.2016 को जारी कर दिया गया था, जो कि इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना का आधार बनते हैं। प्रकटन विवरण पर यदि कोई टिप्पणी देनी है तो उसको 04.7.2016 तक प्रस्तुत कर दी जाए। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

(21) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 61.69 रूपए है।

(22) इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

C. विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र और “समान वस्तु”

घरेलू उद्योग के निवेदन

7. विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, “बांस के फाईबर वर्जिंटिविस्कोस स्टेपल फाईबर” है, जिसका व्यापक उपयोग, वस्त्र उद्योग द्वारा मुख्यतया पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के फैशन वियर, होम फर्निशिंग और कालीनों, परिवारों के वास्ते और चिल्ड्रिसकीय प्रयोगों के लिए किया जाता है। इन्हें मुख्यतया दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है—सामान्य विस्कोस फाईबर और मॉडल फाईबर/माइक्रो मॉडल फाईबर। अनेक डेनियरों में विस्कोस फाईबर का उत्पादन किया जाता है। तथापि, विभिन्न डेनियरों की लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर नहीं होता है।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं, उनके विशेष लक्षणों के कारण समान वस्तुएं हैं, जैसे कि भौतिक और रसायनिक लक्षण, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण। ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं।

(ग) विचाराधीन उत्पाद, सीमा-शुल्क विभाग के उप-शीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा-शुल्क विभाग का वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र को बाध्य नहीं करता है।

(घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं पाटन रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर समान वस्तुएं हैं।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

8. विचाराधीन उत्पाद को डेनियर्स आदि के आधार पर विभिन्न किस्मों में पृथक किया जाना चाहिए था और उसके बाद पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उनका विश्लेषण, पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संचया) की किस्मों के अनुसार किया जाना चाहिए था।

9. यह निवेदन किया गया है कि संबद्ध देशों से कोई भी निर्यातिक मॉडल फाईबर/माइक्रो मॉडल फाईबर का उत्पादन नहीं कर रहा है/भारत को अथवा उसके घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति नहीं कर रहा है। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यात उक्त उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रहे हैं, यह आवेदक उद्योग की ओरापित क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मॉडल/माइक्रो मॉडल फाईबर को क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ समान वस्तु नहीं माना जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, निर्यातित “बांस फाईबर वर्जिंट विस्कोस स्टेपल फाईबर” है। इसे सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत सीमा-शुल्क के उप-शीर्ष 550410 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क विभाग का वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र को बाध्य नहीं करता है।

11. वर्तमान याचिका पहले से लागू पाटन-रोधी शुल्क निर्णयिक समीक्षा जांच करने के लिए है। इसकी मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा विचारित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:-

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

“विचाराधीन उत्पाद, नियर्तित “बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर” है। विस्कोस फाईबर को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत “विस्कोस रेयन स्टेपल फाईबर को ऐसे फाईबर के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि कार्डिंग और कास्टिंग नहीं है और इसे कुछ बाजारों में “रेयन फाईबर” के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत सीमा-शुल्क के उप-शीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा-शुल्क विभाग का वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी तरह से मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र को बाध्य नहीं करता है। विस्कोस स्टेपल फाईबर पहला मानव निर्मित फाईबर था और अन्य मानव निर्मित फाईबरों से भिन्न यह सिंथेटिक फाईबर नहीं है। इसे बेट स्पिनिंग प्रोटोटाइपों से विनिर्मित किया जाता है और यह काष्ठ के गूदे से निर्मित रिजेनरेटिड सेल्युलोज फाईबर है, जो कि मुख्यतया सुस्थिर रखने योग्य प्राकृतिक स्रोत अर्थात् काष्ठ का सेल्युलोज है, जिसे विभिन्न रसायनिक और यांत्रिकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विस्कोस स्टेपल फाईबर का सेल्युलोज आधार होने के कारण इसकी गुणक्षमताएं प्राकृतिक सेल्युलोज के समान होती हैं, न कि रेयन या पॉलिएस्टर जैसे थर्मो प्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक फाईबरों के समान। इसके अतिरिक्त इसमें अभियांत्रिकीकृत विनिर्देशन और समानता का विशिष्ट गुणलाभ होता है। विस्कोस स्टेपल फाईबर में उत्कृष्ट ड्रेप, मुलायम रेशम जैसी सुंदरता होती है और यह सुंदर और चमकीले रंग का होता है। इससे निर्मित किए गए फैब्रिक्स नमी सहने (सूती से भी अधिक), श्वसनीय, पहनने में आरामदायक होते हैं और इन्हें सुगमता से विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। ये स्थाई विद्युत निर्मित नहीं करते हैं और पिल प्रतिरोधी होते हैं।

विस्कोस स्टेपल फाईबर की मुख्य विशेषता उसकी परिवर्तनशीलता तथा किसी भी प्रकार के सभी अन्य प्रकार के वस्त्र फाईबरों में मिश्रित हो जाने की क्षमता रखते हैं, जिससे उसमें चमक, कोमलता, विलयन होने की गुणक्षमता उत्पन्न होती है और जिसके फलस्वरूप ऐसे मिश्रण से फैब्रिक निर्मित करना सुगम होता है। विस्कोस स्टेपल फाईबरों की एक किस्म, बांस के फाईबर को इस जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों से विशेष रूप से यह अनुरोध किया था कि वे बांस फाईबर वर्जित फाईबर के बारे में ही निवेदन करें। इस संबंध में किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है।

12. जांच की कार्यवाई के दौरान पी.टी. साझेथ पेसिफिक विस्कोस (एचपीवी), इंडोनेशिया ने यह तर्क दिया था कि प्राधिकारी को पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती होने और क्षति का विश्लेषण करने के लिए विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) में पृथक करना चाहिए। तथापि, नियर्तक के परिसर पर जा कर मौके पर जांच करने के समय नियर्तक से कहा गया था कि वह पीसीएन-वार विश्लेषण करने के अपने अनुरोध को यथोचित सिद्ध करे। नियर्तक से यह भी कहा गया था कि क्या वह उसके द्वारा विनिर्मित और बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के वीएसएफ के पीसीएन-वार उत्पादन के पृथक ब्यौरे रखता है अथवा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, नियर्तक ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि नियर्तक ऐसे रिकार्ड नहीं रखता है जो कि विभिन्न प्रकार के फाईबरों के उत्पादन की लागत को पृथक कर सके। नियर्तक ने यह भी दावा किया था कि वह ऐसा नहीं मानता है कि विभिन्न प्रकार के फाईबरों के उत्पादन की लागत में कोई विशेष अंतर होता है।

13. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन, कीमत में कटौती होने और क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नियमित (सामान्य) विस्कोस स्टेपल फाईबर की तुलना आयातित फाईबर के साथ की है। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि जांच अवधि के दौरान उसके विलायत संयंत्र में केवल विस्कोस स्टेपल फाईबर का उत्पादन किया गया है। विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थी वीएसएफ अपशिष्ट के आयात पर भी विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

14. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के बारे में किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा कोई ठोस मुद्दा नहीं उठाया गया है और चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा है, इसलिए वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही रहेगा जो कि मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में उत्पाद का कार्य-क्षेत्र था।

D. घरेलू उद्योग और उसका आधार

घरेलू उद्योग के निवेदन

15. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में घरेलू उद्योग के विचार और उत्तर निम्नानुसार हैं:-
- (क) वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग की ओर से भारतीय मानव निर्मित फाईबर उद्योग संघ (एएमएफआईआई) द्वारा दायर की गई थी। उसका एक सदस्य मेसर्ज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है और उसे घरेलू उद्योग के रूप में माना जाए।
- (ख) इस तथ्य से कि याचिकादाता भारत में विचाराधीन उत्पाद का अकेला उत्पादक है, घरेलू उद्योग के रूप में याचिकादाता के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में वीएसएफ का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है और इसलिए याचिकादाता का

उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 100% भाग बनता है। इसके साथ ही भारत से सूती किस्म के बेड लेनिन के आयातों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि पाटन-रोधी करार में प्रयुक्त बहुलवाद में एकल मामला भी शामिल है।

(ग) आवेदक से संबद्ध कंपनियां, चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया के साथ-साथ थाईलैंड में भी अवस्थित हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रही हैं और उनको विश्व भर में बेच रही हैं। इन कंपनियों के उसके साथ संबंध निम्नानुसार हैं:-

1.	ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग है।
2.	विरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	यह एक आदित्य विरला ग्रुप कंपनी है। इसके *** ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, *** थाई रेयन पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड और *** शेयर पी. टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया के पास हैं।
3.	पी. टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया	यह एक आदित्य विरला ग्रुप कंपनी है। इसके *** शेयर ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास हैं।
4.	थाई रेयन पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	यह एक आदित्य विरला ग्रुप कंपनी है और यह थाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसके *** शेयर ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास हैं।

(घ) आवेदक ने अपनी सभी कंपनियों और उनके आधार के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर ये कंपनियां संबंधित कंपनियां हैं। संबद्ध उत्पादक मुख्यतया अपने उत्पादों को संबंधित घरेलू बाजार में बेच रहे हैं अथवा उनके निर्यात तृतीय देशों को कर रहे हैं।

(ङ) चीन में संबद्ध कंपनी ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। इंडोनेशिया की कंपनी ने भी जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है, लेकिन उसने भारत को वीएसएफ अपशिष्ट की कम मात्रा में निर्यात किया है, जो कि तुच्छ मात्र हैं और उन्हें विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने यह सही विचार किया है कि आवेदक को नियमावली के अंतर्गत अयोग्य नहीं माना जाए जैसा कि मूल जांच में भी सिद्ध किया गया था।

(च) घरेलू उद्योग का एक संयंत्र थाईलैंड में स्थापित है, जिसने विचाराधीन उत्पाद के एक एक भाग को जिसे मॉडल फाईबर/माईको मॉडल फाईबर कहा जाता है, भारत में निर्यात किया है। गैर-संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से यह निर्धारित किए जाने से प्रासंगिक नहीं हैं कि क्या घरेलू उद्योग के विदेशी उत्पादक/निर्यातक के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के रूप में वह योग्य पात्र है। सीईएसटीएटी ने विरला एरिक्सन लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में यह निर्णय दिया है कि संबद्ध देशों के परिप्रेक्ष्य में संबंध होने के मुद्दे की जांच की जानी अपेक्षित है। थाईलैंड वर्तमान मामले में संबद्ध देश नहीं हैं, इसलिए नियम 2 (घ) के प्रयोगजार्थ थाईलैंड से आयात प्रासंगिक नहीं हैं। थाईलैंड और यूरोप से आयात की कीमत, चीन और इंडोनेशिया से आयात कीमत से काफी अधिक है।

(छ) घरेलू उद्योग ने तीन कंपनियों नामतः पी. टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया, विरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और थाई रेयन पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न पक्षकारों को किए गए निर्यातों के पूरे ब्यौरे प्रदान किए हैं। विशेषकर पी. टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया और विरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने थाईलैंड को अपने निर्यातों तथा थाईलैंड से भारत को वीएसएफ के निर्यातों के बीजक के ब्यौरों प्रदान किए हैं।

(ज) नियम 2 (घ) में प्रयुक्त किए गए शब्दांश “सकता है” से ऐसा पता चलता है कि संबंधित दो किस्मों के उत्पादक अर्थात् संबंधित उत्पादक और पारित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादक को स्वतः घरेलू उद्योग के भाग के रूप में वर्जित हैं। जांच करने वाले प्राधिकारियों की यह सुसंगत प्रदृष्टि रही है कि वे अलग-अलग मामले के आधार पर ऐसे उत्पादकों को उचित और साम्यक आधार पर तथा उसमें निहित सभी कानूनी और आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद बाहर रखने का निर्णय लेते हैं।

(झ) याचिकादाता का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। इस प्रकार याचिकादाता, वर्तमान याचिका को दायर करने के लिए नियमावली के अंतर्गत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वह “घरेलू उद्योग” बनता है।

(ज) अन्य मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि एसडीएच ट्रांसमिशन के मामले में प्राधिकारी को इस कारण से हुआ बेर्इ को वर्जित करना पड़ा था कि

हुआवेई, चीन ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया था और इस प्रकार वह हुआवेई, भारत से संबंधित कंपनी थी, जिसने घरेलू उद्योग होने का दावा किया था। वर्तमान मामले में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों की संबंधित कंपनियों ने भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। सोडा ऐश के मामले में (क) संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों को ध्यान में रखते हुए टाटा केमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग माना गया था और (ख) जीएचसीएल, निरमा के संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने के बावजूद उन्हें पात्र घरेलू उद्योग माना गया था। इसके अतिरिक्त सोडा ऐश के मामले में संबद्ध देशों से संबंधित पक्षकार द्वारा निर्यात किए गए हैं। वर्तमान मामले में ऐसे देश में संबंधित पक्षकार द्वारा निर्यात किए गए हैं, जो कि जांच अधीन नहीं हैं।

- (ट) एसडीएच ट्रांसमिशन के मामले में प्राधिकारी को इस कारण से हुआवेई को वर्जित करना पड़ा था कि हुआवेई, चीन ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया था और इस प्रकार वह हुआवेई, भारत से संबंधित कंपनी थी। वर्तमान जांच में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियों ने संबंधित कंपनियों को कोई निर्यात नहीं किया है।
- (ठ) विश्व व्यापार संगठन ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद का कोई अकेला उत्पादक है, तो उसे घरेलू उद्योग माना जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने यह निर्णय दिया है कि बहुवचन रूप में शब्द के प्रयोग से उसे एकल रूप में शामिल किए जाने का स्पष्ट पता चलता है।
- (ड) तृतीय देशों में संबंधित पक्षकारों के प्रकटन करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। तृतीय देश के निर्यात न तो पाइत आयात हैं और न ही वे जांच अधीन हैं। थाई से संबंधित पक्षकार द्वारा भारत में लागू पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना करने का कोई प्रयास नहीं है। थाईलैंड से मॉडल फाईबर के आयात किए गए हैं, जिसके लिए उक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास देश में पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं थी।
- (ढ) सोडा ऐश के मामले में (क) संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए निर्यातों को ध्यान में रखते हुए टाटा केमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग माना गया था और (ख) जीएचसीएल, निरमा के संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने के बावजूद उन्हें पात्र घरेलू उद्योग माना गया था। इसके अतिरिक्त सोडा ऐश के मामले में संबद्ध देशों से संबंधित पक्षकार द्वारा निर्यात किए गए हैं। जो कि जांच अधीन नहीं है।
- (ण) घरेलू उद्योग ने एक घरेलू ग्राहक को सामग्री की आपूर्ति की थी जिसने उत्पाद का उत्पादन किया था और तैयार अंत उत्पाद का निर्यात कर दिया था। ऐसे निर्यातों के समस्त निर्यात लाभ का फायदा केवल उसी ग्राहक द्वारा उठाया गया था। इसके साथ घरेलू उद्योग ने ग्राहक को अतिरिक्त लाभ भी दिए थे। यदि घरेलू उद्योग को समग्र घरेलू विक्रियों के लिए इन कीमतों पर समग्र उत्पाद को बेचना होता, तो उसको अत्यधिक वित्तीय घाटे होते। इसलिए घरेलू उद्योग ने ऐसी विक्रियों के लिए विभिन्न कीमतें प्रभारित की थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों द्वारा तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जाए, घरेलू उद्योग ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिससे सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को केवल उसी उत्पादन के लिए विशेष कीमतें प्राप्त हों जो कि निर्यात के निमित्त हैं। ये विक्रियां स्पष्ट रूप से घरेलू विक्रियां हैं, इसलिए किसी भी मामले में इन्हें परिकलनों से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- (त) भारत में लागू पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना करने का न तो कोई प्रयास किया गया था और न ही थाई से संबंधित पक्षकार ने पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना करने के लिए उत्पाद का निर्यात किया था। वास्तव में थाईलैंड से मॉडल फाईबर के आयात किए गए हैं, जिसके लिए घरेलू उद्योग के पास देश में पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं थी।
- (थ) रेयन ने इंडोनेशिया अथवा चीन से भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। यह एक आरोप और निराधार कल्पना मात्र है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

16. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:-

- (क) वर्तमान जांच में मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का घरेलू उद्योग के रूप में कोई आधार नहीं है, क्योंकि वे चीन और इंडोनेशिया दोनों में पी. टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया और बिरला जिंगबेई फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य नामक कंपनियों से संबंधित हैं।
- (ख) एसपीवी ने यह निवेदन किया है कि आवेदक को न केवल उनके स्वामित्वाधीन ढांचे के कारण बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि उनके पारस्परिक संबंधों से भारत में बाजार में उन्हें चालबाजी करने की अनुमति मिली है, अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। यह इस तथ्य से भी सिद्ध हो गया है कि उन्होंने आपस में गोपनीय आंकड़ों की साझेदारी की है। एसपीवी ने आवेदक उद्योग की गोपनीयता के दावे पर भी प्रश्न उठाया है। उनके अनुसार पृथक विशेष पक्षकारों के रूप में गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि संबद्ध देशों में आवेदक उद्योग से संबंधित कंपनियां नामतः पी. टी. इंडो भारत रेयन (आईबीआर), इंडोनेशिया और बिरला जिंगबेई फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(ग) यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक उद्योग का समान प्रतिनिधित्व होने के बावजूद सार्वजनिक मुनवाई के समय के उनके संबंधित निर्यातकों की ओर से कोई निवेदन नहीं किया गया है, जिससे एसपीवी की इस आशंका की संपुष्टि होती है कि वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने और आवेदक की निजी सहायक कंपनियों को पुण्य बाजार प्रदान करने के लिए संपूर्ण आवेदन पत्र चालाकी से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्राथिकारी से अनुरोध किया है कि उन्हें नियम 2 (ख) के अंतर्गत प्राप्त अपने विवेक का प्रयोग करने से पहले आवेदक की वाणिज्यिक कंपनियों की पहचान करनी चाहिए।

(घ) इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देश में विस्कोस फाईबर का अकेला उत्पादक होने के कारण घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

(1) घरेलू उद्योग को बहुवचन में “घरेलू उद्योग” परिभाषित किया गया है, ताकि (पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा से अकेले उत्पादक को वर्जित किया जा सके। घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय घरेलू उत्पादकों के बहुवचन संदर्भ से यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि एकल कंपनी घरेलू उद्योग बनती है। इस एकल कारण मात्र से घरेलू उद्योग से बाहर रखना अथवा प्राथिकारियों द्वारा प्रशासनिक प्रयोजनार्थ उसका वर्जन करना अथवा आंकड़ों की अनुपलब्धता एक स्वीकार्य कारण नहीं है। लेकिन जहां किसी एक ओलिगोपोलिस्टिक उत्पादक को घरेलू उद्योग माना जाता है, तो यह नियम 5 (3) (क) और 5 (3) (ख) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों को अमान्य करना होगा।

(2) याचिकादाताओं द्वारा भारतीय मामलों में उल्लिखित भारतीय विधि शास्त्र का इस मुद्दे पर पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर आगे ईसी-बेड लिनन के मामले के पैरा 6.72 में जिक्र किया गया है जिसमें एक एकल उत्पादक केवल आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अथवा वर्जन से घरेलू उद्योग बन सकता है।

(3) “बहुवचन” में घरेलू उत्पादकों को परिभाषित करने का विधि को प्रयोजन उद्योग को संरक्षण प्रदान करना और एकल उत्पादक को भारत में अनुचित कीमत तंत्र स्वीकृत नहीं करना था।

(ङ) माननीय सीसीआई के (डब्ल्यू पी(सी) वर्ष 2013 की संख्या 4159 दिल्ली (एचसी) के मामले में दिए गए निर्णय से ग्रासीम द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं का शोषण किए जाने के तथ्य की संपुष्टि हो गई है।

(च) इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन ने यह निवेदन किया है कि ग्रासीम को पाटन-रोधी नियमावली के प्रयोजनार्थ पात्र “घरेलू उद्योग” नहीं माना जाना चाहिए जिसके कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) घरेलू उद्योग ने जानबूझ कर थाई रेयन नामक संबंधित निर्यातक के सभी तथ्यों का प्रकटन नहीं किया है, जो कि थाईलैंड में वीएसएफ की अकेली उत्पादक कंपनी है।

(2) थाईलैंड से 100 प्रतिशत निर्यात थाई रेयन द्वारा किए गए हैं (जो कि ग्रासीम से संबंधित विनिर्माता कंपनी है)।

(3) इस संबंधित निर्यातक ने इंडोनेशिया और चीन पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद ही भारत को वस्तुओं के निर्यात किए हैं। थाईलैंड से आयातों की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और यह स्थिर गति से बढ़ते हुए वर्ष 2014-15 में भारत में संबद्ध उत्पाद के कुल आयातों के 11 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

(4) रेयन ने इंडोनेशिया और चीन में संबंधित कंपनियों से सामग्री खरीदी थी और उसी लेखाकरण वर्ष में भारत को फाईबर के निर्यात किए थे।

(5) थाई रेयन से आयातों की मात्रा ग्रासीम के कुल घरेलू विक्रियों का 1.25 प्रतिशत बनती है, जो कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक मानी गई है कि याचिकादाता का यह आरोप है कि (चीन से) 1 प्रतिशत से कम आयात, क्षति का कारण होने के लिए अत्यधिक हैं।

(6) थाई रेयन से आयात ऐसी कीमतों पर किए जाते हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया आस्ट्रिया से समान उत्पादों के आयातों की तुलना में कीमत में कटौती होने तथा पाठन होने का पता चलता है।

(7) इस तथ्य के साथ कि ग्रासीम की संबंधित कंपनी ने भारत को संबद्ध उत्पादों के निर्यात किए हैं और ग्रासीम पर यह आरोप लगाया गया है कि वह भारत में अपने प्रभुत्व से देश के भीतर प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के लिए घरेलू बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर रही है, उसे नियम 2 (ख) के अंतर्गत वर्जित किए जाने की आवश्यकता है।

(8) आईएएस ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के रूप में याचिकादाता की पात्रता का निर्धारण करने के लिए मूल जांच में विनिर्दिष्ट प्राथिकारी द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के खिलाफ याचिकादाता की वर्तमान स्थिति/प्रचालनों की तुलना की जाए। थाई रेयान पर एक समान कार्यकारी निर्दशक (श्री के.के. महेश्वरी) और समान अध्यक्ष का

नियंत्रण है। इसका क्षति अवधि के दौरान भारत में वीएसएफ के कुल आयातों का 11 प्रतिशत अंशदान बनता है, जब कि याचिकादाताओं द्वारा चीन से 0.25 प्रतिशत आयातों के अत्यधिक होने का दावा किया गया है। ग्रासीम ने मौजूदा संयंत्रों में मॉडल वीएसएफ का विनिर्माण करना बंद कर दिया है और उसने केवल थाईरेयन से आयात करना शुरू कर दिया है। इसकी विलायत संयंत्र में ऐसे फाईबर का विनिर्माण करने की परिकल्पना है। ग्रासीम ने थाईरेयन के माध्यम से संबद्ध उत्पाद के आयात किए हैं और इनके प्रचालन का संचालन समान निदेशक और व्यवसायिक अध्यक्ष द्वारा किया गया है। थाईरेयन की भारत में सीआईएएफ निर्यात कीमतें, भारत में मॉडल फाईबर की घरेलू कीमतों से कम हैं।

(छ) कीनिया और 6 अन्य देशों से सोडा ऐश के मामले (संख्या 14/17/2010-डीजीएडी) में घरेलू उत्पादक का इसी प्रकार से वर्जन किया गया है, जिसमें कीनिया से एक घरेलू उत्पादक की संबंधित कंपनी द्वारा 100 प्रतिशत निर्यात किए गए थे, जबकि कुल आयातों में से 8 से 10 प्रतिशत के बीच की सीमा के आयातों को अत्यधिक माना गया था। इसका एक अन्य उदाहरण चीन से कुछ टाईलों के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्णय है।

(ज) एसपीवी ने यह निवेदन किया है कि प्राधिकारी द्वारा यह स्वीकार्य किया गया तथ्य है कि वे निर्णयिक समीक्षा जांच में आवेदक उद्योग के पात्रता की जांच कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने इंडियन कांउसिल ऑफ सिरेमिक्स टाईल्स एंड सेनिटरी बैरेस बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य के डब्ल्यू पी संख्या 4160/2013 के मामले में दिनांक 29.8.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष डीजीएडी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिकारी शपथ पत्र पर विश्वास किया है, जिसमें प्राधिकारी ने निर्णयिक समीक्षा जांच में आवेदक उद्योग के पात्रता की जांच करते की महता पर बल दिया है।

(झ) उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि प्राधिकारी की वर्तमान पद्धति के अनुसार जैसा कि हाल ही की कुछ जांच से पता चला है, प्राधिकारी उन घरेलू उत्पादकों को अस्वीकार कर रहे हैं जो कि आयातकों अथवा निर्यातकों से संबंधित होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चीन जनवादी गणराज्य के खिलाफ सिन्कोनुउस डिजीटल हेयरआर्ची ट्रांसमिशन उपस्कर की जांच पर विश्वास किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने हुआवेर्ड टेलीकम्युनिकेशन (इंडिया) कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (हुआवेर्ड इंडिया) नामक एक घरेलू उत्पादक कंपनी के दावे को केवल इस कारण से खारिज कर दिया था कि वह निर्यातक से संबंधित थी और उसने स्वयं आयात किए थे। इसके अतिरिक्त चीन से विट्रीफाईड टाईलों के संबंध में प्राधिकारी ने उन घरेलू उत्पादकों को भी वर्जित कर दिया है, जिनके संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों अथवा आयाताकों से संबंध थे।

(ज) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एवपीवी का यह निवेदन है कि आवेदक उद्योग को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने का कोई कानूनी या युक्ति संगत कारण नहीं है। तदनुसार उनका यह अनुरोध है कि इस आधार पर इस जांच को समाप्त कर दिया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान याचिकादाता के आधार के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार किया गया है।

18. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख)घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन पत्र भारतीय मानव निर्मित फाईबर उद्योग संघ (एएमएफआईआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसका एक सदस्य, मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तुओं की एक मात्र उत्पादक कंपनी है और उसने याचिका में सभी संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है।

20. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि नियम 2 (ख) के अनुसार मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का घरेलू उद्योग बनने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उससे संबंधित कंपनियां चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड में अवस्थित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र और दायरे से घरेलू उत्पादक को बाहर रखने या शामिल करने का प्रश्न व्यवहारिक महत्ता का है। मूल प्रश्न यह है कि पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार क्या वे घरेलू उद्योग का वास्तविक भाग बनते हैं या नहीं। पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख), प्राधिकारी को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग वे

अलग अलग मामले में ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, जिसमें एक अथवा अधिक उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद के आयात किए होते हैं अथवा वह विचाराधीन उत्पाद के किसी नियांतक या आयातक से संबंधित होता/होते हैं।

21. प्राधिकारी इस संबंध में मूल जांच का स्मरण करते हैं, जिसमें इस मुद्रे पर विस्तार से विचार और निदान किया गया है। घरेलू उद्योग में मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शामिल किया गया है, जिससे संबंधित पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया नामक कंपनी ने इस जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के नियांत भारत को किए हैं। व्यापक जांच करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि इस तथ्य के बावजूद कि मेसर्ज ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का संबद्ध देशों में एक नियांतक से संबंध है, वह घरेलू उद्योग की एक भाग है। उक्त जांच में प्राधिकारी के निर्णय को अब अतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी ने सभी तथ्यों पर गहन विचार किया था और पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया के संबंध में विशेष पूरक पाठन मार्जिन और पाठन शुल्कों का निर्धारण करना उचित समझा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक का नियांतक या आयातक से संबंधित होना मात्र ही ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है।

22. वर्तमान निर्णयक समीक्षा जांच में तथ्य इतने बदल गए हैं कि भारत से इंडोनेशिया में संबंधित नियांतक को विचाराधीन उत्पाद का कोई नियांत नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में कानूनी और संबद्ध अपेक्षा यह है कि क्या जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियों द्वारा नियांत किए गए हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त जांच अवधि से पूर्व संबद्ध देशों में संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए नियांत ऐसे घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखे जाने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक का नियांतक या आयातक से संबंधित होना मात्र ही ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है।

23. इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि असंबद्ध देशों से संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए नियांत वर्तमान जांच से पूर्णतया अप्रासंगिक हैं। सीईएसटीएटी ने विगत में विरला एरिक्सन लिमिटेड बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के मामलों में यह निर्णय दिया है कि याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा आयातक या नियांतक के साथ संबंधित होना (क) जांच अवधि के परिप्रेक्ष्य में और (ख) केवल संबद्ध देशों से आयातों के लिए प्रासंगिक हैं। इस संबंध में असंबद्ध देशों से आयात और जांच अवधि से पूर्व किए गए आयात अप्रासंगिक हैं।

24. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) के संबद्ध भाग में ऐसा प्रावधान निहित है कि जब ऐसे उत्पादक, जो कि आरोपित पाटित वस्तु के नियांतकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा उन्होंने स्वयं आयात किए होते हैं, तो ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में माना जाए। इस प्रकार नियम 2 (ख) से यह स्पष्ट होता है कि “आरोपित पाटित वस्तु” केवल संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद होती है। इसलिए जांच में शामिल नहीं किए गए देशों से आयात और जांच अवधि से पूर्व किए गए आयात अप्रासंगिक हैं।

25. प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया और विरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जो कि भारत में आयातक हैं, ने आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, डीजीसीआईएण्ड एस के आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा की गई जांच जिसमें मौके पर किए गए सत्यापन भी शामिल हैं, के अनुसार जांच अवधि के दौरान पी.टी. इंडो भारत रेयन द्वारा चीन में उसकी संबंधित कंपनी द्वारा विस्कोस फाईबर्स का कोई नियांत नहीं किया गया था। जांच अवधि के दौरान भारत को इंडोनेशिया से वीएसएफ अपशिष्ट के कम मात्रा में नियांत किए गए थे, जो कि कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में नगण्य है। इसके अतिरिक्त वीएसएफ अपशिष्ट, विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रमाणों से यह पता चलता है कि उसके आयात को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पाठन रोधी शुल्क वसूल किए बिना ही क्लीयर कर दिया गया था। इस प्रकार इसे विचाराधीन उत्पादन नहीं माना गया था। इसके अतिरिक्त इन आयातों की मात्रा बहुत कम है।

26. थाई रेयन, थाईलैड द्वारा किए गए नियांतों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में थाईलैड एक संबद्ध देश नहीं है। जहां तक थाई नियांतक के साथ याचिकादाता का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन केवल विवादित संबंधों से ही प्रासंगिक है। तथापि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे पता चलता हो कि थाईलैड से पाटित कीमतों पर नियांत किए गए हैं। याचिका में निहित आयातों की सूचना, और याचिकादाता द्वारा प्रदत्त की गई थाईलैड से नियांत संबंधी सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए डीजीसीआईएण्ड एस के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि अधिकतर यह नियांत मॉडल फाईबर के थे और इनकी कीमत चीन/इंडोनेशिया से आयात की कीमत से बहुत अधिक थी। इस संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि संबंधित कंपनी द्वारा किए गए नियांतों का तथ्य मात्र इस संबंध में पूर्णतः अपर्याप्त है। इस संबंध में प्राधिकारी मूल जांच में किए गए व्यापक निर्धारण का भी हवाला देते हैं, जिसमें प्राधिकारी ने नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र पर संबंधों के प्रभाव की जांच की है।

27. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को निर्णयक समीक्षा जांच के समय घरेलू उद्योग के आधार और कार्य-क्षेत्र पर पुनःविचार करना चाहिए। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा किए गए निवेदनों का हवाला दिया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के आधार और कार्य-

क्षेत्र की जांच नहीं की जाएगी। प्राधिकारी ने वास्तव में आधार संबंधी आवश्यकताओं की जांच की है और यह निर्धारित किया है कि वर्तमान मामले में याचिकादाता, कंपनी घरेलू उद्योग बनती है अथवा नहीं।

28. नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा, प्राधिकारी द्वारा अन्य जांच में तथा वर्तमान मामले में किए गए निर्धारण, सीईएसटीएटी के निर्णयों तथा वर्तमान मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत ग्रासीम इंडस्ट्रीज को अपात्र घरेलू उद्योग माने जाने का कोई आचित्य नहीं है।

29. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि अकेला उत्पादक घरेलू उद्योग नहीं बन सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वहुचन में निर्दिष्ट शब्द से एक से अधिक उत्पादक होने का पता चलता है। प्राधिकारी ने विधि के अंतर्गत नियमित तौर पर अकेले उत्पादक को घरेलू उद्योग माना है। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने विशेष रूप से भारत सरकार से कोटन-टाईप बैड लिलेन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों के मामले में यह निर्णय दिया है कि एक अकेला उत्पादक घरेलू उद्योग बन सकता है।

30. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग से संबंधित थाई रेयन, थाईलैड नामक कंपनी के बारे में सभी तथ्यों को प्रकट नहीं करने का भी मुद्दा उठाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में कानूनी आवश्यकता केवल संबंद्ध देशों में संबंधित पक्षकारों के बारे में प्रकटन करने के संबंध में है। तृतीय देशों में संबंद्ध पक्षकारों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तृतीय देश के आयात न तो पाटित आयात होते हैं और न ही उनकी जांच होती है तथा वे आरोपित पाटित उत्पाद नहीं बनते हैं। यह भी नोट किया गया है कि इस संबंध में घरेलू उद्योग ने सभी संबद्ध सूचना प्रदान की है तथा घरेलू उद्योग ने थाई रेयन, थाईलैड द्वारा न केवल भारत को बल्कि तृतीय देशों को किए गए निर्णयों के भी पूरे ब्यौरे प्रदान किए हैं। इसलिए प्राधिकारी यह नहीं मानते हैं कि याचिकादाता का तथ्यों को छिपाने का कोई इरादा था।

31. केनिया आदि से सोडा-एश के मामले में घरेलू उत्पादक को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी का यह विचार है कि इस मामले के तथ्य वर्तमान जांच से पूर्णतः भिन्न हैं क्योंकि इसमें एक संबंधित घरेलू उत्पादक को अपात्र घरेलू उद्योग माना गया था। सोडा-एश के मामले में (क) जांच अवधि में संबंद्ध देशों से संबंधित पक्षकारों द्वारा निर्यात किए गए थे, (ख) जहां तक टाटा कैमिकल्स का संबंध है, उनकी मात्रा काफी अधिक थी और (ग) जहां तक निरमा और गुजरात हैबी कैमिकल्स का संबंध है, उनकी मात्रा नगण्य थी। प्राधिकारी ने टाटा कैमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योग और निरमा और गुजरात हैबी कैमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग माना था। वर्तमान मामले में संबंधित पक्षकार द्वारा निर्यात किए गए हैं, लेकिन ये निर्यात ऐसे देश से हैं, जो कि जांच अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त निरमा और गुजरात हैबी कैमिकल्स के संबंध में सोडा-एश के मामले में प्राधिकारी का उनको पात्र घरेलू उद्योग माने जाने का निर्णय याचिकादाता के इस तर्क का समर्थन करता है कि ग्रासीम को वर्तमान मामले में अपात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाता सकता है।

32. एसपीवी के इस तर्क के संबंध में कि आवेदक को न केवल उसके स्वामित्व अधीनी ढांचे के कारण ही बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि भारत के बाजार में उसके पारस्परिक संबंध में उसे चालाकी करने का मौका दिया है, अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए, प्राधिकारी का यह मानना है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है। यह तथ्य की इंडोनेशिया की उत्पादक कंपनी और याचिकादाता ने आपस में अपने गोपनीय आंकड़ों में साझेदारी की है, वर्तमान मामले में पूर्णतः अप्रासंगिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में वर्तमान मामले में तथ्य उन्हीं तथ्यों के समान हैं, जो कि मूल जांच के समय विद्यमान थे।

33. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक के प्रयासों का उद्देश्य उसकी निजी सहायक कंपनियों को पुण्य बाजार प्रदान करना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैड, इंडोनेशिया और चीन में संबंधित उत्पादकों द्वारा कोई किए गए निर्यात विशिष्ट प्रमाणों के बिना हैं और वे मात्र परिकल्पना तुल्य हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने कोई पक्षपात किए बिना ऐसा निर्धारण किया है और जहां कहीं भी पाटन के कारण क्षति होना प्रमाणित हुई है, वे वहां सभी स्रोतों पर पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

34. हितबद्ध पक्षकारों ने सीसीआई के निर्णय का हवाला दिया है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीसीआई का ऐसा कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इसके अतिरिक्त हरिदास एक्सपोर्ट्स बनाम ऑल इण्डिया फलोट ग्लास मेनुफैक्चररस [2002(145) ई.एल.टी. 241 (एस.सी.)] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि सीमा-शुल्क अधिनियम में पाटन-रोधी प्रावधानों द्वारा एमआरटीपी कमीशन के विशेष अधिकार को बेदखल नहीं किया है तथा ये दोनों अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं और उनके भिन्न प्रयोजन हैं। हालांकि उक्त निर्णय, एमआरटीपी अधिनियम के परिपेक्ष्य में है, फिर भी यह वर्तमान मामले में मार्गदर्शी नहीं हो सकते हैं। यदि प्रतिस्पृद्धी प्रावधानों में किसी प्रकार का कोई संभावित उल्लंघन हुआ है, तो उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और यह उपयुक्त प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वे उस पर उपयुक्त कार्यवाही करें। विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अधिकार-क्षेत्र यह देखने का है कि क्या उसको घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है और क्या पाटन-रोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने की संभावना है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि सीसीआई द्वारा यह जांच एक आरोप के आधार पर शुरू की गई थी, लेकिन महानिदेशक ने प्रतिस्पृद्ध अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कोई आधार नहीं पाया है।

36. उपरोक्त तथ्य के आलोक में प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता, वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने के आधार की आवश्यकता को पूरा करता है और वह पाटन-रोधी नियमावली की परिभाषा के भीतर 'घरेलू उद्योग' बनता है।

E. गोपनीयता के मुद्दे

घरेलू उद्योग के निवेदन

37. घरेलू उद्योग ने ऐसी समस्त संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है, जो कि प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और निर्धारित की गई है। गोपनीयता के मुद्दे पर कार्यवाही करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की अनदेखी की है। गोपनीयता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों और प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की तुलना करनी चाहिए।

हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

38. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया और बिरला जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन द्वारा किए गए निवेदनों में प्रस्तुत की गई अगोपनीय सूचना को समझने के लिए पर्याप्त व्यौरे प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त व्यौरों में उत्पाद का प्रवाह चार्ट, कारोबार-वार घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातित अवशिष्ट के व्यौरे, तृतीय देशों को निर्यात के व्यौरे, कंपनी द्वारा विचाराधीन बिक्रियां, प्रचलन संबंधी आंकड़े, धमता, उत्पादन, बिक्रियों और भंडार के विवरण, कच्चे माल की खपत के विवरण, कच्चे माल की खपत को दर्शने वाले विवरण, व्यय का आवंटन निर्यात और घरेलू बाजार के लिए उत्पादन की लागत और बिक्री, सामान्य और प्रसाशनीय व्यय को दर्शने वाले विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाये गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निधान निम्नानुसार किया गया है।

(क) सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीयता सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

(ख) गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त की गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्ता के संबंध में की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीयता आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृतांत प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों का गोपनीय वृतांत एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है।

(ग) क्षति के कुछ प्राचलों के अप्रकटन से संबंधित निवेदनों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनकी जांच गोपनीयता के दावे की संबंध में की गई थी और प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। घरेलू उद्योग ने क्षति प्राचलों की सूचीबद्ध सूचना की थी जिसे वास्तविक आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार कुछ सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता है, तो ऐसा हितबद्ध पक्षकार यह समझता है कि ऐसी सूचना गोपनीय व्यवसाय सूचना है, जो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को ऐसी सूचना को प्रकट नहीं करने का निर्देश दे सकता है।

विविध मुद्दे

F. घरेलू उद्योग के निवेदन

40. इस संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैः-

- (क) मूल जांच के समय संबंधित कंपनी और अन्य उत्पादक के मामले में पाटन मार्जिन में अंतर होने के संबंध में यह निवेदन है कि उन कारोबारों में पाटन मार्जिन का होना वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ कोई मायने नहीं रखता है। संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए नियर्तियों की मात्रा इतनी अधिक नहीं थी अथवा ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाए और कंपनी को अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में वर्जित किया जाए। जांच अवधि सहित वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इंडोनेशिया के संबंधित पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है।
- (ख) इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन स्वतः विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं की एक एसोशिएशन होने का दावा नहीं कर सकती है। इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य पोलियस्टर और सूती जैसे अन्य फाइबरों के उपभोक्ता हैं। वे विस्कोस के उपभोक्ता नहीं हैं। वास्तव में इस समग्र परिपेक्ष्य में देश में बीएसएफ की खपत सूती और विस्कोस की खपत से काफी कम है।
- (ग) घरेलू उद्योग निचले स्तर के उद्योग को परिवर्तनीय कीमत दे रहा है जो कि घरेलू उद्योग अथवा नियर्तियों के लिए सामग्री के अंत प्रयोग पर निर्भर करती है। इसलिए विनिर्माता निर्यातकों को कम कीमत पेश की जा रही है ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धा के लाभ को बनाए रख सकें।

हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

41. इस संबंध में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैः-

- (क) घरेलू उद्योग के संबंधित नियर्तिक के लिए पाटन मार्जिन इंडोनेशिया से अन्य सहयोगी नियर्तिक के पाटन मार्जिन से लगभग दोगुना है। भारतीय उत्पादक और इंडोनेशिया में उसकी सहायक कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सांठ-गांठ की है कि अन्य प्रतिस्पर्धियों को पहले अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश किया जाए और उसके बाद भारतीय पक्षकार द्वारा पाटन-रोधी जांच शुरू करवाई जाए जिसका एक मात्र उद्देश्य भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को रोकना है।
- (ख) इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य बीएसएफ के उपभोक्ता होने के साथ-साथ आयातक भी हैं। इसके अतिरिक्त इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन मूल जांच की कार्यवाही में एक पक्षकार थी और चूंकि यह एक निर्णयक समीक्षा जांच है, इसलिए वास्तव में इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन को वर्तमान जांच में एक पक्षकार होना चाहिए।
- (ग) इण्डियन सिपनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी क्षमता बढ़ाई है लेकिन वह विगत चार वर्षों में ग्रासीम की क्षमता से कम है। वह घरेलू रूप से ग्रासीम से अधिप्राप्त बीएसएफ की अधिक कीमतों और भारत में विस्कोस के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के निरंतर लगे रहने के कारण अतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता की कमी का सामना करती है।
- (घ) याचिकादाता विदेशी बाजार में और घरेलू बाजार के लिए भिन्न कीमत की नीति अपना रहा है। वे ऐसे उपभोक्ताओं के बीच भी अंतर बनाए रख रहा है जो कि घरेलू खपत और विनिर्माता नियर्तिकों के लिए विनिर्माता हैं। इससे कारोबार में लगे हुए प्रत्येक पक्षकार को कठिनाई हो रही है। वस्त्रों के सिपनर्स विदेशी बाजार की तुलना में अधिक कीमत पर फाईबर प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार वे प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी ओर विभिन्न कीमतें, भारतीय नियर्तिकों पर पाटनरोधी उपाय लागू कर रही हैं क्योंकि आयातक देशों द्वारा की जा रही जांच से यह सिद्ध होता है कि घरेलू और निर्यात आपूर्तियों के लिए कच्चे माल की दो भिन्न कीमतें हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्रासंगिक पाए गए विशिष्ट निवेदनों का प्राधिकारी द्वारा किया गया निदान निम्नानुसार है :

- (क) मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग के लिए संबंधित नियर्तिक के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन मार्जिन मामले के वास्तविक तथ्यों पर आधारित है यदि किसी पक्षकार के लिए अधिक पाटन मार्जिन पाया गया है तो प्राधिकारी ने तदनुसार पाटन-रोधी शुल्क की अधिक मात्रा की सिफारिश की है (जोकि कमतर शुल्क विधि के लागू होने के अध्यधीन है)। तथापि प्राधिकारी इस तर्क का कोई आधार नहीं पाते हैं कि क्योंकि याचिकादाता इंडोनेशिया के उत्पादक से संबंधित है, इसलिए दोनों ने उत्पाद के पाटन में सांठ-गांठ की है। प्राधिकारी ने मूल जांच में भी किसी मुद्दे पर विचार किया था। वर्तमान जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों में संबंधित नियर्तिकों द्वारा भारत

को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है। मूल जांच के दौरान किए गए निर्यात वर्तमान समीक्षा जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(घ) एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भारतीय स्पिनर एसोसिएशन की अधिकारिता से संबंधित मुद्रे पर प्राधिकारी का यह विचार है कि चूंकि भारतीय स्पिनर एसोसिएशन के अधिकतर उपभोक्ता स्पिनर्स हैं जो कि पोलियस्टर, विस्कोप और सूती फाइबरों का इस्तेमाल करते हैं, प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए इस एसोसिएशन को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वीकार करते हैं।

(ग) कच्चे माल के महंगे होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पिनरों की गैर-प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में भारत सरकार ने निर्यातों के लिए किए जाने वाले आयातों को पाटन-रोधी शुल्क के अधिकार क्षेत्र से छूट दी हुई है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के इस दावे का खण्डन नहीं किया है कि घरेलू उद्योग निर्यात प्रेषणों के निमित सामग्री की तुलना में घरेलू खपत के निमित सामग्री के लिए विभिन्न कीमतें पेश कर रहा है। इससे निर्यात उत्पादन के विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आपूर्तियां की जाती हैं। अन्य देशों में भारतीय निर्यात के खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क की जांच तैयार वस्तुओं के विनिर्माता निर्यातकों द्वारा पाटिट वस्तुओं की एक घटना होती है और यह भिन्न प्रकार की कीमतों के कारण नहीं होती है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक देशों में एक सामान्य प्रक्रिया है।

बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

G. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा और सामान्य मूल्य

43.धारा 9 (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन जनवादी गणराज्य

44. चीन के लिए सामान्य मूल के निर्धारण पर घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार है :

(क) चीन जनवादी गणराज्य को निम्नलिखित कारणों से गैर-बाजार वाला अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए :-

- (1) ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, जिसमें एक प्रमुख शेयर धारक राज्य के स्वामित्वाधिन/नियंत्राधीन एक कंपनी होती है।
- (2) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जबतक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित करने में असमर्थ हों कि उनकी लेखा-बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक को (आईएएस) के सामनरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करने पर बल देने की आवश्यकता से वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए राजस्व और व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करना है।
- (3) बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण को ऐसी स्थितियों में अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए जहां चीन के निर्यातक यह प्रमाणित करने में असमर्थ हों कि उनकी लेखा-बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक को (आईएएस) के सामनरूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करने पर बल देने की आवश्यकता से वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए राजस्व और व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करना है।
- (4) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावाली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक प्राचल के संबंध में जांच परीक्षा पूरी न कर लें। इसके विपरीत एकल प्राचल

आर्थिक क्षति की जांच को ऐसी क्षति को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। अन्य शब्दों में यदि एक प्राचल क्षति के विद्यमान होने को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है तो एक एकल प्राचल की विफलता बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को स्वीकृत करने के लिए पर्याप्त है।

- (5) प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था के परिवेश में प्रचालन कर रही हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण की हकदार हैं। लेकिन चीन के प्रतिवादी निर्यातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालन कर रहे हैं।
- (6) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समग्र समूह उसका दावा नहीं करता है। यदि किसी समूह की एक अथवा अधिक कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं तो उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (7) ऐसी स्थिति में जिसमें की वर्तमान शेरर धारकों ने स्वतः अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की है लेकिन उन्होंने उसे कुछ अन्य पक्षकारों से प्राप्त किया है तो उन्हें तक तब बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि दस्तावेजी प्रमाणों से परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती है।
- (अ) यह निवेदन किया गया है कि ऐसे मामले में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पैरा 8 (2) में उल्लिखित उपबंध को लागू किए बिना केवल पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जा सकता है।
- (ग) इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में तृतीय देश से आयात कीमत, (ख) भारत में बिक्री कीमत और (ग) भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है, जिसके लिए बिक्री, सामान्य और प्रसाशनिक व्यय और लाभ सहित उचित समायोजन किया जाए। यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया 'किसी भी अन्य आधार' पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह तभी लागू करना आवश्यक होगा जबकि विधि के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य आधार लागू नहीं किया जा सकता हो।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए एमईटी के दावे की जांच

45. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निर्दान पाटन-रोधी नियमावली के नियम 9 का (1) (ग) के अनुसार किया गया है।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के परिणामस्वरूप चीन से निर्यातकों ने जिनके नाम इस प्रकार है – तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, तांगशान सानयू यायूंडा फाईबर कंपनी लिमिटेड और भारत जिंगबेई फाईबर्स कंपनी लिमिटेड ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन पक्षकारों ने निर्णयिक समीक्षा के लिए निर्धारित प्रश्नावलियों में निर्धारित तरीके और रूप से सूचना प्रस्तुत की है। चीन के प्रतिवादी निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा नहीं किया है और इस लिए उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।

47. चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पर विचार नहीं कर सकते हैं कि क्या अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दर्जा स्वीकृत किया जाए।

48. पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (1) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(2) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बटे-बातों, वस्तु विनियम-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

(3) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(4) विनियम दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू गुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया गया है कि वहतांगशान सानयू गुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड नामक अपनी संबंधित कंपनी द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की एक निर्यातिक कंपनी है। कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातिक द्वारा अपनी प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की है और तांगशान सानयू गुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड के लिए विशिष्ट प्रथक मार्जिन निर्धारित किया है, जोकि नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू गुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक है और उसने तांगशान सानयू गुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड नामक अपनी संबंधित कंपनी के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू याऊनडा फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने यह दावा किया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक है। इस कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात करने का दावा नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि तांगशान सानयू याऊनडा फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य के लिए कोई विशिष्ट पृथक पाठन मार्जिन निर्धारित करने का कोई मामला नहीं है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की एक संबंधित कंपनी भारत जिंगबेई फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें उसने यह दावा किया है कि इस कंपनी ने जांच अवधि अथवा उससे पहले या उसके बाद किसी भी अवधि में भारत कोई निर्यात नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि भारत जिंगबेई फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीनी जनवादी गणराज्य के लिए कोई विशिष्ट पृथक पाठन मार्जिन निर्धारित करने का कोई मामला नहीं है।

53. विश्वभर में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है और हाल ही के मामलों में भारत में भी चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। इस चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाठन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है वशर्टों की चीन में कोई उत्पादक, अनुबंध-1 के पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण के अपने दावे को प्रमाणित न कर दे। सुलभ संदर्भ के लिए पैरा 7 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदर्भ अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

54. चूंकि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जा रहा है, इसलिए नियमावली में ऐसा प्रावधान है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में घरेलू बिक्री कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश को तृतीय देश की नियात कीमतों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को

शामिल करने के लिए उचित समायोजन करके समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत सहित किसी भी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

55. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन जनवादी गणराज्य से किसी निर्यातिक/उत्पादक ने बजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी निर्यातिकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान प्रयोजन के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश को एक उपयुक्त तृतीय देश के रूप में माने जाने का सुझाव नहीं दिया है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोई सूचना अथवा प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए उचित समायोजन करके उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत सहित किसी भी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातिक अथवा अन्य असहयोगी निर्यातिक द्वारा चीन से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्यों का निर्धारण किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

नाम	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/कि.ग्रा.
तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फार्मासिटी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड (व्यापारी)	***
सभी अन्य निर्यातिक/उत्पादक	***

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

इंडोनेशिया के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, इंडोनेशिया में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया गया है।

पी.टी. पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी)

56. पी.टी. पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी) ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा विनिर्मित और बेची गई संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्रियों के साथ-साथ निर्यात विक्रियों के ब्यौरे निहित हैं। सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए परिशिष्ट-1 में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्रियों को ध्यान रखा गया है। प्रतिवादी पक्षकार ने परिशिष्ट-5 से 9 में उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया था कि एसपीवी द्वारा दिए गए इस आश्य के विवरण में कि वह भारत में अंत प्रयोक्ताओं और व्यापारियों को सीधे निर्यात करती है, के संबंध में दिए गए उत्तर में कुछ असंगितयां हैं। तथापि, जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि एसपीवी भारत में संबद्ध वस्तुओं का विपणन नहीं कर रही है, बल्कि उसकी मूल कंपनी लेंजिंग एजी का भारत में विपणन कार्यालय है जो कि विपणन और विक्री पश्चात् सेवा प्रदान करने का कार्य करती है और उसने भारत में एसपीवी के प्रत्येक कारोबार पर कमीशन अदा किया है। इसी प्रकार एसपीवी ने यह घोषणा की थी कि कंपनी ने अपनी संबद्ध कंपनियों से कच्चे माल की कोई खरीददारी नहीं की थी, लेकिन अन्य निवेदन से यह स्पष्ट हो गया है कि उसने बुड़ पल्प की समस्त खरीददारी, पल्प ट्रेडिंग जीएमबीएच नामक अपनी संबद्ध कंपनी से की है। मूल्य और मामले के तथ्य के रूप में यह बहुत जटिल है और परिचर्चा के दौरान इसके बारे में निर्यातिक को अवगत करा दिया गया है। ऐसी कमी होने के लिए निर्यातिक की ओर से उसके कानूनी सलाहकार ने क्षमा याचना की है। कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में विक्रियों के संबंध में यह बताया गया था कि असंबद्ध पक्षकारों को ***संबद्ध वस्तुओं की विक्री की गई है। यह सत्यापित किया गया था कि *** घरेलू विक्रियां लाभप्रद विक्रियां हैं और उन्हें सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थी ध्यान रखा गया है। प्राधिकारी द्वारा भाडे के व्यय और क्रेडिट व्यय का समायोजन करने की अनुमति दी गई है, जिनका दावा किया गया है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा कारखाना-गत स्तर पर तय किया गया सामान्य मूल्य निम्नानुसार है:-

नाम	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/कि.ग्रा.
पी.टी.साऊथ पेसिफिक विस्कोस	***

पी.टी. इंडिया भारत रेयन

57. इंडोनेशिया से पी.टी. इंडिया भारत रेयन ने निर्धारित रूप में और तरीके से उत्तर दिया है और सूचना प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने परिशिष्ट-1 में घरेलू विक्री से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने परिशिष्ट-5 से 9 में उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी को अपनी घरेलू विक्रियों पर समग्र आधार पर बाटे हुए हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है। मूल दस्तावेजों से इन तथ्यों को विश्वित सत्यापित कर लिया गया है। इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि पी.टी. इंडिया भारत रेयन, इंडोनेशिया के लिए कोई विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करने का कोई मामला नहीं है।

इंडोनेशिया से सभी अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में इंडोनेशिया से किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से सहयोगी निर्यातक के लिए निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य को सभी अन्य निर्यातकों के लिए भी अपनाया है।

निर्यात कीमत

संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

चीन जनवादी गणराज्य

चीन जनवादी गणराज्य

59. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने जांच अवधि के दौरान अपनी संबंधित कंपनी, तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को किए हैं। निर्यातक तथा संबंधित उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, कमीशन, पत्तन व्यय, वैट अंतर (केवल चीन जनवादी गणराज्य के लिए) और मात्रात्मक छूट के लिए कीमत में समायोजन किया गया है। स्वीकार्य समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जो कि नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

60. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक होने के साथ-साथ जांच अवधि के दौरान निर्यातक कंपनी भी है। निर्यातक तथा संबंधित उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, कमीशन, पत्तन व्यय, वैट अंतर (केवल चीन जनवादी गणराज्य के लिए) और मात्रात्मक छूट के लिए कीमत में समायोजन किया गया है। स्वीकार्य समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जो कि नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

तांगशान सानयू यांडा फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

61. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि तांगशान सानयू यांडा फाईबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का कोई भी निर्यात नहीं किया है।

भारत जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य

62. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत जिंगबेर्इ फाईबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने जांच अवधि अथवा उससे पूर्व अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने उनके लिए कोई निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है।

इंडोनेशिया

पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया

63. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक होने के साथ-साथ निर्यातक भी है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, कमीशन, पत्तन व्यय और मात्रात्मक छूट के लिए कीमत में समायोजन किया गया है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान स्वीकार्य समायोजन करने के बाद भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जो कि नीचे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया

65. निर्यातक की प्रश्नावली में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए थे। इसलिए प्राधिकारी ने उसके लिए कोई निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है।

संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों-निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

65. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार संबद्ध देशों से असहयोगी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है। तदनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में स्वीकार्य समायोजन करने के बाद भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जो कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

66. विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

पाटन मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक	समान्य मूल्य अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	सीमा
इंडोनेशिया					
पीटी साऊथ पेसीफिक विस्कोस	***	***	***	***	1-10
सभी अन्य निर्यातक/उत्पादक	***	***	***	***	40-50
चीन जनवादी गणराज्य					
तांगशान सानयू ग्रुप किंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड (व्यापारी)	***	***	***	***	20-30
अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	***	***	***	***	30-40

67. इंडोनेशिया और चीन से पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

H. क्षति का भूल्यांकन और कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के निवेदन

68. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने पूर्ण रूपेण तथा भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में वृद्धि दर्शाई है। जहां तक चीन का संबंध है, पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के कारण उनमें गिरावट आई है।
- (ख) इंडोनेशिया और चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक ह्रास होने का प्रभाव पड़ रहा है।
- (घ) घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ने उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा के रूप में सुधार दर्शाया है। तथापि, घरेलू उद्योग मांग और आयातों में वृद्धि होने के समानुपात अपनी बिक्रियों में वृद्धि करने में असमर्थ है।
- (ङ) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में भी अत्यधिक गिरावट आई है।
- (च) घरेलू उद्योग की मालसूचियों में लगभग उसी मात्रा में वृद्धि हुई है, जितनी संबद्ध देशों के आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में भी गिरावट आई है। वास्तव में यदि मूल जांच की क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से की तुलना, वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से से करें, तो यह पता लगेगा कि घरेलू उद्योग ने अपने बाजार के हिस्से की क्षति, मूल जांच के समय घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से की क्षति से अधिक है। अन्य शब्दों में घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा, मूल मामले में जांच अवधि के दौरान विद्यमान बाजार के हिस्से से काफी कम है, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति और गहन होगी।
- (छ) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद इंडोनेशिया के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसका एक मात्र कारण इंडोनेशिया में उत्पादक द्वारा पाटन को अत्यधिक गहन करना है। यदि थाईलैंड के बाजार के हिस्से को घरेलू उद्योग के बाजार के

हिस्से में जोड़ दिया जाता है, तो आंकड़ों से ऐसा पता चलेगा कि घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है और इंडोनेशिया के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(ज) मात्रा के प्राचलों के कारण क्षति होने का कोई दावा नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह आदि में गिरावट आने के कारण क्षति का दावा किया है।

(झ) थाईलैंड से आयातों की तुलना इंडोनेशिया के आयातों से करने से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि इंडोनेशिया के आयातों की तुलना में थाईलैंड से आयात बहुत कम हैं। घरेलू उद्योग थाईलैंड से मॉडल फाईबर की आपूर्ति कर रहा है क्योंकि उसके पास भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार और गुणवत्ता युक्त मॉडल फाईबर नहीं हैं। घरेलू उद्योग की मॉडल फाईबर की कुल मांग 3,700 मी.टन है, जबकि घरेलू उद्योग की नागड़ा में *** मी.टन की क्षमता है। इसलिए वीएसएफ के लिए नया संयंत्र स्थापित स्थापित करते समय घरेलू उद्योग ने मॉडल फाईबर बनाने की उत्पादन सुविधाएं भी स्थापित की हैं जो कि *** मी.टन का उत्पादन कर सकती हैं। विलायत में उसके संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के पूरी तरह से चालू होने तक कंपनी ने थाईलैंड से मॉडल फाईबर की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त चीन अथवा इंडोनेशिया में स्थापित याचिकादाताओं की संबंधित कंपनियां मॉडल फाईबर का उत्पादन नहीं करती हैं। मॉडल फाईबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है।

(ज) रोजगार और बेतन के कारण क्षति का कोई दावा नहीं किया गया है।

(ट) घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में ऐसा घटिया उत्पाद नहीं बेचा है, लेकिन उसने ऐसे उत्पाद को निर्यात बाजार में बेचा है।

(ठ) 40 वर्ष पुराने संयंत्र पर 10% का प्रतिलाभ अत्यधिक नहीं है।

(झ) घरेलू उद्योग ने संबंधित पक्षकारों के अत्यधिक विक्रियां नहीं की हैं।

(झ) थाईलैंड के मामले में कीमत में कटौती अधिक नकारात्मक नहीं है।

(ण) सूती, पोलिएस्टर और वीएसएफ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद नहीं हैं। वे बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर वैकल्पिक उत्पाद हैं। प्राथिकारी उत्पाद की वीएसएफ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य क्षमता से चिंतित हैं और न कि उपभोक्ताओं की रूचियों से।

(त) वास्तव में घरेलू उद्योग के लिए यह तर्क देना खण्डनक है कि (क) याचिकादाता कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है और (ख) वह घरेलू बाजार में आपूर्तियों पर नियंत्रण रख रहा है (जहां उसे अधिक कीमतें प्राप्त होती हैं)। यदि घरेलू बाजार में कीमतें बेहतर हैं और यदि घरेलू बाजार में मांग अधिक है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि याचिकादाता को घरेलू बाजार में आपूर्तियां क्यों प्रतिबंधित करेगा और निर्यात बाजार में कम कीमत पर निर्यात करेगा।

(थ) घरेलू उद्योग ने पाठन के प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने का दावा किया है और निवेदन किया है कि यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो याचिकादाता के लिए उत्पादन और विक्रियां बनाए रखना कठिन होगा, जिसके उसकी क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(द) हितवद्ध पक्षकारों की यह परिकल्पना मात्र है कि याचिकादाता ने क्षति के रूप में उत्पादन में कटौती होने का दावा किया है। जांच अवधि में अन्य कारकों के कारण याचिकादाता के उत्पादन को कोई क्षति नहीं हुई है।

(झ) विनिमय दर में वृद्धि होने के कारण इनपुट कीमतों में वृद्धि ऐसी श्रेणी में आती है जिसमें घरेलू उद्योग विगत में हुई वृद्धि के कारण अपनी कीमतों में वृद्धि करेगा। किसी भी स्थिति में रूपए में अवमूल्यन इस कारण से घरेलू उद्योग को प्रतिकूल से प्रभावित नहीं करता कि उसने अपनी कीमतों का निर्धारण, आयात की कीमत से जोड़ा होता है जिसका वह अनुसरण करता है। वास्तव में यह घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की अपेक्षा सहायता करता। इसके अलावा पल्प की लागत उत्पादन की कुल लागत का केवल 50-52% भाग बनती है और इसलिए जब घरेलू उद्योग पर उसका प्रतिकूल प्रभाव, उसके उत्पादन की लागत के 28% की हद तक पड़ता, तो वह उसके उत्पादन की लागत में 14% तक सहायक होता।

(न) जब कि पल्प की कीमत में अमरीकी डालर में गिरावट आती, इसलिए ऐसी कीमत ने आईएनआर को अधित प्रभावित नहीं किया है। चूंकि घरेलू उद्योग आईएनआर में लागतों का वहन करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत में पल्प की कीमत में गिरावट ने घरेलू उद्योग को समानुपात रूप से सहायता दी है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग की विक्री कीमत आईएनआर से जुड़ी हुई है, आईएनआर के अवमूल्यन की प्रतिपूर्ति कच्चे माल पर पड़े प्रभाव से हो जाती है।

(फ) घरेलू उद्योग ने विलायत और नागड़ा में अनुकूलतम उत्पादन को ध्यान में रख कर परिकल्पन किया है और इसके कारण लाभ पर नगण्य प्रभाव पड़ा है। नागड़ा का संयंत्र पहले से ही 97% क्षमता का प्रचालन कर रहा है।

(ब) प्राधिकारी द्वारा उत्पादन की लागत पर 5% लाभ देने पर विचार किया गया है जो कि निर्यातकों से असहयोग किए जाने की स्थिति में उचित लाभ है। अन्यथा अनुबंध-1 में उल्लिखित लाभ को उत्पादन की लागत में जोड़ा जाए।

(भ) पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ की समाप्ति होगी। उपभोक्ताओं को अभी भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक स्रोत प्राप्त होंगे। प्राधिकारी ने बार-बार ऐसा माना है कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पद्ध का बातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग अधिक कार्यक्षम नहीं बनेगा। वास्तव में इससे घरेलू उद्योग का क्षति होगी। वीएसएफ और फैब्रिक के निर्यातों के संबंध में यह पूर्णतया भिन्न मामला है और यह पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने के साथ कटई भी नहीं जुड़ा है। पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से किसी भी तरीके से यार्न या फैब्रिक के निर्यात प्रभावित नहीं होंगे। इसके विपरीत पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति का अनुपालन करने में और सहायता मिलेगी।

(म) भारत में उत्पादन की लागत की तुलना इंडोनेशिया में उत्पादकन की लागत के साथ करने से ऐसा पता चलता है कि भारतीय उद्योग वास्तव में कुशल है। इसलिए घरेलू उद्योग पर अकुशलताओं और प्रतिस्पद्ध दशाओं में आंतरिक कारणों से क्षति होने के लगाए गए सभी आरोपों का ढूढ़ता से खंडन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य मात्र कि घरेलू उद्योग कम कीमत पर निर्यात कर रहा है, वर्तमान क्षति विश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। चूंकि याचिकादाता ने निर्यात-निष्पादन को पृथक किया है, सूचित कार्य-निष्पादन केवल घरेलू कार्य-निष्पादन से संबंधित है और इसलिए यह निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

69. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) मॉडल और टेसेल फाईबर को भी आयात आकड़ों में शामिल किया गया है, जिनका आयात इंडोनेशिया और चीन से नहीं किया जाता है। ये मुख्यतया थाईलैंड और यूरोपीय यूनियन से आते हैं। थाईलैंड में स्थित याचिकादाता की संबंधित कंपनी से ये बल्कि में आते हैं। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में उपयुक्त समायोजन करने के बाद वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसने मॉडल फाईबर के बाजार को थाईलैंड में स्थित अपनी संबंधित कंपनियों को अंतरित कर दिया है और यदि उसको घरेलू उद्योग के हिस्से के साथ जोड़ा जाता है, तो भारतीय बाजार के अत्यधिक भाग पर उसका नियंत्रण होगा। घरेलू उद्योग ने जानवृक्ष कर इस तथ्य को प्राधिकारी से लिप्तिया है।

(ख) क्षति अवधि के दौरान स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए इन प्राचलों पर किसी प्रकार की क्षति होने का ह दावा नहीं किया जा सकता है।

(ग) विचाराधीन उत्पाद की मांग में 83,977 मी.टन तक की वृद्धि हुई है, जिसमें से 63,197 मी.टन अर्थात् 80% घरेलू उद्योग ने ले लिया है और बाकी 20% में संबद्ध देशों ओर अन्य देशों की सांझेदारी है, जिनमें थाईलैंड में स्थित उनकी संबंधित कंपनियों और विश्व भर में उनकी संबंधित कंपनियों से मॉडल फाईबर के आयात शामिल हैं। यदि थाईलैंड से मॉडल फाईबर के आयातों को मांग में से घटा दिया जाता है, तब भी बढ़ी हुई मांग में घरेलू उद्योग का अत्यधिक हिस्सा होगा। इससे उसको कोई क्षति होने का पता नहीं चलता है।

(घ) घरेलू उद्योग ने रोजगार और वेतन के कारण से क्षति होने का दावा इसलिए नहीं किया है क्योंकि इन कारकों में सुधार हुआ है।

(ङ) घरेलू कीमतों में गिरावट आने के प्रभाव का विश्लेषण करते समय घरेलू उद्योग ने अपने विलायत संयंत्र में उत्पादन के स्थिर होने के कारण घटिया उत्पाद की बिक्रियों के प्रभाव की अनदेखी की है, जिससे निश्चय रूप से कम बिक्री वसूली हुई है। ऐसी वसूली के लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(च) प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए जो कि विश्व भर में वीएसएफ उद्योग 10%(जीएएफए) से 15%(एनएफए) तक प्राप्त कर रहा है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है और इस कारण से क्षति होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक कि 40 वर्ष पुरानी मशीनों से भी घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है, उनसे प्राप्त होने वाला लगभग 10% प्रतिलाभ, अत्यधिक है। साथ ही घरेलू उद्योग की बेवसाईट पर उपलब्ध वित्तीय प्रस्तुतीकरण अनुसार जांच अवधि और जांच पश्चात् अवधि (वित्तीय वर्ष 2015-16 के पहले 6 महीनों) में उसकी सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन का पता चलता है।

(छ) याचिकादाता पर्याप्त मात्रा में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्तियां अपनी संबंधित कंपनियों को करता है।

(ज) घरेलू उद्योग ने बेशी क्षमताओं और इंडोनेशिया से निर्यातिक के निर्यातोन्मुख होने के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने लागू पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की क्षति में घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति और पाटन होने और उनकी पुनरावृति होने की संभावना को प्रमाणित करने के लिए कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।

(झ) आस्ट्रेलिया से समान उत्पादों के आयातों की कीमत की तुलना में थाई रेयन से जिन कीमतों पर आयात किए जाते हैं, उनसे प्रथम दृष्टया कीमत में कटौती और पाटन होने का पता चलता है।

(ञ) भारत में मॉडल फाईबर की घरेलू कीमतों के साथ थाई रेयन की आयात कीमतों (सीआईएफ) की तुलना करने से कीमत में कटौती और पाटन होने का पता चलता है।

(ट) विक्री वसूली में कमी होने के पीछे कारकों में वीएसएफ की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, सूती फाईबर की कीमत और ऑफ ग्रेड सामग्री शामिल हैं। संबद्ध देशों से आरोपित पाटित आयातों के कारण होने वाली कीमत कटौती को गैर-जिम्मेदार कारकों से समायोजित किया जाना चाहिए।

(ठ) ग्रासीम ने अपने प्रभुत्व का प्रयोग करके घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए विलायत में अपने संयंत्र में अपनी उत्पादन क्षमता में 70,030 मी.टन (34.31%) तक की वृद्धि की है। घरेलू उद्योग के गलत व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए निर्यातिकों को दोषी नहीं माना जा सकता है।

(ड) वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक घरेलू उद्योग का औसत क्षमता उपयोग 94% से 96% तक रहा है, जिससे अच्छी मांग और उपयोग की स्वस्थ स्थिति का पता चलता है।

(ढ) जांच अवधि के दौरान कम उत्पादन होने का कारण आंतरिक (पानी की कमी)/गैर-जिम्मेदार कारकों से संयंत्रों का बंद हो जाना है।

(ण) निम्नोक्त कारणों से उत्पादनकी लागत में वृद्धि हुई है:-

- (1) कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।
- (2) विलायत संयंत्र के विस्तार के स्थिरीकरण के कारण नियत लागतों में वृद्धि।
- (3) नागडा यूनिट में कम उत्पादन पर नियत लागत का भार।

(त) जैसा कि याचिका में सामान्य मूल्य के परिकलन का दावा किया गया है, ग्रासीम ने विगत 5 वर्ष की अवधि के दौरान अत्यधिक सामान्य लाभ अर्जित किया है जब कि उसकी तुलना में घरेलू उद्योग का सामान्य लाभ 5% रहा है।

(थ) ग्रासीम ने मॉडल वीएसएफ फाईबर का विनिर्माण करना बंद कर दिया था और उसने केवल थाई रेयन से आयात करना शुरू कर दिया था। उसने अत्यधिक लाभप्रद उत्पादों के अपने बाजार के हिस्से को थाईलैंड में स्थित अपनी संबंधित कंपनियों को अंतरित कर दिया था। बाजार के हिस्से में कमी के लिए ग्रासीम स्वयं उत्तरदायी है और क्षति का मूल्यांकन करने के लिए यह एक गैर-जिम्मेदार कारक है।

(द) शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग अधिक कुशल बन जाएगा और सीधे प्रतिस्पर्द्धा होने के फलस्वरूप कीमत प्रतिस्पर्द्धा हो जाएगी। इससे भारत में विनिर्मित विस्कोस यार्ट और फैब्रिक के निर्यात बढ़ेंगे और साथ ही भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति का भी संवर्धन होगा।

(ध) पाटन-रोधी शुल्क लागू करना, घरेलू उद्योग की अक्षमताओं और ऐसे आंतरिक कारकों को आवरण में छिपाना है, जिनके कारण प्रतिस्पर्द्धा आर्थिक दशाओं में उसका घाटे हो रहे हैं।

(न) याचिकादाता यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे निर्यात बाजार की क्षति नहीं हो, भिन्न कीमत नीति अपना रहा है। इसका घरेलू बाजार में उसके कार्य-निष्पादन से कोई सरोकार नहीं है, जो कि विधि की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग आरोपित पाटन के अंतर्गत क्षति का आश्रय नहीं ले सकता है, जब कि कथित क्षति का कारण उसकी निजी कीमत नीतियां हो सकती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि याचिकादाता की क्षति और पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(फ) घरेलू उद्योग की क्षति का तब कोई प्रश्न नहीं उठता है, जब संबद्ध देशों से आयात की कीमतों की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं कम कीमत पर निर्यात करता है। आवेदन पत्र में ऐसा कोई सार्थक प्रमाण नहीं जिससे ऐसा पता चल सके कि याचिकादाता की क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के पाटन/संबद्ध देशों से आयातों के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध है।

(ब) घरेलू उद्योग की कीमत संबंधी नीति के अनुसार माने गए आयातों पर उनकी आपूर्तियों के लिए छूट दी जाती है। माने गए निर्यातों के लिए उनकी आपूर्तियों के लिए प्रभारित कीमत, घरेलू विक्रियों के लिए प्रभारित की गई कीमत से कम है। ऐसा घरेलू

उद्योग की कीमत सूची से देखा जा सकता है। कीमत संबंधी कार्यनीति और घरेलू उद्योग की नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः निर्यातों के लिए ग्राहकों को की गई कुछ विक्रियों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू विक्रियों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति, घरेलू उद्योग की अपनी निजी कीमत संबंधी नीति के कारण स्वयं पहुंचाई गई है।

(भ) आवेदन पत्र में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के पाटन/संबद्ध देशों से आयातों के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध है।

(म) अंतर्राष्ट्रीय सीएफआर कीमतों की तुलना में भारत में ग्रासीम द्वारा प्रभारित प्रीमियम 16% और 22% (ग्रासीम के वर्ष 2011-2015 के कार्पोरेट के प्रस्तुतीकरण के अनुसार) के बीच है। ऐसा देखा गया है कि ग्रासीम यार्न की घरेलू विक्रियों में खपत किए गए फाईबर के लिए (सीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार) अत्यधिक कीमतें वसूल कर रहा है, जिसमें गैर-ग्रासीम उत्पादकों से आयातों पर प्रभारित पाटन-रोधी शुल्क की राशि शामिल है।

(य) घरेलू बाजार में वीएसएफ की कीमतें, शेष विश्व में ग्रासीम द्वारा बेची गई निर्यात कीमतों से अधिक हैं। (घरेलू कीमतें कम से कम 8% अधिक हैं।)

(र) विक्री वसूली में गिरावट आने के 3 प्रमुख कारक हैं जिनके कारण विक्री कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है। ये कारक इस प्रकार हैं:-

- (1) अंतर्राष्ट्रीय वीएसएफ कीमतें।
- (2) सूती फाईबर और पीएसएफ की कीमतें।
- (3) ऑफ-ग्रेड सामग्री की अत्यधिक विक्रियां।

(ल) ग्रासीम के उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा अंतरिक रूप से इन कारकों के बारे में सूचित किया गया है और ग्रासीम के वीएसएफ व्यवसाय का मूल्यांकन करने के लिए इस पर जनता द्वारा विश्वास किया गया है। ग्रासीम द्वारा विगत 4 वर्ष अर्थात् 2011 से 2015 तक की अवधि के लिए प्रकाशित निवेशक का प्रस्तुतीकरण, इन कारणों का स्रोत है।

(व) इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबद्ध देशों से वीएसएफ के आयातों के कारण गिरावट के प्रभाव पर विचार करने के लिए वीएसएफ की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू कीमतों में हुई गिरावट (वर्ष 2014 में सूचीबद्ध गिरावट 12.9%, आधार वर्ष 2011) के भाग को निकाल देना चाहिए।

(श) जब कि इंडोनेशिया और चीन से आयातों में गिरावट आई है अथवा स्थिर बने हुए हैं, पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने के बाद कुल आयातों में थाईलैंड से ग्रासीम की संबंधित कंपनी द्वारा किए गए आयातों में 0% से 11% तक की वृद्धि हुई है।

(ष) चीन से आयात 1% से कम हैं (जो कि कुल आयातों का 0.25%), फिर भी याचिकादाताओं द्वारा उन्हें अत्यधिक माना जा रहा है।

(स) घरेलू उद्योग ने अपने बाजार के हिस्से को थाईलैंड में स्थित अपनी संबंधित कंपनी को अंतरित कर दिए हैं और इसलिए विगत 5 वर्ष में उसके बाजार का हिस्सा 40% तक बढ़ गया है।

(ह) घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि उनकी घरेलू मांग में 79,030 मी.टन की पर्याप्त (34.31% की वृद्धि) वृद्धि हुई है।

(क) वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का औसत क्षमता उपयोग 94% से 96% तक हुआ है।

(ख) निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 20% बनते हैं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयोजन निर्यात बढ़ाना था।

(ग) उत्पादन में गिरावट आने का कारण आंतरिक/गैर-जिम्मेदार कारक थे, जो निम्नानुसार हैं:-

- 2011-12 - पानी की कमी होने के कारण नागडा संयंत्र का बंद हो जाना।
- 2012-13 - पानी की कमी होने के कारण हरीहर संयंत्र और खराह संयंत्र का बंद हो जाना।
- 2012-13 - सुदूरीकरण के कारण नागडा संयंत्र का बंद हो जाना।
- 2013-14 - नागडा संयंत्र के उत्पादन में (पानी की कमी होने के कारण) गिरावट आना।

(घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त कारणों से उत्पादन के बंद हो जाने के कारण क्षति की मात्रा को पृथक करना चाहिए, जो कि इंडोनेशिया और चीन से आरोपित पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

(डड) जैसा कि ग्रासीम द्वारा निवेशक के प्रस्तुतीकरण और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटन किया गया है, लाभप्रदता में गिरावट आने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

- कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि रूपए का अवमूल्यन होने के कारण हुई है (कॉस्टिक सोडा की कीमत में 32% तक की वृद्धि हुई और पल्प की लागत 11% तब बढ़ गई आदि)।
- विलायत संयंत्र के विस्तार के स्थिरीकरण के कारण नियत लागत में वृद्धि।
- ब्याज दरों में परिवर्तन होने के कारण कर्मचारियों के लाभ में वृद्धि।
- नागडा यूनिट में कम उत्पादन होने से नियत लागत का भार।
- वीएसएफ के प्रति टन उत्पादन पर ऊर्जा खपत में 3% तक की वृद्धि।

(चच) याचिकादाता कंपनी के जांच अवधि पश्चात् के परिणामों से विशिष्ट लाभ, बिक्री की बढ़ी हुई मात्रा और औसत से अधिक लाभांश की घोषणा का पता चलता है। जांच अवधि पश्चात् याचिकादाता के वीएसएफ व्यवसाय के लाभ में 27% तक की वृद्धि हुई है (जो कि 2608 आईएनआर से बढ़ कर 3331 करोड़ आईएनआर हो गया)। ईंवाइआईटीडीए 146% तक बढ़ गया (जो कि 233 करोड़ आईएनआर से 575 आईएनआर हो गया)। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की संख्या से पहले ही स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। लाभप्रदता में किसी भी प्रकार की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के कारण आई है, जहां घरेलू उद्योग भारतीय उपभोक्ताओं से प्रीमियम प्रभारित कर सकता था और अत्यधिक सामान्य लाभ अर्जित कर सकता था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

70. प्राधिकारी द्वारा किए गए निम्नोक्त क्षति विश्लेषण से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का स्वयमेव निदान हो गया। तथापि, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट निवेदनों का निदान इस प्रकार किया है:-

(क) थाईलैंड से अयातों के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड से निर्यात मॉडल/माइक्रो मॉडल फाईबर के हैं और ये ऐसी कीमत पर किए गए हैं, जो कि चीन और इंडोनेशिया से आयात कीमत से काफी अधिक है। चीन और इंडोनेशिया से इस प्रकार के फाईबर का कोई आयात नहीं होता है। यह नोट किया गया है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 की तुलना में जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(घ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड से कुल आयात इंडोनेशिया से आयातों काफी कम थे। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वह थाईलैंड से मॉडल फाईबर से आयात कर रहा है और उसकी पूर्ति कर रहा है क्योंकि उसके पास भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता युक्त मॉडल फाईबर की पर्याप्त मात्रा नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने विलायत में अपने संयंत्र में मॉडल फाईबर बनाने की नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित की है। जब तक विलायत में स्थापित संयंत्र में पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हो जाता है तब तक कंपनी ने थाईलैंड से मॉडल फाईबर की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा चीन में उसके संबंधित उत्पादकों द्वारा मॉडल फाईबर का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। केवल थाईलैंड में उसके संबंधित उत्पादक द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है।

(ग) क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग, रोजगार और वेतन के प्राचलों पर क्षति नहीं होने से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इन प्राचलों के कारण क्षति होने का कोई दावा नहीं किया है और न ही नियमावली के अंतर्गत प्रत्येक प्राचल के अंतर्गत क्षति होना कोई आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह आदि में गिरावट आने के कारण क्षति होने का दावा किया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा जांच है जिसमें प्राधिकारी को इसकी जांच करनी आवश्यक होती है कि क्या पाठन-रोधी शुल्क को समाप्त कर देने के फलस्वरूप पाठन होगा और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी।

(घ) घटिया उत्पाद की बिक्रियों से संबंधित निवेदन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसने घरेलू बाजार में कोई घटिया उत्पाद नहीं बेचा है। इंडोनेशिया से वीएसएफ अपशिष्ट के कुछ निर्यात किए गए हैं जो कि कम कीमतों पर हैं, तथापि यह मद की भिन्न श्रेणी है और विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा भी वीएसएफ अपशिष्ट का निर्यात किया जा रहा है। कुछ विशिष्ट प्रयोक्ताओं द्वारा इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है।

(ड) निवेश पर प्रतिलाभ से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निवेश पर प्रतिलाभ पर संयंत्र की अवस्था के साथ विचार किया जाना चाहिए और प्रतिलाभ की उच्चतर दर की मांग की है ताकि घरेलू उद्योग नए निवेश पर उचित प्रतिलाभ प्राप्त कर सके, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निवेश पर अर्जित किया गया प्रतिलाभ अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विधि के अंतर्गत उन्हें यह जांच करने की

आवश्यकता है कि क्या निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोई सुधार आया है अथवा गिरावट आई है। यदि निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट आई है तो यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के बारंबार तर्क देने के बावजूद प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली में निर्धारित और निदेशालय में स्थापित पद्धति के अनुसार नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करते हुए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है।

- (च) अपनी संबंधित कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में अपने संबंधित पक्षकारों को अत्यधिक विक्रियां नहीं की हैं। न ही हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई विशिष्ट व्यौरा अथवा प्रमाण प्रस्तुत किया है।
- (छ) थाईलैंड से आयातों के कारण संभावित कीमत कटौती होने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड से आयातों के मामले में कीमत में कटौती अत्यधिक नकारात्मक है। फिर भी थाईलैंड से आयात अधिकतर मॉडल फाईबर के हैं।
- (ज) अन्य किस्म के फाईबर (सूती और पोलिएस्टर) के कारण विक्री वसूली में गिरावट आने से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न किस्मों के बच्चे फाईबरों में पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा होने की यह कोई नई घटना नहीं है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के मामले में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है और मांग ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है। इसलिए संबद्ध वस्तुओं के लिए उपलब्ध बाजार में अन्य बच्चे फाईबरों से प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण गिरावट नहीं आई थी। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विस्कोस, सूती और पोलिएस्टर के उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं हैं।
- (झ) घरेलू उद्योग द्वारा अपने अस्तित्व का दुरुपयोग करने से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से ऐसा पता चला है कि इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है, संबद्ध देशों से आयातों के मामले में कीमत में कटौती सकारात्मक है, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह जैसे प्राचलों के संबंध में गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अपने अस्तित्व का दुरुपयोग करने के संभावित मुद्दे पर प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर होने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है और क्या वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि उद्योग को पाटन और क्षति के निरंतर रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना का निदान किया जा सके।
- (ज) क्षमता उपयोग के संबंध में क्षति नहीं होने से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि पाटन के कारण उसे अनप्रयुक्त क्षमताओं से तुकसान हो रहा है, बल्कि उसने पाटन के प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने का दावा किया है।
- (ट) क्षति अवधि के दौरान उत्पादन घटने से संबंधित अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति के रूप में उत्पादन कम होने का कोई दावा नहीं किया है।
- (ठ) उत्पादन की लागत पर रूपए के अवमूल्यन के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूपए के अवमूल्यन से इस कारण से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह आयात कीमत के संबंध में अपनी कीमत निर्धारित करता है और इसलिए रूपए के अवमूल्यन से घरेलू उद्योग बाजार में बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। चूंकि घरेलू उद्योग लागत का बहन आईएनआर में करता है, पल्प की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने से घरेलू उद्योग को समानुपात स्तर पर कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग की विक्री की कीमत आईएनआर से जुड़ी है, आईएनआर में अवमूल्यन की प्रतिपूर्ति, कच्चे माल के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से हो गई है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने नागडा संयंत्र में अनुकूलतम उत्पादन को ध्यान में रख कर परिकलन किया है और जांच अवधि के दौरान विलायत संयंत्र में मॉडल फाईबर का कोई उत्पादन नहीं हुआ है। इसलिए इस कारणवश लाभ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (ड) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ग्रासीम अत्यधिक सामान्य लाभ अर्जित कर रही है। तथापि, जांच से ऐसा पता चला है कि ग्रासीम द्वारा अर्जित किया गया लाभ नियोजित पूँजी पर 12% प्रतिलाभ बनता है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास अत्यधिक क्षमताएं विद्यमान हैं, जिनका प्रयोग बहुत पहले किया गया था और अब इन निवेश का निवल तय मूल्य बहुत कम है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पुराने और नए निवेश में प्रति यूनिट निवल अचल परिसम्पत्तियों में अत्यधिक अंतर व्याप्त होने का पता चलता है। फिर भी प्राधिकारी ने निदेशालय में सामान्य प्रचलित पद्धति के अनुसार नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करते हुए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है।

(द) घरेलू उद्योग द्वारा अपने बाजार के हिस्से को थाईलैंड में अपनी संबंधित कंपनियों को अंतरित करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता कंपनी ने विलायत में नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और यदि कंपनी को अपनी आपूर्तियां थाईलैंड में अंतरित करनी होती तो उसने भारत में इतने बड़े वाणिज्यिक स्तर पर भारत में अत्यधिक निवेश नहीं किया होता।

(ए) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से प्रयोक्ता उद्योग अधिक कार्यक्षम बनेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन पाटन की अनुचित पद्धति को समाप्त करना है ताकि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को कुछ हद तक दूर किया जा सके। पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। बल्कि इसके विपरीत पाटन-रोधी उपायों से प्राप्ति पद्धतियों से प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट बंद होगी तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक पसंद के उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटन-रोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेंगे। वीएसएफ और फैब्रिक के निर्यातों के संबंध में ये पूर्णतया विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं तथा ये किसी भी तरह से पाटन-रोधी शुल्क को बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़े नहीं हैं। पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से किसी भी तरीके से यार्न और फैब्रिक के निर्यात प्रभावित नहीं होंगे।

(ट) घरेलू उद्योग की अकुशलताओं के संबंध में किए गए निवेदनों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि भारतीय उद्योग, अन्य देशों के उद्योगों की तुलना में अक्षम है।

(थ) घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत के निर्यातों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात निष्पादन को पृथक कर दिया है। घरेलू उद्योग ने अपने निर्यातों और घरेलू विक्रियों के पृथक्कीरण की सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास् अत्यधिक वेशी क्षमताएं होने के कारण वे तृतीय देशों में भी पाटन कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में यह तथ्य मात्र की घरेलू उद्योग कम कीमत पर निर्यात कर रहा है, घरेलू उद्योग को पाटन विधि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं करता है। प्राधिकारी को निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट आने के कारण हुई क्षति को पृथक करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने केवल घरेलू उद्योग की घरेलू विक्रियों पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू प्रचालनों के लिए लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है तथा मौजूदा विश्लेषण करने के लिए केवल ऐसी पृथक की गई सूचना पर ही विचार किया गया है।

(द). निचले स्तर के उद्योग में माने गए निर्यातिक को घरेलू उद्योग द्वारा दी गई छूटों के संबंध में प्रतिवादी पक्षकारों के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे विनिर्माता को सामग्री की आपूर्ति की थी, जिसने निर्यातों के लिए निचले स्तर के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उसे प्रयक्त किया था और सभी सहयोजित निर्यात के लाभों का उपयोग केवल विनिर्माता निर्यातिक ने कर लिया था। इसके साथ ही घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए हैं। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि ऐसी विक्रियां स्पष्ट रूप से घरेलू विक्रियां हैं।

71. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिसने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

72. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से ऐसा पता चलता है कि वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी इसका निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

73. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह प्रावधान है कि - (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

74. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संवधित घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

75. उपरोक्त नियमावली के अनुबंध (4) के अनुसार भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल विक्री वूसली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।

मांग का मूल्यांकन

76. मांग का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने विभिन्न स्रोतों से भारतीय उत्पादकों की विक्रियों और आयातों पर विचार किया है। भारत में उत्पाद की मांग का परिकलन, भारतीय उत्पादकों की विक्रियों और विभिन्न देशों से ज्ञात आयातों के योगफल के रूप में किया गया है। इस प्रकार से मूल्यांकित मांग नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी.टन	215,820	230,450	240,968	279,017
संबद्ध देश	मी.टन	16,261	8,126	11,308	15,129
अन्य देश	मी.टन	4,615	6,539	6,253	11,291
मांग/खपत	मी.टन	2,36,696	2,45,115	2,58,529	3,05,437

77. यह नोट किया जाता है कि समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही देश में उत्पाद की मांग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से देश में उत्पाद की खपत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

पाठित आयातों के मूल्य प्रभाव

आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
आयात की मात्रा					
चीन	मी.टन	220	46	-	22
इंडोनेशिया	मी.टन	16,042	8,080	11,308	15,107
संबद्ध देश	मी.टन	16,261	8,126	11,308	15,129
अन्य देश	मी.टन	4,615	6,539	6,253	11,291
कुल	मी.टन	20,877	14,665	17,560	26,420

संबद्ध देशों के संबंध में आयात

कुल आयात	%	77.89%	55.41%	64.39%	57.26%
कुल मांग	%	6.87%	3.32%	4.37%	4.95%
भारतीय उत्पादन	%	5.06%	2.41%	3.13%	3.71%

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में सूचित की गई संबद्ध देशों से आयात की मात्रा, आईबीआईएस के आधार पर है, जो कि अब डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित आयातों की मात्रा से कम है। घरेलू उद्योग ने आईबीआईएस का एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2011-12 के लिए आईबीआईएस द्वारा संकलित और प्रदान किए गए आंकड़े, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के समनुरूप नहीं हैं, क्योंकि उन्हें टूटीकोरिन बंदरगाहों से पर्याप्त मात्रा में किए गए कारोबार के आंकड़ों के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में गिरावट आई है लेकिन बाद में उनमें पूर्णरूपेण निरंतर वृद्धि होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है वर्ष 2013-14 में चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में शून्य स्तरों तक गिरावट आई है, लेकिन वर्तमान जांच अवधि में उनमें उछाल आया है।

कीमत प्रभाव

80. कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में आरोपित पाठित आयात कीमत में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों के अन्यथा प्रभाव पड़ने से अत्यधिक सीमा तक कीमतों में ह्रास हो रहा है अथवा उनसे कीमतों में वृद्धि होना रुक रहा है जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो सकती थी। कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत का न्यूनीकरण यदि कोई हुआ है, को ध्यान में रख कर घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है।

कीमत में कटौती

81. यह तय करने के लिए कि क्या आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली से की है। घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत, पाठित आयातों की पहुंच कीमत और कीमत में कटौती को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

कीमत में कटौती	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
इंडोनेशिया					
निबल बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	135.29	123.20	117.57	114.05
कीमत में कटौती	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	(0-10)	0-10	0-10	0-10
चीन जनवादी गणराज्य					
निबल बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	-	***
पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	111.50	149.79	-	88.01
कीमत में कटौती	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	-	***
कीमत में कटौती	%	10-20	(10-20)	-	20-30

82. यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया और चीन जनवादी गणराज्य दोनों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके फलस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

83. घरेलू कीमतों पर पाठित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना, उत्पादन की लागत और आयातों की पहुंच कीमत से की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	111
बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	92	89
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.	135.29	123.2	117.57	114.05
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	87	84

परिवर्तन (विगत वर्ष की तुलना में)	रूपए/कि.ग्रा.				
बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा.		***	***	***
बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा.		***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.		***	***	***
परिवर्तन (आधार वर्ष की तुलना में)	रूपए/कि.ग्रा.				
बिक्रियोंकी लागत	रूपए/कि.ग्रा.		***	***	***
बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा		***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/कि.ग्रा.		***	***	***

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हो रही है, जब कि समस्त क्षति अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास और न्यूनीकरण कर रहे हैं।

I. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्राचल

85. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता होती है, जिनमें ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का समान रूप से मूल्यांकन करना निहित है, जो कि घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिनमें बिक्रियों, लाभ, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ और क्षमता उपयोग में स्वभाविक और संभावित गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूचियां, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूँजीगत निवेश जुटाने की क्षमता के कारक शामिल हैं। तदनुसार घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक प्राचलों का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

86. बिक्रियों, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
क्षमता	मी.टन	333,975	352,225	377,775	436,065
उत्पादन	मी.टन	321,085	337,492	361,012	408,332
क्षमता उपयोग	%	96.14%	95.82%	95.56%	93.64%
बिक्रियों की मात्रा	मी.टन	215,820	230,450	240,968	279,017

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने हाल ही में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने विलायत में नई उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करने में अत्यधिक निवेश किया है, जो कि वर्ष 2015 से शुरू हो गई है। जैसा कि याचिकादाता घरेलू उद्योग ने दावा किया है, मांग में निरंतर वृद्धि होने को ध्यान में रख कर उसने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

88. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे उसकी क्षमताओं में वृद्धि होने के स्वाभाविक परिणाम का पता चलता है। क्षति अवधि के दौरान उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यह भी नोट किया गया है कि चूंकि क्षमताओं में निरंतर वृद्धि हुई है, क्षमता उपयोग में गिरावट आने का कारण नई क्षमताओं में संवर्धन हो सकता है। घरेलू उद्योग ने क्षमता उपयोग में गिरावट आने के कारण उसको हुई क्षति का दावा नहीं किया है।

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मांग सूचियां बढ़ गई हैं, जिससे पता चलता है कि यदि नियर्यातकों ने अपनी कीमतों में और कमी नहीं की होती और पाटन-रोधी शुल्क को समायोजित नहीं किया होता, तो घरेलू उद्योग ने अधिक बिक्री की होती।

बाजार का हिस्सा

90. घरेलू बिक्रियों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाठित आयातों के प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	91.18%	94.02%	93.21%	91.35%
इंडोनेशिया	%	6.78%	3.30%	4.37%	4.94%
चीन	%	0.09%	0.02%	0.00%	0.01%
संबद्धदेशों का योग	%	6.87%	3.32%	4.37%	4.95%
अन्य देश	%	1.95%	2.67%	2.42%	3.70%
कुल	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि वर्ष 2012-13 में इंडोनेशिया के बाजार के हिस्से में गिरावट आई थी और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई थी, लेकिन उसके बाद घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है और इंडोनेशिया के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 तक चीन के बाजार के हिस्से में गिरावट आई थी और जांच अवधि में उसमें उछाल आ गया है।

लागत, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

92. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रूपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	111
बिक्री कीमत	रूपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	92	89
लाभ/हानि	रूपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	38	20
ब्याज पूर्वलाभ	रूपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	47	29
नकदी लाभ	रूपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	45	30
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	सीमा	60-70	30-40	20-30	10-20

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में निरंतर गिरावट आ रही है और समग्र क्षति अवधि में अत्यधिक गिरावट आई है। जब कि समग्र क्षति अवधि में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है और बिक्री कीमतों में गिरावट आई है। आयातों के कारण कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक गिरावट आई है।

94. लाभ में गिरावट आने की प्रवृत्ति, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में भी देखी गई है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किए जाने वाले नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में भी समस्त क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

95. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि चूंकि उसके मूल निवेश में पूरी तरह से मूल्य ह्रास हुआ है, इसलिए एक आधार के रूप में उसकी निवल अचल परिसम्पत्तियों को ध्यान में रख कर उसके लिए निर्धारित किया गया नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ अनुचित और भ्रामक है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी निवेदन किया है कि यदि जांच अवधि के दौरान उसके द्वारा अर्जित किए गए लाभ पर विचार किया जाता, तो घरेलू उद्योग विलायत में किए गए नए निवेश पर 45 वर्षों के अंदर लाभ कमा लेता। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर प्रतिलाभ और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एनआईपी का निर्धारण करने के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाए। यह मानते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अत्यधिक निवेश नितांत पुराना है और ऐसे निवेश के संबंध में घरेलू उद्योग की निवल अचल परिसम्पत्तियां अब काफी कम हैं, जिसके फलस्वरूप निवेश के आंकड़ों पर उच्च प्रतिलाभ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे क्षति प्राचलों की प्रवृत्तियों से चिंतित हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी की ऐसी सुसंगत पद्धति रही है कि वे इन निवेशों की अवधि की ओर ध्यान दिए बिना निवेश पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करते हैं।

मालसूचियां

96. संबद्ध वस्तुओं की माल सूचियों से संबंधित आंकडे नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
अंत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	190	163	238

97. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूचियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि देश में पाटन की अनुपस्थिति में उसके पास ऐसी बढ़ी हुई मांग सूचियां नहीं होतीं।

रोजगार, उत्पादकता और वेतन

98. रोजगार और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:-

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	114
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	111	142
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	115	112
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.टन/दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	112	127

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ समय से घरेलू उद्योग ने अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है और उनको वेतन का भुगतान किया है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग में क्षमताओं में संवर्धन होने से रोजगार बढ़ा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता बढ़ने और क्षमता के संबंध में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई है।

पाटन की मात्रा

100. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन त्यूनतम सीमा से ज्यादा और विशेष रूप से अत्यधिक है, जैसा कि ऊपर तालिका में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन के संबंध में देखा जा सकता है। मूल जांच करने के समय निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन भी अत्यधिक था।

संवृद्धि

101. उत्पादन, क्षमता और विक्रियों की मात्रा जैसे प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक थी। तथापि, मालसूचियों, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी लाभ और बाजार के हिस्से आदि के संबंध में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक थी।

क्रमांक	प्राचल	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
1.	क्षमता		5%	7%	15%
2.	उत्पादन		5%	7%	13%
3.	घरेलू विक्रियों की मात्रा		7%	5%	16%
4.	विक्रियों की लागत		3%	5%	2%
5.	विक्री कीमत		-5%	-4%	-3%
6.	लाभ/हानि		-31%	-45%	-46%
7.	आरओआई		-27%	-13%	-13%
8.	नकदी लाभ		-28%	-38%	-33%

क्षति पर निष्कर्ष

102. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वर्ष 2012-13 में पूर्णतया वृद्धि दर्शाई है, लेकिन जहां तक चीन से आयातों का संबंध है, उनमें गिरावट आई है। आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिसके कारण बाजार में विचाराधीन उत्पाद के कीमतों में ह्रास और उनका न्यूनीकरण हो रहा है। निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में माल सूचियों, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह जैसे अर्थिक प्राचलों के रूप में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। जांच अवधि में आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत से कम है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से पुनः क्षति हुई है। ऐसी परिस्थिति में पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और उसके फलस्वरूप कीमत के अत्यधिक न्यूनीकरण होने की संभावना है।

क्षति की मात्रा पर क्षति मार्जिन

103. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रख कर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अत्यधिक निवेश का पहले से ही अवमूल्यन हो गया है, निवेश पर प्रतिलाभ स्वीकृत करना चाहिए और इसलिए प्राधिकारी को इन निवेशों के बाजार मूल्य पर विचार करने के बाद निवेश पर प्रतिलाभ अथवा उच्चतर दर पर प्रतिलाभ स्वीकृत करना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने निवेश पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करने की अपनी सुसंगत पद्धति का अनुसरण किया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की गई है। इस प्रकार से तय की गई क्षति रहित कीमत निम्नानुसार है:-

	इंडोनेशिया		चीन जनवादी गणराज्य	
	पी.टी. साऊथ पेसिफिक	अन्य	तांगशान सानयू ग्रुप निंसडा केमिकल फाईबर कंपनी लिमिटेड और तांगशान सानयू ग्रुप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	अन्य
एनआईपी (अमरीकी डालर/कि.ग्रा.)	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***	***	***
क्षति मार्जिनकी सीमा (%)	***	***	***	***

J. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना

घरेलू उद्योग के निवेदन

104. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) वर्तमान मामले में भी पाटन की संभावना से संबद्ध कारक क्षति की संभावना के प्रासंगिक हैं।
- (ख) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में आयात किए गए हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर पाटित संबद्ध वस्तुओं के व्यापक आयात होने की अत्यधिक संभावना है।
- (ग) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं स्थापित हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर भारत में निर्यात गहन होंगे।
- (घ) संबद्ध देश से निर्यातिक तृतीय देशों को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कर रहे हैं।
- (ङ) वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- (च) प्रचलित पाटन-रोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक है।
- (छ) आयात कीमतें वास्तव में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर उपभोक्ता पाटित उत्पाद की ओर प्रवृत होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।

(ज) पाटित आयातों की अत्यधिक मात्रा घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत से कम है और इसलिए इससे बाजार में कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण होने की संभावना है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी विक्री कीमत को विक्रियों की लागत से भी और कम करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप उसे घोर कीमत क्षति होगी।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

105. संभावना के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात् किए गए निवेदनों का निपटान बाद में पैराओं में उपयुक्त रूप से कर दिया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होने की संभावना है।

107. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने जांच अवधि से आगे की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से अतिरिक्त मंगाई थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी निर्यातकों ने संभावित विश्लेषण के बारे में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से सूचना प्रस्तुत की है। चूंकि यह निर्णायिक समीक्षा है, इसलिए जांच अवधि के बाद के और तृतीय देश के निर्यातों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इंडोनेशिया के संबंध में संभावित विश्लेषण करने के लिए इंडोनेशिया से प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए तृतीय देश को किए गए नियांत के आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।

(1) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन

108. मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का स्तर सकारात्मक है। घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के निरंतर निर्यात हो रहे हैं। समीक्षा अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

(2) जांच अवधि में आयातों की मात्रा

109. यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा अत्यधिक है और इसने वर्ष 2012-13 से ले कर जांच अवधि तक और जांच अवधि के बाद भी निरंतर वृद्धि दर्शाई है। क्षति अवधि के दौरान और क्षति अवधि के बाद आयातों की वर्तमान मात्रा और उसकी कीमतों से यह सिद्ध होता है कि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क के बावजूद पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अभी भी हो रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और निरंतर पाटन हो रहा है तथा वर्ष 2012-13 से उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है, इन प्राचलों से स्वभावतः यह सिद्ध होता है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

जांच अवधि पश्चात् विश्लेषण (अप्रैल-सितंबर, 2015)

110. जांच अवधि पश्चात् भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के आंकड़े, याचिकादाता और सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए थे, जिनका विश्लेषण आयातों की प्रवृत्ति को देखने के लिए किया गया है।

भारत में अन्यदेशों के आयातों की मात्रा

निर्यातक देश	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि पश्चात् (अप्रैल-सितंबर, 2015)	जांच अवधि पश्चात् वार्षिकीकृत
चीन	46	-	22	1,172 मी.टन	2,344 मी.टन
इंडोनेशिया	8080	11,308	15,107	7,935 मी.टन	15,870 मी.टन

111. पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। चीन से आयातों में अत्यधिक उछाल हुआ है। पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर पाटित आयात और गहन होंगे। जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया और चीन से आयातों ने सकारात्मक पाटन और क्षति दर्शाई है। वास्तव में चीन के संबंध में यह बहुत अधिक है।

112. जांच अवधि पश्चात् अर्थात् अप्रैल 2015 – सितंबर, 2015 के दौरान इंडोनेशिया से संभावित पाटन तथा क्षति का और विश्लेषण किया गया था।

इंडोनेशिया से भारत को निर्यात– पाटन मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	निर्यातक कीमत अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	अमरीकी डालर/कि.ग्रा. %	सीमा
पीटी साऊथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	***	5-15
पीटी इंडो भारत रेयन	कोई निर्यात नहीं				

113. चूंकि जांच अवधि में और जांच अवधि पश्चात् औसत विक्री कीमत कुल मिला कर समान बनी रही है, इसलिए प्राथिकारी जांच अवधि के लिए विस्तार से तय की गई उत्पादन की लागत को जांच पश्चात् अवधि और तृतीय देशों के निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य के रूप में 5% लाभ सहित अपनाना उपयुक्त समझते हैं, जिसकी बाद में तुलना भारत और अन्य देशों में निर्यातों की कीमत से की गई है।

1. तृतीय देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन

114. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के तृतीय देशों को किए गए निर्यात भी पाटित कीमतों पर हैं। जब कि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया और चीन से तृतीय देशों को किए गए निर्यातों के आधार पर तृतीय देशों में हो रहे पाटन को सिद्ध कर दिया है, विनिर्दिष्ट प्राथिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर से भी पता चलता है कि तृतीय देशों को किए गए निर्यात पाटित कीमतों पर हैं।

इंडोनेशिया – जांच अवधि और जांच अवधि पश्चात् तृतीय देशों को निर्यातों का विश्लेषण

जांच अवधि में पाटन मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	निर्यात कीमत डालर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिनडालर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	सीमा
पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस	1.73	1.62	0.11	6.8	0-10
पी.टी. इंडो भारत रेयन	1.84	1.57	0.26	16.81	15-25

जांच अवधि पश्चात् पाटन मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	निर्यात कीमत डालर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन डालर/कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	सीमा
पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस	1.73	1.62	0.11	6.8	0-10
पी.टी. इंडो भारत रेयन	1.84	1.57	0.26	16.81	15-25

115. तृतीय देशों के निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, जांच अवधि के लिए विस्तार से तय की गई उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है, जिसके साथ जांच पश्चात् अवधि और तृतीय देशों के निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य के रूप में 5% लाभ जोड़ गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस और पी.टी. इंडो भारत रेयन के उत्पादन की लागत में बहुत अंतर है, हालांकि वे एक ही स्थान पर अवस्थित हैं और समान प्रोद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं। उनकी अधिप्राप्ति और उत्पादन की प्रक्रियाएं भी समान हैं। वास्तव में इन दोनों कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार जांच अवधि के दौरान उनको घाटे हुए हैं।

116. घरेलू उद्योग द्वारा प्रसूत की गई विसृत सूचना की प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान और जांच अवधि पश्चात् भारत में भारित औसत आयत कीमत के लिए जांच की गई थी, जो कि निम्नानुसार है:-

निर्यातक देश	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि पश्चात् (अप्रैल - सितंबर, 2015)
मात्रा				
चीन (मी.टन)	46	-	22	1,172
इंडोनेशिया (मी.टन)	8080	11,308	15,107	7,935
	औसत कीमत (अमरीकी डालर/कि.ग्रा.)			
चीन	2.58	-	1.34	1.73
इंडोनेशिया	2.11	1.86	1.81	1.74

117. यह देखा गया है कि अप्रैल - सितंबर, 2015 की जांच अवधि पश्चात् अवधि में भारत में निर्यातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जब कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि पश्चात् अवधि के दौरान भारत में औसत आयत कीमत में गिरावट आई है।

118. प्राधिकारी ने जांच अवधि और जांच पश्चात् अवधि के दौरान इंडोनेशिया से भारत और तृतीय देशों को निर्यात की भी जांच की है। इसके अतिरिक्त तृतीय देशों के निर्यातों की भी संचयी रूप से जांच की गई है। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से तृतीय देश को निर्यातों के पेटर्न की विशिष्ट पृथक कारोबार में जांच की है तथा तृतीय देशों के निर्यातों की मात्रा का पृथक्कीरण सामान्य मूल्य से नीचे और सामान्य मूल्य से अधिक दो श्रेणियों में किया है।

क्रमांक	विवरण	इंडोनेशिया से निर्यात	
		जांच अवधि (मी.टन)	जांच अवधि पश्चात् (मी.टन)
1	तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा	भारत से अधिक पाटन मार्जिन मात्रा वाले निर्यात	63,717
2	भारत से कम पाटन मार्जिन मात्रा वाले निर्यात	147,207	19,209
3	कुल	210,924	79,344

119. विशिष्ट पृथक निर्यात कारोबार के विश्लेषण से पता चलता है कि तृतीय देशों के संबंध में पाटन मार्जिन, भारत पाटन मार्जिन से अधिक है, जो कि जांच अवधि के दौरान 63,717 मी.टन मात्रा में था। जांच पश्चात् अवधि के दौरान तृतीय देशों को निर्यातों की मात्रा 60,135 मी.टन थी।

2. उत्पादकों की अतिरेक क्षमताएं और निर्यातोन्मुखीकरण

120. सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सूचना और सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना से स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। यह भी नोट किया जाता है कि ये उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार संबद्ध देशों से उत्पादक अपने कुल उत्पादन के 26-47 प्रतिशत से भी अधिक सीमा में निर्यात करते हैं। इंडोनेशिया और चीन में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात-आयतके आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

इंडोनेशिया

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक का नाम	स्थापित क्षमता (मी.टन)	निर्यात	निर्यातों का अंशदान
			(मी.टन)	
1	पीटी साइथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	47%
2	पीटी इंडो भारत रेयन	***	***	26%
3	अन्य	-	-	-
4	कुल	520,000	202,159	39%

121. इंडोनेशिया में निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है और वे अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं। इंडोनेशिया में अत्यधिक बेशी होने को ध्यान में रखते हुए यदि पाटन-रोधी शुल्क की वर्तमान मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो उससे स्पष्ट पता चलेगा कि भारत से कम कीमत पर तृतीय देशों को किए जाने वाले निर्यात, भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित हो जायेंगे। इस प्रकार यदि पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा को उसके वर्तमान स्तर से घटा कर नए स्तर पर कर दिया जाता है, तो उसके फलस्वरूप भारत में निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।

चीन

क्रमांक	उत्पादक/निर्यातक का नाम	स्थापित क्षमता (मी.टन)	निर्यात (मी.टन)
1	फुलिदा	4,80,000	24,423
2	तांगशान सान्हू ग्रुप	5,00,000	200,000
3	आयोयांग	2,70,000	ज्ञात नहीं
4	यामेई	2,60,000	ज्ञात नहीं
5	सतेरी	3,70,000	48,902
6	यिबिन ग्रेस	2,00,000	ज्ञात नहीं
7	लेंजिंग	1,78,000	32,067
8	अन्य	12,18,000	58,163
9	कुल क्षमता	3,476,000	363,555

122. चीन के मामले में इस देश में अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं विद्यमान हैं। भारत की कुल मांग 3,00,000 मी.टन की सीमा में है, जो कि चीन में स्थापित कुल क्षमता का 10% है। पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन के निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार बहुत आकर्षक हो जायेंगे और ऐसी पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात अत्यधिक गहन हो जायेंगे।

3. अन्य देशों द्वारा व्यापारिक रक्षा कार्रवाई

123. यह नोट किया जाता है कि ब्राजील की सरकार ने चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और एशिया से विस्कोस स्टेप्ल फाईबर (वीएसएफ) के आयातों पर पहले से ही पाटन-रोधी शुल्क लगाए हुए हैं।

4. भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

124. जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे हैं, वे उस कीमत से काफी कम हैं, जिन पर संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में बेची जाती हैं। ऐसे आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही हैं। पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उपभोक्ता घरेलू उत्पादकों से सस्ते आयातित उत्पाद प्राप्त करने लगेंगे और संबद्ध देशों से उत्पादक और आक्रामक तरीके से भारतीय बाजार को अपना लक्ष्य बनायेंगे। इस प्रकार यदि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर ये उत्पाद अधिक मात्रा में भारत में प्रवेश करने लगेंगे।

पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

125. मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क लागू होने, कीमत में कटौती होने, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होने के बावजूद भी संबद्ध देशों से जांच अवधि में आयातों की वर्तमान मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निरंतर पाटन होने और घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है। पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयात की कीमतें घरेलू कीमतों में और कटौती करेंगी और साथ ही उनका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक दमनकारी प्रभाव पड़ेगा। संबद्ध देशों के पास उपलब्ध बेशी क्षमताएं होने से संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

126. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि यदि पाटन-रोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को, वर्तमान जांच अवधि में पाए गए पाटन मार्जिन और पाटन क्षति के स्तरों से नीचे कर दिया जाता है, तो आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि भारत में निर्यातों के संबंध में वर्तमान जांच अवधि में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का स्तर यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति मार्जिन से स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति के गहन होने की

संभावना है। इस प्रकार जांच अवधि और जांच पश्चात् अवधि के दौरान तृतीय देशों को विशिष्ट नियर्ति कारोबारों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वर्तमान जांच अवधि में स्थापित पाटन और क्षति के स्तर पर पाटन-रोधी शुल्कों की मात्रा को कम करना उपयुक्त नहीं होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, संभावना का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राचलों में से एक प्राचल है। ये प्राचल पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संभावना की स्थिति का निर्णय लेने के लिए स्वतः पर्याप्त नहीं हैं। जहां तक कि ऐसी स्थिति में जिसमें जांच अवधि में पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, ऐसी स्थिति में पाटन-रोधी शुल्क को और बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि ऐसा पाया जाता है कि जांच अवधि में पाटित और/अथवा क्षति कीमत पर तृतीय देशों को नियर्ति किए जा रहे हैं अथवा जांच पश्चात् अवधि में पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन सकारात्मक पाया जाता है। इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बढ़ने की संभावना है। जैसा कि जांच अवधि में तृतीय देशों को नियर्ति तथा जांच पश्चात् अवधि में भारत और तृतीय देशों के पेटर्न से सिद्ध होता है, पाटन-रोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा को निरंतर जारी रखे जाने की सिफारिश करना उपयुक्त होगा।

कारणात्मक संबंध

127. अधिनियम की धारा 9 क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन और क्षति की संभावना और शुल्कों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता की जांच करना अपेक्षित होता है। जांच से ऐसा पता चला है कि पाटित कीमतों पर आयात किए गए थे, घरेलू उद्योग का पुनः क्षति हुई है और पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। इसके बावजूद प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है।

- (क) तृतीय देशों से नियर्तः- तृतीय देशों से आयात का मात्रा शून्य है अथवा ये आयात अधिक कीमतों पर हैं।
- (ख) उत्पाद की मांग:- विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है और इसलिए घरेलू उद्योग की क्षति के दावे का कारण मांग में संभावित संकुचन नहीं हो सकता है।
- (ग) खपत के पेटर्न में परिवर्तन:- विचाराधीन उत्पादक के खपत के पेटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पेटर्न में कोई परिवर्तन, घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- (घ) प्रतिबंधित व्यापारिक पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:- ऐसी कोई प्रतिबंधित व्यापारिक पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- (ड) प्रोटोग्राफी में विकास:- यह नोट किया गया है कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोटोग्राफी में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटोग्राफी में विकास होने के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है।
- (च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन:- घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है। तथापि, केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही क्षति विश्लेषण किया गया है।
- (छ) नियर्त निष्पादन:- घरेलू उद्योग ने केवल घरेलू प्रचालनों के कारण हुई क्षति का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने उपयुक्त स्थानों पर उसके नियर्त निष्पादन को पृथक किया है।

K. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

घरेलू उद्योग के निवेदन

128. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) विचाराधीन उत्पाद में टेंसिल फाईबर/लयोसिल फाईबर शामिल हैं। इन फाईबरों के आयात तृतीय देशों (आस्ट्रिया, यूके, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका) से किए जा रहे हैं और लेंजिंग द्वारा इनका उत्पादन, अपने संयंत्रों में किया जा रहा है, जो कि इंडोनेशिया और चीन से भिन्न हैं। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि चीन के उत्पादकों ने भी इस फाईबर का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। ऐसा सूचित किया गया है कि इस फाईबर के आयात 5504.9090 शीर्ष के अंतर्गत किए जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि चीन इस विचाराधीन उत्पाद को अन्य शीर्ष संहिता (5504.1090 और 5504.1029, 5504.9000 और 5504.1021) के अंतर्गत वर्गीकृत कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि फाईबर/लयोसिल फाईबर विचाराधीन उत्पाद के अंश हैं और इन्हें तृतीय देशों से आयातों में शामिल किया गया है।
- (2) शुल्क तालिका में विचाराधीन उत्पाद का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए और उसमें यह निर्दिष्ट भी किया जाना चाहिए कि सीमा-शुल्क के वर्गीकरण की ओर ध्यान दिए बिना इन सभी मदों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होता है।
- (3) याचिकादता ने यह भी सिद्ध किया है कि थाईलैंड के माध्यम से चीन/इंडोनेशिया से ऐसे उत्पादों के आयातों पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की कोई अपवर्चना नहीं हुई है।

(4) निर्यातिकों ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है - (1) इनपुट के मामले में वह संबंधित पक्षकार से है, (2) वित्तपोषण के संबंध में वह संबंधित पक्षकार से है, (3) विक्रियों के संबंध में वह संबंधित पक्षकार से है और (4) प्रबंधन शुल्क जिससे पता चलता है कि ये सेवाएं उसे उसकी जननी कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है।

(5) भ्रामक सूचना देने के कारण प्रश्नावली के उत्तर को खारिज कर दिया जाना चाहिए - जो कि (1) कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन करते, (2) बाजार से पल्प की खरीदारी करते, (3) मशीनरी उपस्कर और कल पुर्जों के संबंध में जननी कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और (4) फाईबर को बेचने के बारे में है। वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित पक्षकार के प्रकटन से स्पष्ट पता चलता है कि उपरोक्त कारोबार संबंधित पक्षकारों के कारोबार से संबंधित हैं।

(6) याचिकादाता को इसकी जानकारी नहीं है कि क्या संबंधित पक्षकार ने कार्पोरेट सेवाओं सहित कोई अन्य सेवाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार साऊथ पेसिफिक विस्कोस के न राजस्व और न ही व्यय संबंधित पक्षकार के कारोबार से मुक्त नहीं हैं और निर्यातिक की व्यापक जांच की जानी चाहिए थी, यदि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष निर्दोश पेश होता और यदि उसने वास्तव में सभी प्रासंगिक तथ्यों का सार्वजनिक वृतांत पेश कर दिया होता। तथापि, साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने याचिकादाता से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का इरादा दुर्भावपूर्ण था और उसने इस प्रयोजनार्थ गोपनीयता के प्रावधानों का आश्रय लिया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता को अपने हितों की रक्षा करने और वर्तमान जांच में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने से रोका गया है। साऊथ पेसिफिक विस्कोस के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में प्रक्रियात्मक औपचारिकता मात्र से वर्तमान जांच में याचिकादाता की सहभागिता को कम कर दिया गया है।

(7) इंडोनेशिया सरकार के वस्तु उद्योग में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी ने इंडोनेशिया सरकार से अनुदान प्राप्त किया है। कंपनी को ऐसे अनुदान 12 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किए गए हैं। निर्यातिक ने इस तथ्य को भी छिपाया है।

(8) प्रश्नावली के भाग-2 के उत्तर में साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने यह बताया है कि उसकी ऐसी कोई फर्म नहीं है जो कि भारत में और तृतीय देशों में ऐसे उत्पाद का उत्पादन करती है अथवा उसका उत्पादन करने का कोई संयंत्र है। यह पूर्णतया झूठा विवरण है, क्योंकि साऊथ पेसिफिक विस्कोस लेंजिंग एजी की एक सहायक कंपनी है और जिसके आस्ट्रिया में दो संयंत्र, यूके में एक संयंत्र और संयुक्त राज्य अमरीका में एक संयंत्र स्थापित है। निर्यातिक द्वारा ऐसा झूठा और भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(9) साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने यह सिद्ध नहीं किया है कि मुख्य कच्चे माल (पल्प) सहित इनपुट की उसकी अधिप्राप्ती कीमत उचित रूप से ऐसी कीमत की परिचायक है जो कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री की लागत से संबद्ध है।

(10) साऊथ पेसिफिक विस्कोस की वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस अवधि में पल्प की कीमतों में गिरावट आई थी, पल्प आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी को देय राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त पल्प आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी को औसत बकाया राशि, उचित रूप से उच्च स्तरों पर है और यह 100 दिनों से भी अधिक बकाया रहने की परिचायक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यदि उसकी पल्प आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी के साथ संबंध नहीं होता तो कंपनी को अत्यधिक व्याज लागत का भुगतान करना पड़ता। इस प्रकार संबंधित कंपनी द्वारा साऊथ पेसिफिक विस्कोस को आर्थिक सहायता दिए जाने का स्पष्ट पता चलता है।

(11) कंपनी ने अपनी जनक कंपनी से अत्यधिक ऋण प्राप्त किया है। ऐसे ऋण पर लिवर सहित 2.75% व्याज प्रभारित किया जाता है। तथापि, निर्यातिक ने इस व्याज दर को उचित सिद्ध करने की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। यदि साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने इंडोनेशिया में ऋण प्राप्त किया होता, तो कंपनी को इंडोनेशिया में लागू व्याज की दर से लगभग 13% की वार्षिक दर पर व्याज का भुगतान करना पड़ता। उत्पादन की लागत को इनके लिए समायोजित करने की आवश्यकता होती है, ताकि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत और बिक्री से उसके उचित रूप से प्रासंगिक होना प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अत्यधिक अपूर्ण उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को इंडोनेशिया में लागू व्याज की दर पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों पर पूरा व्याज प्रभारित करना चाहिए।

(12) उत्पाद का विपणन जनक कंपनी के विपणन अंग द्वारा किया गया है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि ऐसे विपणन अंगों से संबंधित समस्त व्यय को, जिसमें एसजीए और शामिल है, का पाटन मार्जिन का निर्धारण किए जाने के लिए ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

(13) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में 1-10% की सीमा में पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। याचिकादाता ने निर्यातिक की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में निर्यात कीमत के आधार पर निर्यातिक के पाटन मार्जिन का निर्धारण 341 अमरीकी डालर प्रति मी.टन किया है। पाटन मार्जिन में यह अंतर बहुत अधिक है।

(14) सर्कुलन बीविंग मशीन के मामले में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने उत्पादक की धारक कंपनी के भारतीय अंग के लिए सैद्धांतिक लाभ और एसजीए के लिए निर्यात कीमत को समायोजित किया है। तथापि, निर्यातिक

ने प्राधिकारी को ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा भ्रामक विवरण देने के कारण ऐसे मुद्दों की कभी जांच नहीं की है और घरेलू उद्योग ने अभी हाल तक ऐसा कभी अवसर प्राप्त नहीं किया है कि वह निर्यातक द्वारा ऐसे तथ्यों को छिपाने और भ्रामक विवरण दिए जाने को ध्यान में रखते हुए इन तथ्यों को विशेष रूप से उजागर करे।

(15) याचिकादाता ने पहले याचिका में यह निवेदन किया है कि निर्यातक बीजक पश्चात् छूट देता है। निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर, इस तथ्य को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है। निर्यातक ने यह बताया है कि उसके पास कोई कीमत सूची नहीं है और बातों के माध्यम से आर्डर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आर्डर प्राप्त करने के बाद छूट देने को कोई प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, निर्यातक ने यह बताया है कि कीमतों पर बातचीत की जाती है, जो कि बाजार की दशाओं पर निर्भर करता है और "छूट अपरिहार्य" है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातक आर्डर प्राप्त करने के बाद छूट दे रहा है। याचिकादाता का यह निवेदन है कि बीजक पश्चात् ऐसी छूट 100 अमरीकी डालर प्रति टन तक अधिक थी।

(16) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि निर्यातक को विनिमय में क्षति हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में विनिमय लाभ में क्षति का समायोजन करने के बाद राशि सूचित की जाती है। विनिमय क्षति की समग्र राशि, कच्चे माल की लागत होती है, जबकि विनिमय लाभ राजस्व के भाग होते हैं। इसलिए याचिकादाता का प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए विनिमय क्षति की सकल राशि पर विचार किया जाए।

(17) याचिकादाता ने उप-उत्पाद/अपशिष्ट/स्क्रेप/क्षति/घटिया वस्तुओं को गोपनीय माने जाने के प्रश्न पर उत्तर का दावा किया है। याचिकादाता का यह निवेदन है कि यह इस कारण से दुर्भावपूर्ण है कि एक ओर अपशिष्ट/स्क्रेप/क्षति/उप-उत्पाद और दूसरी ओर घटिया वस्तुओं का ऐसा निरूपण पाठन विधि के अंतर्गत पूर्णतया भिन्न है। जहां तक घटिया वस्तुओं का संबंध है, इन्हें उत्पाद का एक भाग ही माना जाना चाहिए। जहां तक अपशिष्ट/स्क्रेप/क्षति/उप-उत्पाद का संबंध है, चूंकि वर्तमान मामले में ये एनपीयूसी हैं, इसलिए अपशिष्ट/स्क्रेप/क्षति/उप-उत्पाद के उत्पादन के लिए उसका समायोजन करने के बाद उसके उत्पादन का निर्धारण करने की आवश्यकता है।

(18) लेंजिंग की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि लेंजिंग की लिखी गई मांग सूचियां 9.88 मिलियन यूरो की हैं। याचिकादाता का यह निवेदन है कि मांग सूचियों का लिखा जाना उत्पादन की लागत का वैसा ही भाग बनती है, जैसा कि उत्पादन की लागत के एक भाग के रूप में कच्चे माल पर विदेशी मुद्रा की क्षति होती है। इसलिए माल सूची की लिखी गई राशि को कच्चे माल की लागत के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उत्पादन की लागत का निर्धारण किया जा सके।

(19) याचिकादाता ने जांच की कार्रवाई के समय इंडोनेशिया के सीमा-शुल्क विभाग में सूचित की गई अत्यधिक कम कीमत का मुद्दा कई बार उठाया था। तथापि, निर्यातक द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और न ही निर्यातक ने कभी यह प्रमाणित किया है कि इंडोनेशिया के सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों से उसकी निर्यात कीमत की संपुष्टि कैसे होती है। साऊथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत को इसी आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

(20) याचिकादाता का यह निवेदन है कि साऊथ पेसिफिक विस्कोस की वार्षिक रिपोर्ट से पहले ही ऐसा पता चलता है कि कंपनियों को वित्तीय घाटे हुए हैं। निर्यातक के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि उसके तृतीय देशों के निर्यातों की कीमत की तुलना भारत में निर्यातों से की जा सकती है, ऐसा पता चलता है कि गृह बाजार में उसकी सभी बिक्रियों पर उसे घाटा हो रहा है। इस प्रकार याचिकादाता का यह निवेदन है कि वर्तमान मामले में उत्पादन की लागत का सही मूल्यांकन किया जाना अत्यावश्यक है।

(21) याचिकादाता का यह भी निवेदन है कि याचिकादाता द्वारा इस समय किए जा रहे निवेदन, प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय वृत्तांत के रूप में नहीं है। वास्तव में साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में इस सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकादाता ने यह निवेदन याचिकादाता द्वारा अपनी बाजार आसूचना से अब प्राप्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया है।

(22) हरिहर में कंपनी ने अपने पल्प की अत्यधिक खपत की है। पल्प का अंतरण पल्प प्रभाग से फाईबर प्रभाग को वित्तीय खातों के माध्यम से किया जाता है। वीएसएफ में अपनाया गया पल्प का मूल्य, कंपनी द्वारा बना कर रखे गए वित्तीय रिकार्ड के आधार पर है। चूंकि कंपनी द्वारा केप्टिव पल्प का मूल्यांकन कंपनी द्वारा बना कर रखे गए वित्तीय रिकार्ड के आधार पर है, इसलिए वर्तमान प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा अपनाए गए मूल्य को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

(23) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी और घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दावा की गई एनआईपी में अत्यधिक अंतर व्याप्त है। इसके अतिरिक्त प्रकटन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि घरेलू उद्योग की एनआईपी को क्यों अत्यधिक घटा दिया गया है।

(24) अचल सम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य अथवा अचल परिसम्पत्तियों के कम से कम सकल मूल्य को ध्यान में रख कर नियोजित पूँजी का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में निबल अचल परिसम्पत्तियों का अपनाया जाना अत्यधिक असंगत है और

वास्तव में इस पर विचार करते हुए कि कुछ निवेश अत्यधिक पुराने हैं, घरेलू उद्योग के लिए अनुचित है तथा इसलिए निबल अचल परिसम्पत्तियां, निवेश का सही मूल्य का परिचायक नहीं हैं। वास्तव में इस प्रयोजनार्थ एनआईपी का निर्धारण करने के लिए अत्यधिक उचित मूल्य, निवेश का वर्तमान मूल्य है।

- (25) याचिकादता का निवेदन है कि कच्चे माल के उपयोग और प्रयोज्यताओं के उपयोग पर विगत में प्राप्त उत्तम स्तर पर इस कारण से विचार किया जाना चाहिए कि खपत में वृद्धि ऐसी इनपुट की अपर्याप्त उपयोग नहीं होती है।
- (26) अनुबंध-3 के अंतर्गत कच्चे माल अथवा प्रयोज्यताओं के केवल अपर्याप्त उपयोग को सामान्य बनाए जाने की आवश्यकता होती है। कच्चे माल में आधारभूत परिवर्तन को सामान्य बनाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इनपुट की वास्तविक खपत पर विचार करें।
- (27) कंपनी की समेकित विक्रियों पर विचार करते हुए कंपनी के व्यय आवंटित किए जाते हैं। तथापि, कार्पोरेट के ऐसे व्यय केवल भारतीय व्यवसाय से संबंधित होते हैं।
- (28) एनआईपी का परिकलन करते समय अनुसंधान और विकास व्यय पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे व्यय उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। भारित औसत एनआईपी का निर्धारण करते समय एक्सिल, नागडा संयंत्र की एनआईपी पर विचार नहीं किया गया है।
- (29) पाटन-रोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप उत्पादन और विक्रियों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात समग्र रूप से बढ़ गए हैं और भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के प्रसंग में वे अत्यधिक बने हुए हैं। आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में अत्यधिक है।
- (30) पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के बावजूद संबद्ध आयात का अत्यधिक बाजार हिस्सा है। पाटन-रोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती अत्यधिक सकारात्मक है।
- (31) साऊथ पेसिफिक विस्कोस के प्रश्नावली के उत्तर और उसकी वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि वह वर्ष 2014 से बाजार दशाओं में निरंतर गिरावट का दावा कर रही है, जिसका मुख्य कारण चीन में अतिरेक क्षमताओं का विद्यमान होना है। विगत तिमाही में निर्यातिक के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जिससे क्षति होने की संभावना का और स्पष्ट पता चलता है।
- (32) कंपनी ने सूचित किया है कि वर्ष के दौरान बाजार की दशाएं "घातक" थीं जिसके फलस्वरूप उसे व्याज और कर पूर्व नकारात्मक लाभ हुआ है। वर्ष 2015 में भी कंपनी को बाजार की दशाओं के कठिन बने रहने की आशा है। कंपनी को घाटे होने का प्रमुख कारण अत्यधिक कम विक्री कीमत होना था।
- (33) कंपनी ने पीटीजी और एलएजी को कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया है और इरेफिस्टा को केवल 50% कमीशन का भुगतान किया है। उत्पादन की लागत पर इनके पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं।
- (34) साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों के बारे में अपर्याप्त सूचना प्रदान की है। इसके अतिरिक्त साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने अत्यधिक भ्रामक सूचना प्रदान करने की चेष्टा की है और ज्ञाठा व्यान दिया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को साऊथ पेसिफिक विस्कोस को उनके आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी को पी.टी. इंडो भारत के आधार पर सामान्य मूल्य और इंडोनेशिया सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करना चाहिए और उसके बाद पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।
- (35) इसलिए पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि होने के कारण बढ़ाया जा सकता है। किसी दुर्भावना के बिना यदि प्राधिकारी निरंतर यह विचार करते हैं कि ऐसी सुस्पष्ट अंतर युक्त, ज्ञाठी और भ्रामक सूचना के बावजूद साऊथ पेसिफिक विस्कोस के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, उनकी प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया जाना आवश्यक है, तो प्राधिकारी पाटन-रोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि मूल जांच में इसे लगाया गया था। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के होने की स्पष्ट संभावना है।
- (36) याचिकादता ने इंडोनेशिया के मामले में विशिष्ट पृथक निर्यात कारोबार पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का विश्लेषण किया है। तृतीय देशों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन, भारत के मामले में पाटन और क्षति की तुलना में समग्र रूप से अधिक है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वाले निर्यातों की मात्रा, भारत की तुलना में बहुत अधिक है। साऊथ पेसिफिक विस्कोस के मामले में पाटित आयातों की मात्रा, इंडो भारत के मामले में पाटित आयातों की मात्रा से अधिक है।
- (37) याचिकादता ने भारतीय सीमा-शुल्क विभाग के अनुसार जांच पश्चात् अवधि के आंकड़ों पर विचार करते हुए इंडोनेशिया के मामले में पाटन और क्षति मार्जिन का भी विश्लेषण किया है। इसके संबद्ध परिकलन और आयात के आंकडे संलग्न हैं। इनसे यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि पश्चात् की अवधि में निर्यात कीमत में 72.84 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन की गिरावट

आई है। इस प्रकार यदि प्रकटन विवरण में दिए गए पाटन मार्जिन पर विचार किया जाता है, तो जांच अवधि पश्चात् की अवधि में पाटन मार्जिन, मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क से अधिक है।

- (38) पाटन-रोधी शुल्क को निर्धारित रूप में लागू किया जा सकता है। इस उपाय के रूप को अमरीकी डालर में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।
- (39) याचिकादता का निवेदन है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास पहले से ही अत्यधिक बेशी क्षमताएं स्थापित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त संबद्ध देशों में और नई क्षमताएं स्थापित की जा रही हैं।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

129. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-
 - (1) प्राधिकारी ने आवेदक उद्योग की पात्रता पर हमारे निवेदनों का निदान नहीं किया है। आवेदकों ने अपनी गोपनीय सूचना में पारस्परिक रूप से सांझेदारी की है और आवेदक उद्योग और दोनों संबद्ध देशों के एक निर्यातक का प्रतिनिधित्व एक सामान्य कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने सामान्यतया यह बताया है कि वर्तमान मामले में यह "समग्र रूप से अप्रासंगिक" है, जिसके समर्थन में उन्होंने कोई कारण दर्ज नहीं किया है।
 - (2) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में बताया है कि आवेदक उद्योग की दोनों संबंधित कंपनियों को पाटन और क्षति होने की संभावना है। यदि ऐसा मामला है, तो प्राधिकारी को केवल अंतिम परिणाम यह दर्ज करना चाहिए था कि नियम 2 (ब) के अनुसार आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र माने जाने पर विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुए थे, अंतिम समीक्षा जांच पर पूर्णतया कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि प्राधिकारी का निर्णय, पाटन और क्षति की संभावना पर आधारित है।
 - (3) प्राधिकारी को आवेदक उद्योग की पात्रता की पुनः जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम 2 (ब) के अनुसार यदि यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग किसी निर्यातक या अयातक से संबंधित है अथवा उसने स्वयं आयात किए हैं, तो उसको शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाए का निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि यह मुद्दा पूर्व अंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णयिक चरण में पहुंच गया है, वास्तविक रूप से सही नहीं है, यदि इसे विषय पर स्थापित विधि के मापदंड से परीक्षित किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अंतिम जांच परिणाम की माननीय ट्रिभ्यूनल द्वारा रद्द कर दिया गया था और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया गया था। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वे प्रभावी हैं क्योंकि वे एटीएमए के मामले में पाटन-रोधी विधि के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित प्राकृतिक न्याय का अतिक्रमण करते थे।
 - (4) निर्णयिक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन है कि "वीएसएफ अपशिष्ट" को मूल जांच में बाहर नहीं रखा गया था और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर रखा जाना चाहिए।
 - (5) प्रकटन विवरण में यह दर्ज है कि केवल इंडोनेशिया से "वीएसएफ अपशिष्ट" (जो कि गैर-विचाराधीन उत्पाद है) का आयात किया गया है, जबकि आयात आंकड़ों से पता चलता है कि केवल विचाराधीन उत्पाद की अनेक प्रविष्टियां हुई हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि उनके अनुसार कौन सी प्रविष्टि विचाराधीन उत्पाद नहीं है।
 - (6) प्रकटन विवरण के पैरा 56 के उत्तर में यह निवेदन किया जाता है कि साऊथ पेसिफिक विस्कोस सीधे प्रयोक्ताओं और व्यापारियों को वस्तुएं बेच रही हैं और भारत में इसकी संबंधित कंपनी का विपणन कार्यालय मात्र है, जिससे उसके वितरण के माध्यम में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की खरीद के बारे में संबंधित कंपनी से खरीद से संबंधित व्यारों के साथ-साथ विस्तृत दस्तावेजी प्रमाण वास्तव में प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए थे।
 - (7) जांच पश्चात् अवधि के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करने के संबंध में प्राधिकारी ने अभूतपूर्व तरीके से जांच अवधि पर आधारित सामान्य मूल्य का परिकलन किया है जिसमें 5% जोड़ दिया गया है। प्राधिकारी को संभावना के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए निर्यातक के जांच अवधि पश्चात् के परिशिष्ट-1 पर विचार करना चाहिए था, जो कि पहले से ही रिकार्ड पर है।
 - (8) आवेदक उद्योग की घरेलू बिक्रियों की तुलना में घरेलू खपत के लिए निचले स्तर उत्पाद के उपयोग के लिए अथवा निर्यात प्रयोजनार्थ भिन्न कीमतें हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया क्षति का मूल्यांकन करते समय इस कारक पर विचार करें। यह उपयुक्त होगा कि ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए जो कि अंततः वस्तुओं का निर्यात करते हैं, कम विक्री कीमत होने के कारण किसी प्रकार की कम वसूली के लिए इंडोनेशिया से आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

(9) प्राधिकारी ने अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार पाटन-रोधी शुल्क जोड़ने के बाद कोई विश्लेषण नहीं किया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया पाटन रोधी शुल्क को जोड़ने के बाद क्षति प्राचलों, कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री होने का भी विश्लेषण करें, ताकि आवेदक उद्योग की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जा सके। पाटन रोधी शुल्क को जोड़े बिना वर्तमान विश्लेषण से केवल संभावित विश्लेषण होगा और इसे जांच अवधि के लिए क्षति विश्लेषण के समान नहीं माना जा सकता है।

(10) आवेदक उद्योग की माल-सूची में वृद्धि होने के संबंध में प्राधिकारी ने पैरा 88 में यह नोट किया है कि "घरेलू उद्योग की मांग सूचियां बढ़ गई हैं, जिससे पता चलता है कि यदि नियर्तकों ने अपनी कीमतों में और कमी नहीं की होती और पाटन-रोधी शुल्क को समायोजित नहीं किया होता, तो घरेलू उद्योग ने अधिक बिक्री की होती।" प्राधिकारी को माल सूची में आयातों के योगदान का विश्लेषण करना चाहिए।

(11) यह निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा संभावना का किया गया विश्लेषण अधूरा है और यह किसी सार्थक मूल्यांकन के बिना है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने केवल संबद्ध देशों के नियर्तकों के संभावित पाटन, कीमत आकर्षण और नियर्त की सघनता पर विचार किया है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से मामूली अधिक है और इसे अत्यधिक या वास्तविक नहीं कहा जा सकता है।

(12) कीमत के आकर्षण के संबंध में यह एक खोखला व्यापार मात्र है क्योंकि भारत में और विश्वभर में कीमतें लगभग एक समान हैं। इस प्रकार यह सुझाव देने का कोई आधार नहीं है कि भारतीय बाजार विशेष रूप से कीमत आकर्षक है।

(13) साऊथ पेसिफिक विस्कोस की नियर्त सघनता के बारे में उल्लेखनीय है कि अनेक वर्षों से भारत में नियर्त कुल मिला करके समान बने हुए हैं। यह भी एक तथ्य है कि साऊथ पेसिफिक विस्कोस केवल ऐसे ग्राहकों को समग्र वस्तुएं बेच रही है, जिनकी आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जाती है अथवा जिनकी आपूर्ति करने में उसकी मनाही है। इसलिए साऊथ पेसिफिक विस्कोस के पास अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। साऊथ पेसिफिक विस्कोस अपनी क्षमता का 99% का उपयोग कर रही है और लगभग अपनी संपूर्ण मात्रा को बाजार में बेच रही है। इसलिए साऊथ पेसिफिक विस्कोस के पास कोई वेरी क्षमता उपलब्ध नहीं है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में बताया गया है, जिससे नियर्त की सघनता की मिथ्या अवधारणा का और खंडन हो जाता है।

(14) क्षति और पाटन की संभावना होने के आधार पर साऊथ पेसिफिक विस्कोस पर शुल्कों को आगे बढ़ाने का कोई कानूनी या युक्तिसंगत आधार नहीं है। चूंकि प्राधिकारी ने जांच पश्चात् अवधि के लिए क्षति मार्जिन का परिकलन नहीं किया है, इसलिए हमारा प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया साऊथ पेसिफिक विस्कोस के खिलाफ किसी संभावित विश्लेषण के प्रतिकूल निष्कर्ष पर विचार नहीं करें।

(15) निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिणामों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद में से मॉडल/माईक्रो मॉडल फाईबर को बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने मार्च, 2015 में शुरू किए गए अपने नए संयंत्र सहित भारत में कहीं भी किसी मॉडल/माईक्रो मॉडल फाईबर का उत्पादन नहीं किया है। घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों के लिए अनावश्यक संरक्षण प्राप्त नहीं करता है, जो कि भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है और न ही भारत में ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने की उसकी क्षमता स्थापित है।

(16) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकादाताओं द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं प्रयुक्त कुल लागत के 5% की लाभप्रदता की उपेक्षा की है और वे नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिलाभ देने पर विचार करते हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐसे प्रतिलाभ का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त कार्य-प्रणाली के पर्याप्त व्यारे प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन पर प्रतिवादी पक्षकार ऐसी अवधारणा का खंडन कर सके। ऐसोसिएशन का यह दावा है कि ऐसा अत्यधिक सामान्य प्रतिलाभ इस तथ्य के आलोक में यथोचित नहीं है कि याचिकादाता आंतराष्ट्रीय फाईबर कीमत पर पहले से ही 16% से 22% तक का प्रीमियम प्रभारित कर रहा है और घरेलू विक्रियों में अत्यधित सामान्य लाभ अर्जित कर रहा है।

(17) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य की पूर्णतया उपेक्षा की है कि याचिकादाता ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में निरंतर वृद्धि की है और उसने 16% से 22% तक का प्रीमियम प्रभारित किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि शुल्कों को निरंतर जारी रखे जाने से याचिकादाता के गलत पूंजी निवेश (विलायत संयंत्र में क्षमतओं में निवेश करने के) निर्णय को संरक्षण मिलेगा। इसलिए आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं और यदि शुल्कों को जारी रखा जाता है, तो याचिकादाता घरेलू उपभोक्ताओं से विस्कोस फाईबर की अंतराष्ट्रीय कीमतों से अधिक निरंतर प्रीमियम प्रभारित करता रहेगा।

(18) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में खपत के निमित्त विक्रियों (माने गए नियर्तों) को घरेलू विक्रियों में शामिल करके विधि और तथ्य दोनों तरीके से गलती की है, जिससे वास्तविक घरेलू लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत से बाहर खपत के निमित्त विक्रियों को क्षति और कारणात्मक संबंध से विशेष कर लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ,

नकदी लाभ और क्षति रहित कीमत का परिकलन(ऐसी विक्रियों पर छूट को बाहर रखने के बाद) से बाहर रखा जाए। ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्यातों में ऐसी छूटों और रिबेट की उपेक्षा की जाए जो कि भारत में खपत के निमित्त नहीं हैं।

- (19) लागू पाटन-रोधी शुल्क भारत के निचले स्तर के उद्योगों को कम लागत पर कच्चे माल को प्राप्त करने के अवसर से वंचित रखेंगे और उन्हें निर्यात के लिए अप्रतिस्पर्द्धी उद्योग बना देंगे। इसके अतिरिक्त निचले स्तर के उद्योग, लघु और मध्यम स्तर के उद्योग हैं जो कि पुनर्नियात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह "मेक इन इंडिया" की भावना के विरुद्ध है।
- (20) इसके अतिरिक्त ऐसे आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जिन्होंने प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर दिए बिना निवेदन किया है/पत्र प्रस्तुत किया है, से ऐसा पता चलता है कि उन्हें याचिकादाता कंपनी ने ऐसा पत्र प्रस्तुत करने के लिए धमकाया है (यह देखा जा सकता है कि ऐसी सभी पत्र एक जैसे हैं और मुख्यतया नम्मकल जिला, तमिलनाडु में अवस्थित कंपनियों के हैं)। इन कंपनियों के पास आयात करने का कोई स्रोत नहीं है।
- (21) विस्कोस स्टेप्ल फाईबर के भिन्न अंत प्रयोक्ता हैं और याचिकादाता कंपनी सभी ग्राहकों से समान कीमत प्रभारित नहीं करती है गैर-बुने 100% विस्कोस यार्न/पोलिएस्टर यार्न में विस्कोस और विस्कोस सूती यार्न आदि और साथ ही यार्न के निर्यात में विस्कोस के लिए भी भिन्न कीमत होती है।
- (22) तांगशान पाटन-रोधी जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन से बहुत प्रभावित हुआ है। पाटन मार्जिन का परिकलन, प्रस्तावित सीएनवी और सानयू के निर्यात मूल्य से किया जाता है। पाटन-रोधी करार के पैरा 2.4 में ऐसा प्रावधान निहित है कि "निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना की जाएगी"। इसलिए जांच प्राधिकारी को पाटन मार्जिन का परिकलन करने में जांच किए गए उत्पादकों द्वारा निर्यातित सभी मॉडलों के निर्यात कारोबार पर विचार करना चाहिए। इस मामले में संबद्ध उत्पाद के लिए विभिन्न विनिर्देशन अथवा मॉडल हैं। लेकिन हम प्रकटन विवरण से ऐसा अभिज्ञात नहीं कर सकते हैं कि क्या तुलना, विभिन्न उत्पाद विनिर्देशनों अथवा मॉडलों पर आधारित है।
- (23) प्रश्नावली के परिशिष्ठ 2 के अनुसार सानयू के विचाराधीन उत्पाद की मात्रा 267.5 मी.टन है। तथापि, प्रकटन से हमने ऐसा नोट किया है कि जांच अवधि के दौरान चीन से आयात की मात्रा 22 मी.टन मात्र है। ऐसे परस्पर विरोधी आंकड़ों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- (24) प्राधिकारी द्वारा पेश की गई सानयू की कार्यगत निर्यात कीमत, प्रश्नावली में प्रस्तुत आंकड़े से भिन्न है। इसमें तदुनसार संशोधन किया जा सकता है।
- (25) जांच अवधि के दौरान अमरीकी डालर और आईएनआर, सदैव स्थिर संचया पर स्थिर नहीं रहे हैं। काफी लंबे समय तक ये आंकड़े 61.69 से अधिक बने रहे हैं। इसलिए सीआईएफ कीमत का परिकलन करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त विनिमय दर उचित नहीं है।
- (26) ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिचायक घरेलू उत्पादों के समेकित दस वर्षीय वित्तीय सारांश का परिशीलन करने पर हमने यह पाया है कि जांच अवधि के दौरान ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वीएसएफ से प्राप्त लाभ उच्चतर स्तर पर है।
- (27) जैसा कि प्रकटन में उल्लेख किया गया है, मॉडल फाईबर अधिक कीमत होने, उसमें विशेष उत्पादन प्रोद्योगिकी निहित होने और उसका विशेष प्रयोग किए जाने के कारण समान बाजार में विचाराधीन उत्पाद से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रहा है। याचिकादाता और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के अनुसार मॉडल फाईबर/मार्ईक्रा मॉडल फाईबर को विचाराधीन उत्पाद से कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

130. प्रकटन पश्चात् निवेदनों का निदान इस परिणाम के पूर्व पैराओं में पहले से ही कर दिया गया है। तथापि, उनका बिन्दु-वार किया जा रहा निदान इस प्रकार है:-

- (1) प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मूल जांच में अपविष्ट विचाराधीन उत्पाद नहीं था अथवा यह वर्तमान जांच में भी विचाराधीन उत्पाद नहीं है। निर्यातिक का यह दावा कि इससे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, निराधार है।
- (2) साऊथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में वितरण के माध्यम से संबंधित सूचना के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि साऊथ पेसिफिक विस्कोस के प्रश्नावली के उत्तर में भारत में विपणन कार्यालय की भूमिका के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, न ही कंपनी ने इस विपणन कार्यालय को किए गए भुगतान के बारे में कोई सूचना प्रदान की है और लेंजिंग के भारतीय कार्यालय द्वारा किए गए व्यय पर विचार करते हुए यह पर्याप्त है।

(3) कच्चे माल की खरीद के बारे में साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने प्रश्नावली के उत्तर में वास्तव में यह दावा किया है कि आदानों की सभी खरीदारियां असंबंधित पक्षकारों से की गई थीं, जब कि पल्प की खरीदारी वास्तव में संबंधित पक्षकारों से की गई थी।

(4) 5% लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर जांच अवधि पश्चात् सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि पश्चात् सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संपूर्ण सूचना की आवश्यकता होता है जो कि उपलब्ध नहीं कराई गई थी और इसलिए प्राधिकारी ने 5% लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि जांच अवधि और जांच पश्चात् अवधि में पी.टी. साऊथ पेसिफिक विस्कोस की भारित औसत कीमत कुल मिला कर समान रही है, इसलिए प्राधिकारी ने यह उपयुक्त समझा है कि जैसा कि जांच अवधि में और जांच पश्चात् अवधि के लिए तथा साथ ही तृतीय देशों के निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य के साथ 5% लाभ को जोड़ कर तय किया गया है, उत्पादन की लागत को अपनाया जाए। इंडोनेशिया से अन्य निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य की उचित तुलना सुनिश्चित करने के विचार से इसी कार्यप्रणाली को अपनाया गया है।

(5) घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुछ विक्रियों के संबंध में, जिन्हें माने गए निर्यात की विक्रियां वर्णित किया गया है, याचिकादाता ने यह स्पष्ट किया है कि उसने इन विक्रियों से कोई निर्यात लाभ प्राप्त नहीं किया है और ये विक्रियां घरेलू उपभोक्ताओं को की गई हैं तथा इन मामलों में वस्तुएं देश के भीतर खपत किए जाने के निमित्त थीं। इन मामलों में घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात लाभ प्राप्त किए गए हैं। इन विक्रियों को सीधे घरेलू विक्रियां माना जाता है।

(6) पाटन-रोधी शुल्क को जोड़ने के बाद कीमत कटौती का मूल्यांकन करने के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की विक्री कीमत पाटन-रोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयात की पहुंच कीमत के लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णयिक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी को संभावना के प्रयोजनार्थ पाटन-रोधी शुल्क को जोड़ विना तथा कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना आवश्यक है। पाटन-रोधी शुल्क को जोड़ विना सकारात्मक कीमत कटौती तथा पाटन-रोधी शुल्क को जोड़ने के बाद लगभग तुलनीय घरेलू और आयातित उत्पाद कीमतों से यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कीमत में कटौती होने के साथ-साथ कम कीमत पर विक्री होने पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

(7) माल सूचियों में वृद्धि होने के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग माल सूचियों की सीमा तक विक्री कर सकता था। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान माल सूचियां और आयातों में निर्विवाद रूप से वृद्धि हुई है।

(8) संभावित विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पाटन मार्जिन की मात्रा के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन, संभावित विश्लेषण शुरू करने के प्राचलों में से एक प्राचल है। पाटन-रोधी शुल्क की वर्तमान मात्रा, निर्यातकों के पास उपलब्ध बेशी क्षमता और तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा भी इस संबंध में प्रासंगिक और उपयुक्त हैं।

(9) साऊथ पेसिफिक विस्कोस ने यह तर्क दिया है कि चूंकि क्षति अवधि के दौरान निर्यातों की मात्रा तुलनीय है, साऊथ पेसिफिक विस्कोस के पास निर्यात सघनता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद वर्ष 2012-13 में इंडोनेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य मात्रा से कि विद्यमान क्षमताओं को पूरा उपयोग किया जा रहा है, यह अभिप्राय नहीं है कि निर्यात के पास उपयोग किए जाने के लिए उत्पादन क्षमताएं नहीं हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया से निर्यातों की वर्तमान मात्रा पर्याप्त है, जिससे पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संभावित प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ने की संपुष्टि होती है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट में स्वतः अन्य बातों के साथ-साथ यही उल्लेख किया गया है, जिससे यहिसद्ध होता है कि निर्यातक बाजार में उसी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है, जिसका सामना याचिकादाता द्वारा किया जा रहा है।

(10) हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मॉडल/माईक्रा मॉडल फाईबर को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा मॉडल/माईक्रा मॉडल फाईबर का उत्पादन किया जाता है और तृतीय देशों से भी इनका आयात किया जाता है, हांलांकि इनका आयात संबद्ध देशों से नहीं होता है। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातकों ने मॉडल/माईक्रा मॉडल फाईबर के निर्यात नहीं किए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने मॉडल/माईक्रा मॉडल फाईबर के उत्पादन की लागत को बाहर रखने के बाद एनआईपी और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। तथापि, जहां तक क्षति विश्लेषण का संबंध है, चूंकि मॉडल/माईक्रा मॉडल फाईबर विचाराधीन उत्पाद का एक भाग है, इसलिए क्षति के विश्लेषण में उसे शामिल किया गया है।

(11) यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने सुसंगत तरीके से अपनी कीमतों में वृद्धि की है। तथापि, सत्यापित सूचना से ऐसा पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में निरंतर गिरावट आई है और इस दौरान उसकी लाभप्रदता में भी गिरावट आई है। उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के बावजूद विक्री कीमत में गिरावट आई है।

(12) विभिन्न आंकड़ों जैसे कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, एनआईपी आदि के प्रकटन के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सूचनाएं गोपनीय हैं और इसलिए इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। चीन से निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का परिकलन निवेशालय में सुस्थापित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

(13) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को निर्यातकों और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की तुलना करनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य याचिकादाता घरेलू उद्योग और निर्यातकों के बीच प्रस्पर्द्धा की जांच करना नहीं है। प्राधिकारी को इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन की पुनरावृति होने और उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की विदेशी उत्पादक के साथ पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा करना अप्रासंगिक है।

(14) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक अपनी कीमतों का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा घोषित कीमतों के आधार पर करते हैं। तथापि, जांच करने से ऐसा पता चला है कि कीमत में कटौती सकारात्मक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि घरेलू उद्योग पहले अपनी कीमतें तय करता है, तो निर्यातक उन कीमतों पर अपने उत्पाद को बेचता है जो कि घरेलू उद्योग की कीमत से कम होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती होगी और प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।

(15) निर्यात बाजार में निचले स्तर तक के उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्थिति में निर्यात उत्पादन के लिए उत्पाद के निर्यात पर पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होता है और इसलिए ऐसे निर्यात को प्रस्तावित उपायों के फलस्वरूप नुकसान नहीं होगा।

(16) कार्यप्रणाली और पाटन मार्जिन से संबंधित सूचना के प्रकटन के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के स्पष्ट ब्यौरे दिए गए हैं। जहां तक गोपनीय आंकड़ों का संबंध है, गोपनीयता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विधि के अंतर्गत निर्धारित किए गए सभी प्राचलों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना की है और चीन से ज्ञात निर्यातों को ध्यान में रखने के बाद सभी प्राचलों के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

(17) वास्तविक विशेषताओं और विनिर्देशनों में अंतर होने के बारे में निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना प्रदान नहीं की है और न ही ऐसा कोई दावा किया है जिससे यह पता चले कि विनिर्देशनों या मॉडलों में अत्यधिक अंतर व्याप्त है और भारित औसत तुलना करना उचित नहीं होगा। वास्तव में मौके पर सत्यापन करने पर ऐसा पता चला है कि विभिन्न किसी के उत्पादों के उत्पादन की लागत में कोई विशेष अंतर नहीं था।

(18) प्रकटन विवरण के पैरा (20) के बारे में उल्लेखनीय है कि हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण में इस पैरा को गलती से शामिल किए जाने के बारे में सूचित कर दिया गया था।

(19) विनियम दर के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन के क्रियाविधि के भाग में जांच अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत दर का उल्लेख कर दिया है। तथापि, आयात कीमत, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथा घोषित संबद्ध महीने के दौरान प्रचलित दर पर आधारित है।

(20) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और विदेशी निर्यातक का एक कानूनी सलाहकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर कोई प्रतिवंध नहीं है, विशेषकर जब कि दोनों संबंधित कंपनियां हैं। अंततः प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण, सत्यापित तथ्यों के आधार पर और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के संबंध में आत्म संतुष्टि होने के बाद किया है।

(21) याचिकादाता की पाटता से संबंधित तर्कों के बारे में तथ्य यह है कि दोनों कंपनियां संबंधित कंपनियां हैं और प्राधिकारी ने यह पाया है कि पाटन और क्षति के निरंतर होने और/अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को उसके कंपनी के साथ संबंधित होने के कारण एक अपात्र माना जाना चाहिए। प्राधिकारी ने वास्तव में याचिकादाता के घरेलू उद्योग होने के आधार का पुनर्मूल्यांकन किया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि कैसे याचिकादाता, नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर एक घरेलू उद्योग नहीं बनता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि संबद्ध देशों में ऐसे संबंधित उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया है और इसलिए किसी भी स्थिति में याचिकादाता का संबद्ध देशों में ऐसे संबंधित उत्पादकों के साथ संबंध होने से नियम 2 (ख) लागू नहीं होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाहर रखने का प्रश्न ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है जिसमें संबद्ध देशों में ऐसे संबंधित उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान अत्यधिक मात्रा में निर्यात किए हुए होते हैं। जब कि वर्तमान मामले में इंडोनेशिया में संबंधित कंपनी ने भारतीय बाजार में अपशिष्ट की नगण्य मात्रा में निर्यात किए हैं। याचिकादाता द्वारा प्रदत्त दस्तावेज से स्पष्ट

पता चलता है कि आयात को पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान किए बिना क्लीयर कर दिया गया था। इस तथ्य से न केवल यह सिद्ध होता है कि जांच अवधि के दौरान अपशिष्ट को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इससे यह भी सिद्ध होता है कि संबंधित पक्षकार ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

(22) याचिकादाता के दस वर्षीय वित्तीय सारांश के विश्लेषण के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्धारण, याचिकादाता की सत्यापित सूचना पर आधारित है, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए है। इसके अतिरिक्त लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ आदि का निर्धारण केवल घरेलू प्रचालनों के लिए किया गया है।

L. निष्कर्ष

131. प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पर विचार करने के बाद निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार है:-

(क) संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, उसके सामान्य मूल्य से कम पर किए गए हैं।

(ख) घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(ग) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृति होने की संभावना है।

(घ) इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी, इंडोनेशिया और चीन जनवादी गणराज्य के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा की सिफारिश करना उपयुक्त समझते हैं। चीन जनवादी गणराज्य के मामले में हालांकि मूल जांच के दौरान किसी भी निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया था, फिर भी वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच में एक निर्यातक ने उत्तर दिया है और सूचना प्रदान की है, जिस पर प्राधिकारी ने विचार किया है तथा विशिष्ट पृथक मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। तदनुसार प्रतिवादी निर्यातक और असहयोगी निर्यातक के लिए शुल्क नीचे तालिका में दिए गए हैं।

M. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

132. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्ध कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होनेवाली गिरावट रुकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पर्द्ध का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

N. निष्कर्ष और सिफारिशें

134. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए निवेदनों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर जिसमें पाटन के निरंतर जारी रहने और उसकी पुनरावृति होने और क्षति होने की संभावना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए निवेदन शामिल हैं, प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार है:-

(1) संबद्ध देशों से वस्तुएं भारतीय बाजार में पाठित कीमतों पर निरंतर प्रवेश कर रही हैं। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।

(2) घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में माल सूचियों, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह जैसे आर्थिक प्राचलों के रूप में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। जांच अवधि में आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत, उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत से कम है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को पाठित आयातों से पुनः क्षति हुई है।

(3) जांच अवधि में कीमत में कटौती सकारात्मक है और पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उसमें अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(4) यह तथ्य है कि संबद्ध देशों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएं विद्यमान हैं, संबद्ध देशों से निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और ऐसी कीमत निर्यात किए गए हैं, जो कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दर्शा रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि

पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के गहन होने और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(5) इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी, इंडोनेशिया और चीन जनवादी गणराज्य के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा की सिफारिश करना उपयुक्त समझते हैं। चीन जनवादी गणराज्य के मामले में हालांकि मूल जांच के दौरान किसी भी निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया था, फिर भी वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच में एक निर्यातक ने उत्तर दिया है और सूचना प्रदान की है, जिस पर प्राधिकारी ने विचार किया है तथा विशिष्ट पृथक मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। तदनुसार प्रतिवादी निर्यातक और असहयोगी निर्यातक के लिए शुल्क नीचे तालिका में दिए गए हैं। प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और “क्षति” को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी यह सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए। प्राधिकारी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है:-

शुल्क तालिका

क्रमांक	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्बातिक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	अम.डॉ.	यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(9)
1	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पी टी माऊथ पेसिपिक विस्कोस	पी टी माऊथ पेसिपिक विस्कोस	0.103	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
2	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	क्रमांक 1 में विनिश्चित कोई भी अन्य संमिश्रण		0.512	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
3	5504 10	विस्कोस	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	0.512	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
4	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	इंडोनेशिया से भिन्न कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	0.512		कि.ग्रा.
5	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोसस्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	तांगशान सानयू ग्रंप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	तांगशान सानयू ग्रंप हांग कांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	0.180	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
6	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक 5 में विनिश्चित कोई भी अन्य संमिश्रण		0.194	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
7	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	0.194	अम.डॉ.	कि.ग्रा.
8	5504 10	'बांस फाईबर वर्जित विस्कोस स्टेपल फाईबर (वीएसएफ)'	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.194	अम.डॉ.	कि.ग्रा.

135. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमा-शुल्क शामिल होंगे।

136. इस अंतिम जांच परिणाम के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष दायर की जाएगी।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2016

(Final Findings)

Subject: Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre, originating in or exported from China PR and Indonesia

A. BACKGROUND

F. No. 15/9/2015-DGAD.—Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of ‘Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre’ (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Indonesia, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 19th March, 2009, leading to issue of preliminary findings vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 5th August, 2009 and imposition of provisional duty.

2. Whereas, the original final findings were issued by the Authority, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Indonesia vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 17th May, 2010. The definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries vide Notification No. No.76/2010-Customs dated 26thJuly, 2010.
3. And whereas some interested parties filed appeals before the Hon’ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi, challenging the Final Findings dated 17th May, 2010 and the Customs Notification No. 76/2010-Customs dated 26thJuly, 2010.The Hon’ble CESTAT, after extensively hearing the interested parties and the domestic industry, remanded the matter back to the Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and other interested parties, if any, and for making such modifications to the Final Findings as might be necessary as a result of such post decisional hearing. The Authority, vide its Notification No 4/6/2009-DGAD dated 10th April 2012, issued its post decisional Final Findings confirming the Final Findings earlier notified vide Notification No. 14/6/2009-DGAD dated 17th May, 2010.
4. Whereas, the present petition was filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as Petitioner), on behalf of the domestic industry for the product under consideration. One of its members, M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer (hereinafter referred to as Petitioner Company) and provided necessary information for the present purposes.

5. Having satisfied that the petitioner has substantiated the need for a sunset review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/9/2015-DGAD dated 22nd July, 2015. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended up to 25th July 2016 by the Central Government vide Notification No. 37/2015-Customs (ADD) dated 6th August, 2015.

F. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed in this investigation:

- i. The Authority issued a Notification No. 15/9/2015-DGAD dated 22nd July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries on receipt of application to initiate the SSR investigation.
- ii. The Authority sent a letter along with a copy of the notification to all known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject countries in accordance with the Anti-dumping Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.
- iv. Copy of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/ producers in the subject countries were also sent to the embassy of the subject countries in India along with a list of known exporters / producers.
- v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Antidumping Rules:
 1. P.T.South Pacific Viscose
 2. PT. Indo Bharat Rayon
 3. HebeiJigao Chemical Fiber Co., Ltd.
 4. Hubei Chemical Fiber Group Co.,Ltd
 5. Sateri (Jiangxi) Chemical Fibre Co., Ltd.
 6. China Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited
 7. ChtcHelon Co., Ltd
 8. Xinjiang fulida fibre Co., Ltd
 9. Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.
 10. Shandong Yamei Technology Co., Ltd
- vi. Following companies have filed the exporter questionnaire response as a producer/exporter of the product under consideration in India:
 1. Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd, China PR
 2. Tangshan SanyouYaunda Fibre Co. Ltd, China PR
 3. Tangshan Sanyou Group Xinda Chemical Fibre Co., China PR
 4. Birla Jingwei Fibres Co. Ltd., China PR
 5. P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia

6. P.T. South Pacific Viscose (SPV), Indonesia

vii. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known Importers/Consumers/User Associations of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Customs Rules, 1995:

1. Pallava Textiles
2. Pallipalayam Spinners,
3. ShriCheran Syn. India Ltd.
4. KesharMultiyarn Mill Ltd.
5. Ginni Filaments Ltd.
6. Gimatax Industries Pvt. Ltd.,
7. Pee Vee Textiles,
8. RSWM Ltd.
9. Suryalata Spinning Mills
10. Shree Rajasthan Syntex Limited,
11. Spentex Industries Limited (CLC)
12. Rajasthan Textiles Mills Association
13. Northern India Textiles Mill's Association
14. The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTPC)
15. Indian Spinners' Association

viii. Following importers/users responded and filed importer questionnaire response:

1. Suryalata Spinning Mills Ltd.
2. RSWM Ltd.
3. Shree Rajasthan Syntex Ltd.
4. Pee Vee Textiles Ltd.
5. Gimatax Industries Pvt. Ltd.
6. Magnum Spinning Mills India Pvt. Ltd.
7. Indian Spinners' Association

ix. The following importers/users of PUC have also filed submissions/letters during the course of investigation, though without a detailed questionnaire response. Submissions made by these parties have also been taken into account in the present determination.

1. Confederation Indian textile Industry (CITI).
2. Textile Consumer's Foundation
3. The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council
4. Arbind Limited LalBhai Group
5. Spentex Industries Limited
6. Victory Spinning Mills Ltd

- 7. Chola Spinning Mills Private Limited
- 8. Pavathal Spinning Mills Private Limited
- 9. JPP Mills Private Limited
- 10. ArunachalaGounder Textile Mills Private Limited (AGT Mills)
- 11. APM Industries Limited

x. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2014 – March 2015 (12 months). However, injury analysis covered the period April 2011 - March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the POI.

xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. Domestic industry procured import data from secondary source, namely, IBIS, Mumbai. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis.

xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xiv. The Authority held oral hearing on 19th January 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6).

xv. The parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this final finding notification, to the extent considered relevant by the Authority.

xvi. The Authority examined the information furnished by the domestic producer to the extent necessary on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non- injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvii. Verification of the information and data submitted by the applicant was carried out to the extent deemed necessary. The information submitted by responding exporter and importers has been also examined in detail.

xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of the ‘facts available’.

- xx. A disclosure statement was issued on 27.06.2016 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. Time up to 04.07.2016 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority is USD = Rs. 61.69.
- xxii. *** in this final finding notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

G. SCOPE OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND ‘LIKE ARTICLE’

Submissions by the Domestic Industry

7. Views of the domestic industry on product under consideration are as follows:
 - a. The product under consideration in the present investigation is ‘Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre’ which is widely used in textile industry, mainly in fashion wear, home furnishings and carpets, household textiles and for medical uses. It can broadly be divided into two forms - normal viscose fibre and modal fiber/micro modal fiber. Viscose fibre is produced in large number of deniers. However, cost and price of different deniers do not differ significantly.
 - b. Goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable.
 - c. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504 10 00. Since the goods are imported under many other HS codes, the Customs classifications are indicative only.
 - d. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules.

Submissions by the Opposing Interested Parties

8. The product under consideration should have been segregated into different types based on deniers etc. and then analysis for the purpose of dumping margin, price undercutting and injury margin analysis should have been carried out as per PCN types.
9. It has been submitted that none of the exporters from the subject countries are producing and/or supplying modal fiber/micro modal fiber to India or in the domestic market. Since the exports from the subject countries are not competing with the said products, the same cannot possibly be the cause of the alleged injury to the applicant industry. Therefore, modal fiber/micro modal fibres cannot be considered as “like articles” to the imported goods for the purpose of injury analysis.

Examination by the Authority

10. The product under consideration in the present investigation is “Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre”. The product is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 550410. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.
11. The present petition is for sunset review of the anti-dumping duty earlier imposed. The product under consideration considered by the Authority in the original final findings is as follows:

D. Product under Consideration and Like Article

“The product under consideration is “Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre”. Viscose Staple Fibre is described as “Viscose rayon staple fibre not carded/combed” under the Customs Tariff and is also known as “Rayon Fibre” in some markets. The product under consideration is

classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Viscose Staple Fibre was the first man-made fibre, and unlike other man-made fibres, is not a synthetic fibre. It is made through wet spinning technology and is a regenerated cellulose fibre made from wood pulp, which is essentially cellulose extracted from a sustainable natural resource i.e. wood, by subjecting it to various chemical and mechanical processes. On account of its cellulosic base, viscose staple fibre properties are similar to those of natural cellulosic fibres than those of thermoplastic, petroleum based synthetic fibres such as nylon or polyester. Further, it has a distinct advantage of engineered specification and uniformity. Viscose Staple Fibre has silk-like aesthetic with superb drape, soft feel and retains rich brilliant colours. Fabrics made from it are moisture absorbent (even more than cotton), breathable, comfortable to wear, and easily dyeable in vivid colours. They do not build up static electricity, and are pill-resistant.

Main strength of VSF is its versatility and ability to blend easily with nearly all other textile fibres to impart lustre, softness, absorbency and resulting comfort to the fabric made from such blends. Bamboo fibre, one of the types of Viscose Staple Fibre is excluded from the scope of this investigation. In the initiation notification, Designated Authority has specifically requested the interested parties to make their submissions with regard to exclusion of Bamboo Fibre. None of the interested parties had made any submissions in this regard.”

12. During the investigation, P.T. South Pacific Viscose (SPV), Indonesia had contended that the authority should have segregated different types of the product under consideration into different PCN (Product Control Number) types for the purpose of dumping margin, price undercutting and injury margin analysis. However, at the time of spot verification at the premises of the exporter, the exporter was asked to justify its request for PCN wise analysis. The exporter was also asked whether the producer exporter maintains or can otherwise provide separate PCN wise cost of production details for different types of VSF produced and sold. The exporter however categorically clarified that the exporter does not maintain records which can segregate cost of production for different kinds of fibres. The exporter also claimed that the exporter does not consider that there were significant differences in the cost of production of different types of fibres.
13. The Authority has compared the regular (normal) Viscose Staple Fibre produced by the domestic industry compared with the normal imported fibres for dumping margin, price undercutting and injury margin determination. DI has clarified that only VSF Fibre was being produced in its Vilayat Plant during POI. The import of VSF waste has also not been considered for analysis purposes as it is not covered within the scope of PUC.
14. The Authority concludes that no substantive issue has been raised by any interested party regarding the scope of the product under consideration, and since the present investigation is a sunset review, the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as the scope of the product in the final finding of the original investigation.

H. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

15. Views and response of the domestic industry on domestic industry & standing are as follows:
 - a. The present petition was filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (AMFII) on behalf of the domestic industry. One of its members, M/s Grasim Industries Limited is the sole producer of the subject goods in India and may be considered as the domestic industry.
 - b. The fact that the petitioner is the sole producer of the product under consideration in India does not affect the standing of the petitioner as domestic industry. There is no other known producer of VSF in India and hence the production by petitioner constitutes 100% of the Indian production. Also, the Panel in the matter of imports of Cotton-type bed linen from India held that the plural form used in the AD agreement includes the singular case.

c. The applicant has affiliated companies in China PR, Indonesia and Thailand, producing & selling the product under consideration globally. The relationship amongst these entities is as below:-

1.	Grasim Industries	Domestic industry in the present case
2	Birla Jingwei Fibres Company Limited, China PR	An Aditya Birla Group Company. 26.63% is held by Grasim Industries Ltd, 42.53% is held by Thai rayon Public Company Ltd, Thailand and 30.84% is held by PT Indo Bharat Rayon, Indonesia
3	PT Indo Bharat Rayon, Indonesia	An Aditya Birla Group Company, 5% is held by Grasim Industries Ltd.
4	Thai Rayon public Company Limited, Thailand	An Aditya Birla Group Company and listed on Thai Stock Exchange. 6.99% is held by Grasim Industries Ltd.

d. The applicant has furnished the details of all related entities and the basis on which these companies are related. The affiliated producers are largely selling their products either in the respective domestic markets or exporting to third countries.

e. The affiliated company in China has not exported the PUC to India. The Indonesian Company has also not exported the PUC to India during POI but exported a small quantity of VSF waste to India, which is insignificant and not covered within the scope of PUC. Therefore, the Authority has rightly considered that the applicant should not be considered ineligible under the Rules, as was also established in the original investigation.

f. The domestic industry has a plant in Thailand which has exported one of the forms of the product under consideration to India called modal/micro modal fibre. Imports from non subject countries are in any case not relevant in order to determine whether a domestic producer qualifies as domestic industry in view of relationship with the foreign producer/exporters. CESTAT has held in the mattes of Birla Ericsson Ltd. v/s Designated Authority that the issue of relationship is required to be examined only in the context of subject countries. Thailand is not a subject country in the present case so the imports from Thailand are not relevant for the purpose of Rule 2(b). The import price from Thailand and Europe are much higher than the import price from China and Indonesia.

g. Domestic industry has provided complete details of exports from the three related companies PT Indo Bharat Rayon, Indonesia, Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and Thai Rayon, Thailand to various parties in the domestic and international markets. PT Indo Bharat Rayon, Indonesia and Birla Jingwai Fibres Company Limited, China in particular have provided invoice by invoice details of their exports to Thailand and exports of VSF from Thailand to India

h. The use of the word ‘may’ in Rule 2(b) suggests that the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product are not automatically excluded from being part of the domestic industry. Rather, it is the consistent practice of the investigating authorities that the exclusion of such producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.

i. The production of petitioner constitutes a major proportion of total domestic production of subject goods in India. Thus, the present petition satisfies the standing requirement under the Rules to file the present petition and petitioner constitutes ‘domestic industry’.

j. Present petition is for sunset review. This being sunset review investigation, the Authority is not required to ascertain standing of the petitioner to file the present petition.

- k. Responding to the contentions of other interested parties with regard to decision of the Designated Authority in other case, the domestic industry has submitted that in SDH transmission case, the Authority had to exclude Huawei for the reason that Huawei, China had exported the product to India and was thus related to Huawei India who claimed status of a domestic industry. In the present investigation, there are no exports by related entities in the subject countries to India in the present POI. In Soda Ash case (a) Tata chemicals was treated as ineligible domestic industry in view of exports made by related parties, (b) GHCL, Nirma and Saukem were treated as eligible domestic industry despite export made by related entity. Further, in Soda Ash case, the exports were by related parties from subject countries. In the instant case the exports are by related party in countries not under investigation..
- l. In SDH transmission case, the Authority had to exclude Huawei India for the reason that Huawei, China had exported the product to India and was thus related to Huawei India who claimed relationship. In the present investigation, there are no exports by related entities to the related companies in the subject countries in the present POI.
- m. WTO has clearly held in its judgement that even if there is one sole producer of PUC, the same shall constitute domestic industry. It has been held by WTO that in use of the word in plural form implies inclusion of the word in its singular form.
- n. There is no legal requirement of disclosure of related parties in third countries. Third country imports are neither dumped imports nor under investigation. There is no attempt to circumvent the ADD imposed in India by the Thai related party. The imports from Thailand are of modal fibre, for which DI did not have sufficient capacities in the country during that period.
- o. In Soda Ash case (a) Tata chemicals was treated as ineligible domestic industry in view of exports made by related parties, (b) GHCL, Nirma and Saukem were treated as eligible domestic industry despite export made by related entity. Further, in Soda Ash case, the exports were by related parties from subject countries. In the instant case the exports are by related party in countries not under investigation.
- p. Domestic industry supplied material to a domestic customer who produced the product and exported the eventual product. All export benefits on such exports have been taken by the customer only. Also, domestic industry gave additional benefit to the consumer. If domestic industry were to sell the entire product at these prices for all domestic sales, they would have suffered significant financial losses. Domestic industry therefore charged differential price for such sales. To ensure that this mechanism is not misused by customers, domestic industry has evolved a system to ensure that the consumers get these special prices only for that production which is meant for exports. These sales are clearly domestic sales so in any case cannot be taken out from the calculations.
- q. Neither there was any attempt to circumvent the anti dumping duty imposed in India, nor has the Thai related party exported the product in order to circumvent the anti dumping duty. In fact imports from Thailand are of modal fibre, for which domestic industry did not have sufficient capacities in the country.
- r. Thai Rayon has not imported from Indonesia or China for export to India. This is mere allegation and conjecture.

Submissions by the Opposing Interested Parties

16. Views of the opposing interested parties on domestic industry & standing are as follows:

- a. M/s Grasim Industries Ltd. does not have a standing as domestic industry for the present investigation as they have related entities in both China and Indonesia, namely PT Indo Bharat Rayon, Indonesia and Birla Jingwai Fibres Co. Ltd, China.

b. SPV has submitted that the applicant ought to be considered as ineligible Domestic Industry not only on account of their ownership structure but also on account of the fact that their inter-linkages allow them to manipulate the market in India. This is further proved by the fact that they have even shared their confidential data amongst themselves. SPV has also questioned the claim of confidentiality by the applicant industry as, according to them, confidentiality cannot be claimed qua individual parties. It is further submitted that the related entities of applicant industry in subject countries namely PT Indo Bharat Rayon (IBR), Indonesia and Birla Jingwei Fibers Company Limited, China are represented by common representative.

c. It has been further submitted that the fact that no submissions were made during the public hearing on behalf of related exporters of the applicant industry, despite there being a common representative, confirms the apprehension of SPV that the whole application has been cleverly managed to oust genuine competition and to provide a sanctuary market to the applicant's own subsidiaries. They further requested the Authority that the commercial realities have to be recognized before the Authority exercises its discretion under Rule 2(b).

d. Further, it has been submitted that M/s Grasim Industries Ltd. should not be considered as domestic industry by virtue of being the sole producer of Viscose fibre in the country.

- (i) Domestic industry has been defined to consider "domestic producers" in plurality to exclude a sole oligopolistic producer from its definition (Rule 2(b) of AD Rules). While defining domestic industry, the plural reference to domestic producers should not be construed for a single entity to be considered as domestic industry. Singularity on account of exclusion from domestic industry or exclusion for administrative purposes by the authorities or unavailability of data is an acceptable reason. But, where a single oligopolistic producer is considered to constitute domestic industry, this would void the provisions under rule 5(3)(a) and 5(3)(b).
- (ii) Legal jurisprudence in Indian cases mentioned by the petitioners have not fully addressed this issue. The issue has been discussed further in EC-Bed Linen case Para 6.72 where a single producer can form DI by virtue of exclusion or non availability of data ONLY.
- (iii) The intent of the law in defining domestic producers in "plurality" was to protect the industry at large and not grant a sole producer unfair pricing mechanism in India.

e. The fact of exploitation of domestic consumers by Grasim has been established in a Judgment of the Hon'ble CCI [WP(C) No.4159 of 2013Delhi (HC)].

f. Indian Spinners Association has submitted that Grasim must not be considered eligible "domestic producer" for the purposes of the AD rules because:

- i. The domestic industry deliberately did not disclose full facts of a related exporter namely, Thai Rayon which is the sole producer of VSF in Thailand
- ii. 100% of the imports from Thailand have been made from Thai Rayon (related manufacturer of Grasim).
- iii. The related exporter has exported goods to India only after anti dumping duties were imposed on Indonesia and China. The quantum of imports from Thailand has increased slowly and steadily to reach 11% of total imports of subject products in India in 2014-15.
- iv. Thai Rayon has purchased materials from related companies in Indonesia and China and exported fiber to India in the same accounting year.

- v. The quantum of imports from Thai Rayon constitutes 1.25% of the total domestic sales of Grasim, which is deemed to be significant considering that the petitioner alleges that imports below 1% (from China) are significant in causing injury.
- vi. The imports from Thai Rayon are at prices which *prima facie* indicate undercutting and dumping as compared to imports of similar products from Austria.
- vii. Together with the fact that Grasim's related company has exported subject products to India and that Grasim has been accused of controlling the domestic market by means of its dominant position in India to stifle competition within the country, exclusion under Rule 2(b) is warranted.
- viii. ISA requests comparison of current position / operations of the petitioner against the rules laid down by DA in the original investigation for determination of eligibility of petitioner as DI. The Thai Rayon is controlled by a common Executive Director (Shri K.K Maheshwari) and common Chairman. It commands 11% of total imports of VSF into India during the period of injury, whereas imports of 0.25% from China are claimed significant by the petitioners. Grasim had stopped manufacturing of Modal VSF fiber in existing plants and turned to imports from Thai Rayon only. It envisages manufacturing of such fiber in Vilayat plant. Grasim has imported the product concerned through Thai Rayon as marketing and operations are headed by common director and Business Head. Thai Rayon's CIF export prices into India are lower than the domestic prices of Modal fiber in India.
- g. Similar exclusion of domestic producer has been made in case of Soda Ash from Kenya and 6 other countries (No 14/17/2010-DGAD), where 100% of the exports from Kenya were made by a related company of a domestic producer, imports ranging from 8 to 10% of total imports were considered significant. Another such example is the decision of the DA in case of Certain Tiles from China.
- h. SPV has submitted that it is an admitted position of the Authority that they can re-examine the eligibility of the applicant industry even in the sunset review investigation. In this connection, they have relied on the counter affidavit filed by the DGAD before the Hon'ble High Court of Delhi on 29.8.2013 in the matter of Indian Council of Ceramics Tiles & Sanitary ware Vs Designated Authority &Anr. WP No. 4160/2013, wherein, the Authority has stressed the importance of reexamination of the eligibility of the applicant industry even in the sunset review investigation.
- i. They further submitted that as per the current practice of the Authority, as revealed from some of the recent investigations, the Authority is rejecting those domestic producers who are related to importers or exporters. In this context, reliance has been placed on the investigations of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment against China PR wherein the authority rejected the claim of one of the domestic producer namely Huawei Telecommunications (India) Co. Pvt. Ltd. (Huawei India) as a domestic industry only because they are related to exporter and imported themselves. Further, in the case of Vitrified Tiles from China, the Authority has even excluded those domestic producers who have mere relationship with exporters or importers of the subject goods.
- j. In view of the above, SPV submits that there is no legal or logical reason for the authority to treat applicant industry as eligible domestic industry. Accordingly, they have requested for termination of the investigation on this ground.

Examination by Authority

17. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to standing of petitioner and considered relevant by the Authority are examined and addressed in terms of Rule 2 (b) of Anti-dumping Rules.
18. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

19. The application was filed by Association of Man-Made Fibre Industry of India (AMFII) on behalf of the domestic industry. One of its members, M/s Grasim Industries Limited is the sole producer of the subject goods in India and submitted all relevant information for the petition.
20. It has been submitted by opposing interested parties that as per Rule 2(b), Grasim Industries doesn't have a standing as domestic industry because they have related entities in China, Indonesia and Thailand. The authority notes that the question of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of practical importance. The root question is whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. The Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides discretion to the Designated Authority which could be applied on case by case basis in such situations where one or more domestic producers have imported the product under consideration or is related to an importer or exporter of the product under consideration.
21. The authority recalls in this connection that at the time of original investigation, the issue had been dealt with in detail. The domestic industry was comprised of M/s. Grasim Industries Ltd. who had a related entity namely P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia, exporting the PUC to India during the then prevailing POI. After elaborate investigation, the authority concluded that Grasim Industries constituted domestic industry notwithstanding its relationship with one of the exporters in subject countries. The decision of the Designated Authority in that investigation has now attained finality. The authority had considered all facts in detail and found it in fitness of things to determine individual dumping margin and anti-dumping duties in respect of P.T. Indo Bharat Rayon and the company is at present attracting anti-dumping duties. The Authority noted that mere fact of relationship of a domestic producer with an importer or exporter or import by such a producer is insufficient to exclude such a producer from the scope of the domestic industry.
22. In the present review investigations, the facts have changed to the extent that there are no exports of the PUC by the related exporter in Indonesia to India. The Authority notes that the legal and relevant requirement in this regard is whether or not there are exports by the related entities in subject countries in the investigation period. Further, exports by related entities in subject countries made prior to the investigation period are also not relevant to disentitle such domestic producers from the scope of the domestic industry. Therefore, the Authority notes that mere fact of relationship of a domestic producer with an importer or exporter is insufficient to exclude such a producer from the scope of the domestic industry.
23. The Authority further notes that the exports made by related companies from non- subject countries are entirely irrelevant for present investigation. The CESTAT has held previously in the matters of Birla Ericsson Ltd. vs Designated Authority that the relationship with importer or exporter or imports by petitioner domestic industry is relevant (a) in the context of POI and (b) for imports from subject countries only. Imports from non-subject countries and imports prior to investigation period have no relevance in this regard.
24. The authority also notes that the Rule 2(b) in its relevant part provides that when such producers who are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof, such producers may be deemed not to form part of domestic industry. Thus, the Rule 2(b) clearly refers to "alleged dumped article", which can only mean product under consideration from subject countries only. Goods imported from countries not under investigation is not "alleged dumped article".

25. The Authority holds that as per the data furnished by the domestic industry, PT Indo Bharat Rayon, Indonesia, Birla Jingwai Fibres Company Limited, China, importers in India who filed Importer's questionnaire responses, DGCI&S data and investigations conducted by the authority, including spot verifications, there were no exports of the Viscose fibre by the related entity in China by PT Indo Bharat during the POI. There were small quantity of export of VSF waste from Indonesia to India during the POI, which is insignificant compared to total imports and also negligible with reference to Indian production, also VSF waste is beyond the scope of the product under consideration. Evidence on record shows that its import was cleared by the customs authorities without collection of anti-dumping duties, thus treating this as product not under consideration. Further, the volume of these imports is quite small.

26. As regards exports by Thai Rayon, Thailand, the authority notes that Thailand is not a subject country in the present case. As far as relationship of the petitioner with the Thai exporter is concerned, the submissions made by the interested parties are relevant only when the relationship is disputed. Relationship of the petitioner with the Thai exporter has not been disputed by the petitioner. However, there is no evidence on record to show that exports made from Thailand are at dumped prices. The information on imports contained in the petition, the DGCI&S data procured by the authority and information on exports from Thailand provided by the petitioner clearly shows that majority of these exports were of modal fibre and at a price much higher than the import price from China/Indonesia. The authority holds in this regard that mere fact of exports by related entities is wholly insufficient in this regard. In this regard the authority also recalls its elaborate determination in the original investigation wherein the authority has extensively examined the impact of relationship on scope of domestic industry under Rule 2(b).

27. Some interested parties have contended that the authority should re consider the standing and scope of domestic industry at the time of sunset review. Reference to submissions by the authority before Delhi High Court has been made in this regard. The authority holds in this regard that the authority has not stated that standing or scope of the domestic industry will not be examined in the present case. The authority has in fact examined standing requirements and has determined whether the petitioner company constitutes domestic industry in the present case.

28. Having regard to definition of Rule 2(b), past determinations made by the authority in other investigations and original investigation in the present case, decisions of the CESTAT and considering the facts on record of the present case, the Authority considers that there is no justification to consider Grasim Industries as ineligible domestic industry under Rule 2(b) of the Antidumping Rules.

29. An issue has been raised by the opposing interested parties that the petitioner being the sole producer cannot constitute domestic industry. The Authority notes that the placement of a word in plural form implies existence of more than one producer. The authority has routinely considered sole producer as domestic industry under the law. The authority also notes in this regard that the WTO Appellate Body in the matter of anti-dumping duties on the imports of Cotton-Type Bed Linen from India in particular held that a sole producer can constitute domestic industry.

30. The opposing interested parties have also contended regarding non-disclosure of full facts about Thai Rayon, Thailand which is a related entity to the domestic industry. The Authority notes that the only legal requirement in this regard is with regard to disclosure about related parties in subject countries. There is no such requirement for related parties in third countries. Third country imports are neither dumped imports nor under investigation and do not constitute alleged dumped product. It is also noted that the domestic industry has provided all relevant information in this regard. The domestic industry has also provided complete details of exports made by Thai Rayon, Thailand not only to India but also to third countries. The authority therefore does not consider that the Petitioner had any intentions to suppress the facts.

31. As regards the exclusion of domestic producer in the case of Soda Ash from Kenya, etc., the Authority is of the view that the facts of the cited case were completely different from the current investigation as far one of the domestic producers is concerned who was treated ineligible domestic industry. In Soda Ash case, (a) the exports were by related parties from subject countries in the POI, (b) in quite significant volumes as far as Tata Chemicals is concerned and (c) insignificant volumes as far as Nirma and Gujarat Heavy Chemicals are concerned. The authority treated Tata Chemicals as ineligible domestic industry and Nirma and Gujarat Heavy Chemicals as eligible domestic industry. In the instant case, the exports are by related party but from country not under investigation. Further, authority's decision in soda ash case with regard to Nirma and Gujarat Heavy Chemicals to treat them as eligible domestic industry further supports the contention of the petitioner that Grasim Industries cannot be treated as ineligible domestic industry in the present case.

32. As regards SPV contention that the applicant ought to be considered as ineligible Domestic Industry not only on account of their ownership structure but also on account of the fact that their inter-linkages allow them to manipulate the market in India, the authority holds that there is no substance in the contention. The fact that the Indonesian producer and Petitioner have shared their confidential data amongst themselves is entirely irrelevant to the present issue. The authority also notes that the facts in this regard in the present case are the same as facts that had prevailed at the time of original investigation.

33. As regards contention that the efforts of the applicant is to provide a sanctuary market to the applicant's own subsidiaries, the authority notes that the exports made by the related producers in Thailand, Indonesia and China is without any specific evidence and tantamount to a conjecture. Moreover, the authority has made determination on non-discriminatory basis and recommends anti-dumping duty on all sources wherever dumping causing injury is established.

34. Interested parties have referred to the decision of the CCI. The authority however notes that there is no final decision from the CCI. Moreover, the Hon'ble Supreme Court in the matter of Haridas Exports Versus All India Float Glass Mfrs. Association [2002 (145) E.L.T. 241 (S.C.)] held that the jurisdiction of the MRTP Commission is not ousted by the Anti-dumping provisions in the Customs Act and the two Acts operate in different fields and have different purposes. Even though the said decision is in the context of MRTP Act, the same is nevertheless guiding to the present case also. If there are any possible contraventions of the provisions of Competition Act, the provisions of the said act would prevail and it is for the appropriate authority to take appropriate action thereon. The jurisdiction of the Designated Authority is with regard to possibility of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the product under consideration, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry and whether anti-dumping duties are required to be extended.

35. The authority also notes that the documents on record show that investigation by the CCI was initiated on the basis of an allegation but the DG did not find any substance under Section 3 of the Competition Act, 2002.

36. In light of the above, the Authority holds that the petitioner satisfies the requirement of standing to file the present petition and constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the AD Rules.

I. CONFIDENTIALITY ISSUES

Submission by the Domestic Industry

37. The DI has submitted all the relevant information as required and prescribed by the Authority. While dealing with issue of confidentiality, the interested parties conveniently ignore to refer to the submissions made by other interested parties. The Authority must compare the confidentiality claims by the domestic industry and the confidentiality claims made by the opposing interested parties in order to conclude regarding the issue of confidentiality.

Submissions by opposing interested parties

38. The submissions made by Indo Bharat Rayon, Indonesia &Birla Jingwai Fibres Company Limited, China do not provide sufficient details for providing a reasonable understanding of the non-confidential information submitted. For example the product flow chart, transaction wise domestic sales, details of waste exported to India, details of exports to third countries, sales of PUC by company, operating statistics, statement of capacity, production, sales and stock, statement of consumption of raw materials , statement showing raw materials consumption, allocation of expenditures, cost of production for export and domestic market and statement showing selling, general and administrative expenses were not provided in adequate details for comments by interested parties.

Examination by the Authority

39. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- a. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule12, sub-rule (4) of rule 15 and sub rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that their request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

- b. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
- c. As regards submission on non-disclosure of certain injury parameters, the Authority notes that the same were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim and upon being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims. The domestic industry had provided indexed information of the injury parameters which could not be disclosed on actual basis. The authority notes that if an interested party is not obliged to publicly disclose some information and if such interested party considers that such information constitutes confidential business information, the authority cannot direct such party to nevertheless disclose such information.

J. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by the domestic industry

40. Views of the domestic industry in this regard are as follows:

- a. As regards difference in dumping margin in case of related entity and other producer at the time of original investigations, the dumping margin in those transactions is entirely immaterial for the purposes of present investigations. Exports made by the related entities were not in such volumes or under such conditions as to exercise the discretion and exclude the company as ineligible domestic industry. Also there is no export of PUC by related Indonesian party during the present injury period including the POI.
- b. Indian Spinners' Association cannot claim itself as an Association of consumers of PUC. Majority of the members of the Indian Spinners' Association are consumers of other fibres such as Polyester and Cotton. They are not consumers of Viscose. In fact in overall context, consumption of VSF in the country is far lower than the consumption of Cotton and Viscose.
- c. The DI is giving a variable price to the downstream industry depending on the end use of the material for domestic use or exports. Therefore, the manufacturer exporters are being offered a discounted price to keep their competitive edge intact.

Submissions by the opposing interested parties

41. Views of the opposing interested parties in this regard are as follows:

- a. The dumping margin for the related exporter of the domestic industry is almost twice of the other cooperating exporter from Indonesia. Indian producer and its subsidiary in Indonesia have colluded to ensure that the other competitors are first forced to lower their prices and then the Indian arm brings an anti-dumping investigation with the sole objective of blocking fair competition in the Indian market.
- b. Majority of the members of Indian Spinners' Association are the consumers as well as importers of VSF. Also, Indian Spinners' Association was an interested party in the original proceedings and since this is an SSR, *ipso facto*, Indian Spinners' Association should be a party to the current investigations.
- c. The members of Indian Spinners' Association increased their capacity but relatively lower than Grasim in the past 4 years. It faces lack of competitiveness in international markets due to the higher prices of domestically procured VSF from Grasim and the continuous imposition of anti-dumping duty on imports of viscose yarn in India.
- d. The petitioner is indulging in different pricing policy for overseas market and domestic market; they are also differentiating between customers who are manufacturers for domestic consumption and manufacturers exporters. This is causing hardship to everyone involved. The textile spinners are getting fibres at higher price as compared to overseas market thus taking away the competitive edge. On the other hand differential pricing is attracting ADD measures on Indian exporters as the investigations by importing countries prove that there are two different prices of raw material for domestic and export supplies.

Examination by the Authority

42. The specific submissions made by the opposing interested parties and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

- a. As regards to the submission of the opposing interested parties concerning the dumping margin for the related exporter of the domestic industry during original investigations, the Authority holds that the dumping margin is based on actual facts of a case. If the dumping margin for a party was found higher, the authority had recommended higher quantum of anti-dumping duty (subject to application of lesser duty law) accordingly. The authority however finds no merits in the argument that because the Petitioner is related to an Indonesian producer; the two have colluded to dump the product. The authority had considered this issue in the original investigation as well. During the present POI, there are no exports of PUC to India by the related exporters in

subject countries. The exports made during original investigations are not relevant for the present review investigations.

- b. As regards to the submission of the opposing interested parties concerning the issue regarding the *locus standi* of Indian Spinners' Association as an interested party, the Authority is of the view that as the majority of the consumers of the Indian Spinners' Association are spinners using fibers such as Polyester, Viscose and Cotton, the Authority admits the association as an interested party for the present investigation.
- c. As regards to the submission of the opposing interested parties concerning non competitiveness of spinners in international market on account of expensive raw materials, the Authority notes that with regard to the adverse impact on exports, the Govt. of India has exempted imports for exports from the preview of anti dumping duty. Also the interested parties have not disputed the claim of the domestic industry that the domestic industry is offering a differential pricing for material meant for domestic consumption versus the material meant for export consignments. This takes care of the supplies at competitive prices for manufacture of export productions. The ADD investigations against Indian exporter in other countries is a phenomenon of dumped goods by the manufacturer exporters of finished goods and not caused by differential pricing which is a common practice in many countries across various sectors.

MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

K. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Normal Value

43. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

CHINA PR

44. Views of the domestic industry on determination of normal value for China are as follows:

- a. China PR should be treated as nonmarket economy country for the following reasons:
 - i. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
 - ii. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.

- iii. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
- iv. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. Contrarily, while examining material injury existence of a single parameter is considered sufficient to establish such injury. In other words, where one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.
- v. It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- vi. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- vii. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

b. It has been submitted that the normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules without invoking proviso to 8(2) in view of the aforementioned facts and circumstances.

c. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. It is also submitted that since these options for determination of normal value are available, the Designated Authority may not kindly consider "any other basis" because this is required to be applied only when other basis listed under the law cannot be applied.

Examination of claim of MET for China PR

45. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to determination of normal value and considered relevant by the Authority are examined and addressed in terms of 9A(1)(c) of Anti-dumping Rules.
46. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; the exporters from China namely, Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd., Tangshan Sanyou Group Xinda Chemical Fibre Co., Tangshan SanyouYaundaFiber Co. Ltd., and Bharat Jingwei fibres Co. Ltd. responded. These parties have provided information in the form of manner prescribed in both the questionnaires prescribed for a sunset review. The responding Chinese exporters have not claimed market economy treatment and therefore have not filed market economy treatment questionnaire responses.
47. None of the exporters from China PR have filed the MET questionnaire response and therefore the Designated Authority could not consider whether a Chinese producer could be granted market economy treatment in accordance with para 8 of Annexure-I.
48. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of Injury) Rules, 1995, the presumption of

a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s) /producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/ producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/ sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:-

- i. *The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*
- ii. *The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*
- iii. *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and*
- iv. *The exchange rate conversions are carried out at the market rate.*

49. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd, China PR claiming that the company is an exporter of the product under consideration produced by its related company M/s Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co. Limited. The company has claimed export of the product under consideration to India during the investigation period. The data filed by the exporter in their questionnaire response was verified, the individual dumping margin has been determined by the Authority for Tangshan Sanyou Group. Hong Kong International Trade Co. Ltd is mentioned in dumping margin table below.

50. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Tangshan Sanyou Group Xinda Chemical Fibre Co., China PR claiming that the company is a producer of the product under consideration and has exported the same to India through its related company namely Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited.

51. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Tangshan SanyouYaunda Fibre Co. Ltd, China PR claiming that the company is a producer of the product under consideration. The company has claimed no export of the product under consideration to India during the period of investigation. Therefore, the Authority considers that there is no case to determine individual dumping margin for Tangshan SanyouYaunda Fibre Co. Ltd, China PR.

52. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Bharat Jingwei fibres Co. Ltd, China PR, a related company of Grasim Industries Ltd. India, claiming that the company has not made any export to India during the POI or any period before and after that. Therefore, the Authority considers that there is no case to determine individual dumping margin for Bharat Jingwei fibres Co. Ltd, China PR

53. China has been treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China has been treated as non-market economy country in India also. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules, if none of the producers in China claim and establish their treatment as market economy company in terms of provisions of Para 8 of Annexure I. For the ready reference the provisions of Para 7 are quoted below:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable

basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

54. Since China is being considered as Non Market Economy, the Rules provide that the normal value for China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

55. In view of the fact that the exporter/producer from China PR has not claimed market economy treatment, the Authority has not granted the Market economy status to all the exporters/producers of China PR. Further, none of the interested parties have suggested a market economy third country as an appropriate third country for the present purposes. The opposing interested parties have also not provided any information or evidence to determine normal value on the basis of market economy third country. The Designated Authority has constructed the normal value in China on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Authority has determined the Normal Value for the subject goods exported by all exporters in China for each product type as below.

Name	Normal Value USD/Kg
Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co., Ltd (Producer) & Tangshan Sanyou Group Hongkong International Trade Co., Ltd (Trader)	***
All other exporters/producers	***

Normal Value for Indonesia

Normal value in case of Indonesia has been determined on the basis of prices in Indonesia.

PT. South Pacific Viscose (SPV)

56. PT. South Pacific Viscose filed a questionnaire response containing details of the domestic as well as exports sales of the subject goods manufactured and sold by them. For computation of Normal Value, the domestic sales of the subject goods were considered based on the verified data in Appendix -1. The respondent has furnished information relating to cost of production in Appendix 5 to 9. It was noted that there are some inconsistencies in the response with regard to the statement by SPV that they make direct exports to end users and traders in India. However, during verification it was clear that SPV is not doing marketing of subject goods in India, rather the parent company Lenzing AG has a marketing office in India who undertakes the marketing and after sales service and is paid commission on each and every transaction of SPV in India. Similarly, SPV had declared that the company had not purchased any raw material from its affiliated companies, however, it is clear from the statement in another submission that total quantity of wood pulp has been bought from their affiliated company viz. Pulp Trading GMBH. As regards the sales in the domestic market by the company, it was stated that ***% of the subject goods

have been sold to the non-affiliated parties. It was verified that ***% of the domestic sales are profitable sales and the same have been considered for the purpose of determining the Normal Value. Adjustments namely Freight Expenses, and Credit Expenses, as claimed were allowed by the Authority. The Normal Value at ex-factory level as worked out by the Authority taking into consideration the above factors is as below.

Name	Normal Value USD/Kg
PT South Pacific Viscose	***

PT. Indo Bharat Rayon

57. P T Indo Bharat Rayon from Indonesia has responded and provided information in the form and manner prescribed. The respondent has furnished information relating to domestic sales in Appendix 1. The respondent has furnished information relating to cost of production in Appendix 5 to 9 of the Questionnaire. The Authority notes that the respondent has made losses on overall basis on its domestic sales. The company has further claimed that no export of the product under consideration was made to India during the period of investigation. The facts were duly verified with the original documents. Therefore, the Authority considers that there is no case to determine individual dumping margin for P T Indo Bharat Rayon, Indonesia.

Normal Value for all other exporters from Indonesia

58. The Authority notes that no other exporter/producer from Indonesia has responded to the Authority in the present investigation. The Authority, therefore, has determined the normal value for the cooperating exporter from Indonesia, for all other exporters as well.

Export Price

Export price for the responding producers/exporters from Subject Countries

China PR

Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd, China PR

59. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd, China PR has exported subject goods to India produced by its related company M/s Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co. Limited during the POI. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, credit costs, commission, port expenses, VAT difference (only for China PR) and quantitative discount on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and the related producers. After making the acceptable adjustments, the Authority has determined weighted average net export price during the POI as mentioned in the dumping margin table below.

Tangshan Sanyou Group Xinda Chemical Fibre Co., China PR

60. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that Tangshan Sanyou Group Xinda Chemical Fibre Co., China PR is a producer as well as exporter of the subject goods to India during POI. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, credit costs, commission, port expenses, VAT difference (only for China PR) and quantitative discount on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and the related producers. After making the acceptable adjustments, the Authority has determined weighted average net export price during the POI as mentioned in the dumping margin table below.

Tangshan Sanyou YaundaFiber Co. Ltd, China PR

61. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that Tangshan Sanyou Yaunda Fiber Co. Ltd, China PR did not export subject goods to India during the POI.

Bharat Jingwei fibres Co. Ltd, China PR

62. Based on the information furnished in the EQ responses, the authority notes that the Bharat Jingwei fibres Co. Ltd, China PR, a related company of Grasim Industries Ltd. India, has not made any export to India during the POI or any period before and after that. Therefore, the Authority has not determined any export price for them.

Indonesia**PT. South Pacific Viscose, Indonesia**

63. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that PT. South Pacific Viscose, Indonesia is a producer as well as exporter of the subject goods to India during the POI. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, marine insurance, credit costs, commission, port expenses and quantitative discount on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and duly verified. After making the acceptable adjustments, the Authority has determined weighted average net export price during the POI as mentioned in the dumping margin table below.

PT. Indo Bharat Rayon, Indonesia

64. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that PT. Indo Bharat Rayon, Indonesia did not export subject goods to India during the POI. Therefore, the Authority has not determined any export price for them.

Export price for the Non-Co-operative producers-exporters from Subject countries

65. The Authority has determined the Export Price in respect of non-cooperative exporters from the subject countries as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. Accordingly, after making the due adjustments, the weighted average net export price at ex-factory level in respect of all non-co-operative exporters from the subject countries is determined as mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

66. The dumping margin for various producers/exporters is as follows:

<u>Dumping Margin</u>					
Producer/Exporter	Normal Value US\$/Kg	Export price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin %	Range
Indonesia					
PT South Pacific Viscose	***	***	***	***	0-10
All Other exporters/ producers	***	***	***	***	40-50
China PR					
Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co., Ltd (Producer) & Tangshan Sanyou Group Hongkong International Trade Co., Ltd (Trader)	***	***	***	***	20-30
All other exporters/ producers	***	***	***	***	30-40

67. The dumping margins from Indonesia and China are positive.

L. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions by domestic industry

68. The submissions made by the Domestic Industry with regard to injury and causal link are as follows:

- a. Imports of the product under consideration from Indonesia have shown significant increase in absolute terms and in relation to production and consumption in India. As far as imports from China are concerned, they have declined because of the imposition of anti-dumping duty.
- b. Imports of the product under consideration from Indonesia and China are undercutting the prices of the domestic industry in the market.
- c. Imports of the product under consideration are having significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- d. Performance of the domestic industry has shown improvement in terms of production and sales volume. However the domestic industry is unable to increase its sales in proportion to increase in demand and imports.
- e. Profits of the domestic industry have declined significantly over the injury period. Return on investment and cash flow earned by the domestic industry has declined significantly over the injury period.
- f. The inventories with the domestic industry have increased by almost the same quantum as the increase in imports from subject countries. Further, market share of domestic industry has declined. In fact, if market share of domestic industry in the injury period of the original investigation is compared with the market share of domestic industry in the present injury period, it would be seen that the domestic industry has lost market further to the market share loss suffered by the domestic industry at the time of original investigations. In other words, the market share of domestic industry is far lower than the market share that had prevailed at the time of injury period of original case, which clearly shows that cessation of anti-dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry.
- g. There is significant increase in market share of Indonesia even after imposition of anti-dumping duty only because of intensified dumping resorted by the producer in Indonesia. Even if market share of Thailand is added to the market share of domestic industry, the data will show that the market share of domestic industry has declined and that of Indonesia has increased.
- h. No injury has been claimed on account of volume parameters. Domestic industry has claimed injury on account of deterioration in profits, return on investment, cash flow etc.
- i. Comparison of the imports from Thailand with that from Indonesia clearly establishes that the import from Thailand were far lower than import from Indonesia. The domestic industry is supplying modal fibre from Thailand as they do not have modal fibre of the quantity and quality required by Indian consumers. The demand of modal fibre is of 3,700 MT, the domestic industry has a capacity of *** MT in Nagda. So, while setting up a new plant for VSF, domestic industry has setup production facilities for making modal fibre which can produce to the extent of *** MT. Pending full commercial production at this plant in Vilayat, the company has arranged modal fibre from Thailand. Also, modal fibre is not being produced by petitioners' related entities in China or Indonesia, it is being produced only in Thailand.
- j. No injury has been claimed on account of employment and wages.

- k. Domestic industry has not sold such substandard product in the domestic market but only in export market.
- l. 10% return on a 40 year old plant is not significant.
- m. The domestic industry does not have significant sales to related parties.
- n. The price undercutting is hugely negative in case of Thailand.
- o. Cotton, polyester and VSF are not technically commercially substitutable product. They are at best alternative products in different market segments. The Authority is concerned with technical and commercial substitutability of product and not with consumer preferences.
- p. It is indeed contradictory for the interested parties to contend that (a) the petitioner is exporting the product at a lower price and (b) is controlling supplies in the domestic market (where it is getting higher prices). If prices in the domestic market are better and if there is a demand in the domestic market, there is no reason why the petitioner would restrict the supplies in the domestic market and export the product at a lower price in export market.
- q. The domestic industry has claimed adverse price effect of dumping and has submitted that if the present duties are allowed to cease, the petitioner would find difficulty in maintaining production and sales, which shall adversely affect capacity utilisation.
- r. It's the mere assumption of the interested parties that the petitioner has claimed reduction in production as the form of injury. The petitioner has not suffered loss of production in POI due to other factors.
- s. Increase in input prices due to exchange improvement falls in the category of a situation where the domestic industry would increase its prices due to cost increases. The depreciation of rupee in any case would not have adversely affected the domestic industry for the reason that it fixes its prices linked to import price which follows that the depreciation of rupee in fact helps the domestic industry rather than adversely impacting. Also, cost on account of pulp constitutes only 50-52% of total cost of production and therefore while depreciation of rupee adversely affects the domestic industry to the extent of 28% of its cost of production, it supports to the extent of 14% of its cost of production.
- t. While the price of pulp may have declined in terms of US\$, the price has not been much affected in INR. Since the domestic industry incurs the costs in INR, the decline in pulp price in international price has not helped the domestic industry to proportionate extent. However, since the selling price of the domestic industry is linked to INR, the depreciation of INR has more than compensated for the impact on account of raw materials.
- u. Domestic industry has done calculations by considering optimum production at Vilayat and Nagda plant and there is negligible impact on profits on this account. The plant at Nagda is already operating at 97% capacity utilisation.
- v. 5% profit on cost of production is considered by the Authority as reasonable profit in case of non-cooperation from the exporters. Otherwise, Annexure-I refers to the actual profits that must be added to the cost of production.
- w. Imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices. Consumers could still maintain two or even more sources of supply. The Authority has repeatedly held that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Cessation of anti-dumping duty will not make domestic industry more efficient. In fact, it will

injure the domestic industry. As regards exports of VSF and fabric, the same are entirely different issues and are not at all linked to the proposed extension of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty shall not impact exports of yarn or fabric in any way. On the contrary, imposition of anti-dumping duty is in furtherance to the “Make in India” policy of GOI.

- x. The comparison of cost of production in India with cost of production in Indonesia, Thailand and China shows that Indian industry is in fact efficient. So all allegations of inefficiencies of the domestic industry and the internal factors causing losses in the competitive economic conditions are strongly denied.
- y. Any situation that implies segregating the domestic and export performance and does not imply that the Authority shall hold no injury to the domestic industry. Further, the mere fact that domestic industry is exporting at a lower price does not prejudice the present injury analysis. Since the petitioner has segregated export performance, the reported performance relates only to domestic performance and therefore is sufficient enough to allow Designated Authority to determine injury and causal link.

Submissions by opposing interested parties

69. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury and causal link are as follows:

- a. Modal and Tencel Fibre are also included in the import data which are not imported from Indonesia or China. These are mainly coming from Thailand and EU, bulk of which is coming from Thailand from the related company of the petitioner. After appropriate adjustments, the market share of domestic industry has increased in the POI. The domestic industry had admittedly shifted market of Modal Fibre to one of their related companies in Thailand and if same is added to the share of domestic industry they would be controlling significant portion of the Indian market. Domestic industry has deliberately concealed this fact from Authority.
- b. The installed capacity, production, sales and capacity utilization continuously increased in the injury period so it cannot claim any injury on these parameters.
- c. The demand of PUC has increased by 83,977 MT out of which 63197 MT i.e., around 80% has been taken by the domestic industry and remaining 20% is shared by subject countries and other countries including imports of Modal Fibre from Thailand from related entity other related entities from around the world. If the imports of Modal fibre from Thailand are subtracted from the demand, the share of domestic industry in increased demand will be significant. This in no way indicates any injury.
- d. Employment and Wages have not been claimed by the domestic industry as factors causing injury because these factors also show improvement.
- e. While analysing the impact of decline in domestic sales prices, domestic industry ignored the effect of sales of sub-standard product due to stabilization of production in their Vilayat plant, which admittedly fetched lower realization. This lower realization cannot be attributed to imports from the subject countries.
- f. Considering the returns, the VSF industry is getting worldwide, return somewhere in the range of 10% (GFA) to 15 % (NFA), as in the instant case, appear to be very good and no injury can be alleged on this count. Even on the 40 year old depreciated machines they are earning return somewhere around 10% which is significant. Also, as per the financial presentations on their website, they have robust financial performance in the POI and even Post POI (first 6 months of the financial year 2015-16).
- g. The petitioner supplies substantial quantities of PUC to its related entities.

- h. The domestic industry has not provided any information regarding the surplus capacities and export orientation of the exporter from Indonesia. Moreover, no data has been provided by the DI substantiating their claim of likelihood of continuation and recurrence of injury and dumping to the DI in case the duty in force has been withdrawn.
- i. The imports from Thai Rayon are at prices which *prima facie* indicate undercutting and dumping as compared to imports of similar products from Austria.
- j. The import prices of Thai Rayon (CIF) indicate substantial price undercutting when compared with the domestic prices of Modal fiber in India.
- k. The factors behind the decline in the sales realizations are International prices of VSF, price of cotton fiber and PSF and significant sales of off-grade materials. The price undercutting due to allegedly dumped imports from subject countries must be adjusted on account of non-attribution factors.
- l. Grasim increased its production capacities by 79,030 MT (34.31%) by commencement of plant at Vilayat to control the domestic supply and prices by using the dominant position. The exporters cannot be blamed for a wrong business decision of the domestic industry.
- m. Average capacity utilization of the domestic industry has been 94% to 96% during 2011-12 to 2014-15 which indicates a good demand and a healthy state of usage.
- n. Reduction in production during the injury period is on account of shutdown of plants due to internal (water shortages)/ non-attributable factors.
- o. The Cost of Production has increased due to
 - i. Increase in raw material prices
 - ii. Increase in fixed costs due to stabilization of Vilayat plant expansion.
 - iii. Burden of fixed costs on reduced production at Nagda Unit.
- p. Grasim has been earning super normal profits during past 5 years as compared to the normal profits of 5% for the industry as claimed in the calculation of normal value in the petition.
- q. Grasim had stopped manufacturing Modal VSF fiber and turned to imports from Thai Rayon only. It shifted its market share of highly profitable products to its related companies in Thailand. This decrease in market share is self inflicted by Grasim & is a non-attributable factor for injury evaluation.
- r. The termination of duty would lead the domestic industry to become more efficient and price competitive as a result of direct competition. It will also give great boost to exports of viscose yarn and fabric manufactured in India and also promote the “Make in India” policy of the Government of India.
- s. The imposition of anti-dumping duty has been used as a shield to cover the inefficiencies of the domestic industry and the internal factors causing losses in the competitive economic conditions.
- t. The petitioner follows a different pricing policy to ensure that the export market is not lost. This has nothing to do with its performance in the domestic market which is the requirement of law. The domestic industry cannot take shelter of injury under alleged dumping when the so-called injury may have been caused due to its own pricing policies. Thus, there is clearly absence of causal link between alleged dumping and injury to the petitioner.
- u. No question of injury can arise to the domestic industry when it itself exports its production at a much lower price as compared to import prices from subject countries. There are no positive

evidences in the application to indicate the causal link between the injury to the domestic industry and the imports from subject countries/threat of dumped imports from subject countries.

- v. As per the pricing policy of the domestic industry, rebates are given for their supplies against deemed exports. The price charged for the supplies against deemed exports are much below the price charged for the domestic sales. This may be seen from the price lists of the domestic industry. It appears from the pricing strategy and policy of the domestic industry that certain sales made to customers for eventual exports have also been included under domestic sales for the purposes of injury analysis. The so-called injury as claimed by the domestic industry is self-inflicted due to its own pricing policy.
- w. There are no positive evidences in the application to indicate the causal link between the injury to the DI and the imports from subject countries or threat of dumped imports from subject countries.
- x. Premium charged by Grasim in India, as compared to International CFR prices, is between 16% to 22%. (As per corporate presentation 2011-2015, Grasim). Grasim has been found to recover higher prices for fiber consumed in domestic sales of yarn (as per CCI report) including the amount of anti-dumping duty levied on imports from non-Grasim producers.
- y. The prices of VSF in the domestic market are higher than export prices sold by Grasim to rest of world. (Domestic prices are higher by at least 8%)
- z. The reasons for decline in sales realization bring out 3 major factors that cause for significant decline the sales prices
 - (a) International VSF Prices,
 - (b) Prices of cotton fiber and PSF and
 - (c) Significant sales of off-grade materials.
- aa. These factors are internally reported by the highest level of management of Grasim and are to be relied on by the public at large for evaluation of VSF business of Grasim. Source of these reasons is the investor presentations published by Grasim during the previous 4 years 2011 to 2015.
- bb. Therefore, the DA must eliminate that part of the decline in domestic prices caused due to the decline in International Prices of VSF (indexed decline in 2014 is 12.97%, 2011 base) to consider the impact of decline due to imports of VSF from subject countries.
- cc. While imports from Indonesia and China have declined or remained stable; the imports from Thailand through related company of Grasim have increased from 0% to 11% of total imports post imposition of anti-dumping duties.
- dd. The imports from China are lower than 1% (0.25% of total imports) and yet being considered significant by the petitioners.
- ee. The domestic industry has shifted it's market share to related company in Thailand and therefore has increased it's market share by 40% in the past 5 years.
- ff. Increase in sales of VSF in Indian market by Aditya Birla Group companies from India and Thailand is 40% during 2009-2015.
- gg. Domestic industry increased it's production capacities for catering to the export market as their domestic demand increased substantially by 79,030 MT (increase of 34.31%).
- hh. Average capacity utilization of the domestic industry has been 94% to 96% during the years 2011-12 to 2014-15.
- ii. Exports constitute nearly 20% of total production and increase in production capacity was aimed at increased exports.

jj. Reduction in production is on account of shutdown of plants due to internal / non-attributable factors;

- 2011-12 – Shutdown of Nagda plant due to shortage of water
- 2012-13 – Shutdown of Harihar plant and Kharach plant due to non-availability of water
- 2012-13 – Stoppage at Nagda plant due to revamping
- 2013-14 – Decline in production of Nagda plant (shutdown due to water shortage)

kk. The DA must segregate the quantum of injury caused by the aforementioned production shutdowns, which is non-attributable to allegedly dumped imports from Indonesia and China.

ll. The major reasons of decline in profitability, as disclosed by Grasim in the investor presentations and annual reports are as follows:

- Increase in raw material prices has been due to the depreciation of rupee (Caustic soda prices increased by 30%, pulp cost went up by 11% etc.)
- Increase in fixed costs due to stabilization of Vilayat plant expansion
- Increase in employee benefits due to change in interest rates
- Burden of fixed costs on reduced production at Nagda Unit
- increase in consumption of energy per tonne of VSF production by 3%

mm. The post POI results of the petitioner company have shown exceptional profits, increased volume of sales and above average dividend declarations. Petitioner's VSF business has increased profits during the post investigation periods by 27% (from INR 2608 Crores to INR 3331 Crores). The EBITDA has increased by 146% (from INR 233 Crores to INR 575 Crores). The profitability numbers of the DI clearly indicate that there is no injury being caused to the DI. Any decline in profitability was solely due to the decline in international prices, where the DI was able to charge a premium to Indian consumers and earn super normal profits.

Examination by Authority

70. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below:

- a. As regards to the submission of the other interested parties concerning the imports from Thailand, the Authority notes that imports from Thailand are of modal/micro modal fibre and at a price much higher than the import price from China & Indonesia. There is no import of this type of fibre from China and Indonesia. It is noted that there is an increase in the market share of Indonesia during the POI as compared to 2012-13 and 2013-14.
- b. The Authority notes that the total import from Thailand were far lower than imports from Indonesia. The domestic industry has contended that it is importing and supplying modal fibre from Thailand as they did not have modal fibre of the quantity and quality required by Indian consumers. The domestic industry submitted that the domestic industry has setup new production facilities for making modal fibre at their new plant at Vilayat. Pending full commercial production at the plant in Vilayat, the company has arranged modal fibre from Thailand. Also, modal fibre is not being produced by related producers in China and Indonesia. It is being produced only by the related producer in Thailand.
- c. As regards to the submission concerning the absence of injury on parameters of installed capacity, production, sales and capacity utilization, employment and wages the Authority notes that the

domestic industry has not claimed any injury on these parameters, nor existence of injury in each and every parameter is must under the Rules. The domestic industry has claimed injury on account of deterioration in profits, return on investment, cash flow etc. Further, the present investigation is a sunset review investigation, wherein the authority is required to examine whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

- d. As regards to the submissions concerning the sales of sub-standard product, the domestic industry submitted that it has not sold any sub-standard product in the domestic market. There have been some exports from Indonesia of VSF waste which is at low prices, however it is a different category of item and not covered with in the scope of PUC. The VSF waste is being exported by the responding exporters as well it has a specialized usage by some specific users.
- e. As regards to the submission concerning the return on investment, the Authority notes that while the domestic industry contended that the return on investment should be considered along with age of the plant and demanded higher rate of return to enable the domestic industry to get appropriate return on new investments, the interested parties have contended that the return on investment earned by the domestic industry was high. The authority notes that the requirement under the law is whether the performance of the domestic industry has improved or deteriorated in respect of return on investment. If the return on investment has declined, it must be concluded that the performance of the domestic industry has suffered. Despite repeated arguments of the domestic industry, the authority has determined NIP by allowing 22% return on capital employed, as per the established practice in the Directorate and prescribed in ADD Rules.
- f. As regards supply of substantial quantities of PUC to its related entities, the Authority notes that domestic industry does not have significant sales to its related parties in India. Nor the interested parties have provided any specific details or evidence in support of their claim.
- g. As regards possible price undercutting in imports from Thailand, the Authority notes that the price undercutting is significantly negative in the case of imports from Thailand. In any case, imports from Thailand are largely of modal fibre.
- h. As regards submissions concerning the decline in the sales realization due to other types of fibres (cotton and polyester), the Authority notes that inter-se competition amongst different types of textile fibres is not a new phenomenon. Further, the price undercutting in case of imports of PUC from subject countries is significantly positive and demand has shown a positive trend. Therefore, the available market for the subject goods was not declining due to competition from other textile fibres. It is also noted that for the purpose of the present investigations, viscose, cotton and polyester are not technically and commercially substitutable products.
- i. As regards possible abuse of dominant position by the domestic industry, the Authority notes that investigation has shown that imports of the product from Indonesia increased, price undercutting in case of imports from subject countries is positive, performance of the domestic industry deteriorated in respect of parameters such as profits, return on investment and cash profits. The authority also notes that the issue of possible abuse of dominant position is required to be considered by the Competition Commission. The authority is required to determine whether the cessation of the existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and whether the present anti-dumping duty is required to be extended further in order to address the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
- j. As regards absence of injury in respect of capacity utilization, the Authority notes that the domestic industry did not claim that it is suffering from unutilised capacities because of dumping but has claimed adverse price effect of dumping.

- k. As regards to the submission of the other interested parties concerning reduction in production during the injury period, the Authority notes that the production of domestic industry has increased. The Authority notes that the domestic industry has not claimed reduction in production as the form of injury.
- l. As regards adverse effect of rupee depreciation on the cost of production, the Authority notes that the depreciation of rupee would not have adversely affected the domestic industry for the reason that it fixes its prices linked to import price and therefore depreciation of Rupee would have enabled the domestic industry to fetch better prices from the market. Since the domestic industry incurs the costs in INR, the decline in pulp price in international price has not helped the domestic industry to proportionate extent. However, since the selling price of the domestic industry is linked to INR, the depreciation of INR has more than compensated for the adverse impact on account of raw materials. It is further noted that the domestic industry has done calculations by considering optimum production at Nagda plant and there was no production of Modal Fiber in Vilayat Plant during POI. Therefore, there is no significant impact on profits on this account.
- m. Interested parties have contended that Grasim is earning super normal profits. The investigation has however shown that profits earned by Grasim constitute 12% return on capital employed. It is also noted that the domestic industry has significant capacities which were deployed a long time back and net fixed assets value of these investments is quite low now. The information on record shows very significant difference in the per unit net fixed assets in the old and new investments made by the domestic industry. In any case, the authority has determined NIP after allowing 22% return on capital employed as per the usual established practice in the Directorate.
- n. As regards shifting of the market share of the domestic industry to its related companies in Thailand, the Authority notes that the petitioner company has set up a new production facility in Vilayat and if the company were to shift its supplies to Thailand, then they would not have made significant investment in India on such a large commercial level.
- o. Interested parties have contended that cessation of anti-dumping duty will make user industry more efficient. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to eliminate the unfair practice of dumping to the extent it is causing injury to the domestic industry. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. As regards exports of VSF and fabric, the same are entirely different issues and are not at all linked to the proposed extension of anti-dumping duty. Imposition of anti-dumping duty shall not impact exports of yarn or fabric in any way.
- p. As regards submissions concerning the inefficiencies of the domestic industry, the Authority notes that no credible evidence has been on record to show that the Indian industry is inefficient as compared to other subject countries.
- q. As regards low price exports by the domestic industry, it is clarified that the Authority has segregated the domestic and export performance. The domestic industry has provided information segregating its exports and domestic sales. The domestic industry has contended that faced with significant surplus capacities, the producers in subject countries are resorting to dumping in third countries as well. In any case, the mere fact that domestic industry is exporting at a lower price does not prejudice the right of the domestic industry to seek protection under the dumping law. The authority is required to segregate injury suffered by the domestic industry on account of possible deterioration in export performance. The authority has considered only domestic sales of the

domestic industry. Further, profits, return on investment and cash flows are segregated for the domestic operations and only such segregated information has been considered for the present analysis.

- r. As regards to the submission of the opposing interested parties concerning the rebates given by the domestic industry to the deemed exporter in downstream industry, the Authority notes that the domestic industry supplied the material to a manufacturer who consumed the product for production of downstream products for exports and all the associated export benefits were taken by the manufacturer exporter only. Also, domestic industry gave additional benefit to the consumer. Hence, the Authority holds that these sales are clearly domestic sales.

71. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

72. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that the domestic industry has not suffered injury during the current period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

73. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

74. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”

75. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Assessment of Demand

76. For the purpose of determining the demand, the Authority has considered sales of the Indian producers and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of

domestic sales of the Indian producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of Domestic Industry-	MT	215,820	230,450	240,968	279,017
Subject Countries	MT	16,261	8,126	11,308	15,129
Other Countries	MT	4,615	6,539	6,253	11,291
Demand/consumption	MT	2,36,696	2,45,115	2,58,529	3,05,437

77. It is noted that the demand/apparent consumption of the subject goods increased throughout the injury period. Also there has been significant increase in demand for the product in the Country, thus establishing that imposition of anti-dumping duty has not adversely impacted the consumption of the product in the Country.

Volume Effects of Dumped Imports

Import volumes & market share

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Imports Volume					
China	MT	220	46	-	22
Indonesia	MT	16,042	8,080	11,308	15,107
Subject countries	MT	16,262	8,126	11,308	15,129
Other Countries	MT	4,615	6,539	6,253	11,291
Total	MT	20,877	14,665	17,561	26,420
Imports from subject countries in relation to					
Total Imports	%	77.89%	55.41%	64.39%	57.26%
Total demand	%	6.87%	3.32%	4.37%	4.95%
Indian Production	%	5.06%	2.41%	3.13%	3.71%

78. The authority notes that the volume of import from subject countries reported in the petition is on the basis of IBIS which is lower than the volume of imports now established based on DGCI&S. The domestic industry has provided a communication from IBIS stating that the data compiled and provided by IBIS for the year 2011-12 did not match with the DGCI&S data because of non-reporting of data from tuticorin ports which has transacted substantial quantities.

79. The Authority notes that the imports of the subject goods from Indonesia declined in 2012-13 as compared to base year 2011-12 but have subsequently shown a continuous upward trend in absolute terms. The imports from China PR declined to nil levels in the year 2013-14 and picked up during the present period of investigation.

Price Effect

80. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant

degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting

81. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. The following table shows the net selling price of the domestic industry, landed price of the dumped imports and the price undercutting.

Price undercutting	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Indonesia					
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Landed Price	Rs/Kg	135.29	123.20	117.57	114.05
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	-0.49%	3.99%	4.67%	5.06%
China PR					
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	-	***
Landed Price	Rs/Kg	111.50	149.79	-	88.01
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	-	***
Price undercutting	%	***	***	-	***
Price undercutting Range	%	10-20	10-20	-	20-30

82. It is noted that the landed price of imports from both Indonesia and China PR were below the selling price of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. The imports from subject countries are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

Price suppression/depression

83. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of selling price of the domestic industry has been compared with the cost of production and landed price of imports as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	111
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	92	89
Landed Price of Imports	Rs/Kg	135.29	123.2	117.57	114.05
Trend	Indexed	100	91	87	84
Change (over previous year)					
Cost of Sales	Rs/Kg		***	***	***
Selling Price	Rs/Kg		***	***	***
Landed Price of Imports	Rs/Kg		***	***	***
Change (over base year)					

Cost of Sales	Rs/Kg		***	***	***
Selling Price	Rs/Kg		***	***	***
Landed Price of Imports	Rs/Kg		***	***	***

84. The Authority notes that the sale price of the product under consideration has been undergoing a steady decline since base year whereas the cost of sales has increased throughout the injury period. It is thus concluded that the imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market.

M. ECONOMIC PARAMETERS AFFECTING DOMESTIC INDUSTRY

85. As per Annexure II to the AD Rules, the Authority is required to examine the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, which includes an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry have been analyzed as follows.

Production, Capacity, Capacity utilization, Sales

86. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production, and capacity utilization has been as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity	MT	333,975	352,225	377,775	436,065
Production	MT	321,085	337,492	361,012	408,332
Capacity utilization	%	96.14%	95.82%	95.56%	93.64%
Sales volumes	MT	215,820	230,450	240,968	279,017

87. The Authority notes that the domestic industry has enhanced its capacity over the period. The domestic industry has made huge investment in setting up new production facilities at Vilayat, which commenced commercial production in the year 2015. As claimed by the Petitioner domestic industry, the capacity has been enhanced in view of the consistent increase in demand.

88. The production of the domestic industry increased over the injury period, which is a natural consequence of additions to the capacities. Capacity utilisation has declined over the injury period. It is also noted that since there has been consistent increase in capacities, the decline in capacity utilisation could be due to fresh capacity additions. The domestic industry has not claimed injury on account of decline in capacity utilisation.

89. Sales of the domestic industry increased over the injury period. It is however noted that the inventories with the domestic industry increased, which clearly shows that the domestic industry could have sold more, had the exporters not reduced their prices further and absorbed anti-dumping duty.

Market Share

90. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been as below:

	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Domestic Industry	%	91.18%	94.02%	93.21%	91.35%
Indonesia	%	6.78%	3.30%	4.37%	4.94%
China	%	0.09%	0.02%	0.00%	0.01%
Subject Countries- total	%	6.87%	3.32%	4.37%	4.95%
Other Countries	%	1.95%	2.67%	2.42%	3.70%
Total	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

91. The Authority notes that whereas market share of Indonesia declined in 2012-13 and that of domestic industry increased, thereafter, the market share of the domestic industry has declined and that of Indonesia has increased. Market share of China declined till 2013-14 and picked up during the POI .

Profits, return on investment and cash flow

92. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	111
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	92	89
Profit/ Loss	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	38	20
Profit before Interest	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	47	29
Cash Profit	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	45	30
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Return on Capital Employed	Range	60-70	30-40	20-30	10-20

93. The Authority notes that the profit of the domestic industry has declined consistently and significantly throughout the injury period. Whereas the cost of production has increased throughout the injury period, the selling prices have declined throughout the injury period. The price suppression and depression caused by the imports have led to significant decline in profits of the domestic industry.

94. Cash profits and return on investment have followed the same trend as that of profits.

The cash profit and return on investment earned by the domestic industry have declined consistently and significantly throughout the injury period.

95. The domestic industry contended that since its original investments are fully depreciated, the return on capital employed determined by considering net fixed assets as a basis is inappropriate and misleading. The domestic industry further submitted that if the profits earned in the POI are considered, the domestic industry would recover its fresh investments in Vilayat in 45 years. The domestic industry has requested the authority to consider present value of the investment to determine the return on investment earned by the domestic industry and to determine NIP for the purpose of injury margin determination. While

recognising that a significant part of the investments made by the domestic industry are quite old and net fixed assets of the domestic industry in respect of these investments are now quite low thus leading to a situation of high return on investments figures, the authority notes that the authority is concerned with the trends in the injury parameters. Further, it has been consistent practice of the authority to allow 22% return on investments regardless of the age of these investments.

Inventories

96. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table.

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Closing stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	190	163	238

97. It is seen that the inventories with the domestic industry increased over the injury period. The domestic industry contended that they would have not faced rising inventories in the absence of dumping in the Country.

Employment, Productivity and Wages

98. The position with regard to employment and wages is as follows:

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
No of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	98	114
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	111	142
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	115	112
Productivity Per Day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	112	127

99. The Authority notes that number of persons employed and wages paid by the domestic industry has increased over the period. Productivity of the domestic industry has also increased. The increase in employment is because of additions to the capacities. It is noted that despite improvements in productivity and number of employees in relation to capacity, profits of the domestic industry have steeply declined.

Magnitude of Dumping

100. Dumping margins determined for each of the subject countries are above de minimis and significant as can be seen from the table above relating to dumping margin determined by the authority. The dumping margins determined at the time of original investigation were also significant.

Growth

101. Growth of the domestic industry was positive in respect of parameters such as production, capacity, sales volumes. The growth of the domestic industry was however negative in respect of inventories, profits, return on investment, cash profits, market share, etc.

S.NO.	Parameters	2011-12	2012-13	2013-14	POI
1.	Capacity		5%	7%	15%
2.	Production		5%	7%	13%
3.	Domestic Sales Volume		7%	5%	16%
4.	Cost of Sales		3%	5%	2%
5.	Selling Price		-5%	-4%	-3%
6.	Profit/ Loss		-31%	-45%	-46%
7.	ROI		-27%	-13%	-13%
8.	Cash profits		-28%	-38%	-33%

Conclusion on injury

102. In view of the above, it is concluded that imports of the product under consideration from Indonesia have shown an increase after 2012-13 in absolute terms and in relation to production and consumption in India whereas imports from China are concerned, it has declined. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, which has caused depressing and suppressing effect on the prices of the product under consideration in the market. The dumping margin and injury margin determined are positive. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of various economic parameters such as inventories, profits, return on investments and cash flow. Market share of domestic industry has declined. The landed price of imports is below the selling price, cost of production and non injurious price of the domestic industry in the POI. It is concluded that the domestic industry once again suffered injury from dumped imports. In such a scenario, cessation of the anti dumping duty is likely to adversely affect the prices of the domestic industry and is likely to result in significant price depression.

Magnitude of injury and injury margin

103. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. The domestic industry contended that the authority should allow return on investment considering that significant investments are already depreciated and therefore either the authority should allow return on investment after considering market value of these investments or at least a higher rate of return. The authority has however followed its consistent practice of allowing 22% return on investment. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods from the subject countries to determine the injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

	Indonesia		China PR	
	PT South Pacific Viscose	Others	Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co., Ltd& Tangshan Sanyou Group Hongkong International Trade Co. Ltd	Others
NIP (USD/KG)	***	***	***	***
Landed Value	***	***	***	***
Injury Margin	***	***	***	***
Injury margin %	***	***	***	***
Injury margin Range (%)	1-10	25-35	5-15	15-25

N. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

Submissions by the domestic industry

104. The submissions made by the Domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- a. The factors relevant to likelihood of dumping are relevant to the likelihood of injury as well in the present case.
- b. Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty. There is huge probability of massive imports of dumped subject good in the event of cessation of anti dumping duty.
- c. Producers in the subject countries have significant capacity which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.
- d. The exporters from subject countries are exporting the product under consideration to third countries at dumped prices.
- e. The dumping margin in the current POI is positive.
- f. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.
- g. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- h. Significant volume of the dumped imports is at prices below cost of sales of the domestic industry and therefore is likely to lead to price suppression and depression in the market. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.

Submissions by the opposing interesting parties

105. Submission made by various interested parties in respect of likelihood were made subsequent to disclosure statement have been dealt with appropriately in later paragraphs.

Examination by the Authority

106. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of injury in the event of cessation of the duty. The Authority has determined whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these imports if the duty ceases to exist.

107. The Authority has examined the contention of various interested parties. The Authority had called for additional information from the domestic industry for the period beyond the period of investigation. Further, the responding exporters have filed information in the form and manner prescribed by the authority with regard to likelihood analysis. As this is a sunset review, the post POI and third country exports data was analysed. Individual countries trade data has been considered for analysis of post POI data, Export to third country data submitted by the responding exporterfrom Indonesia has also been considered for likelihood analysis concerning Indonesia.

i. Level of current and past dumping margin

108. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is positive. Despite the domestic industry holding the capacity to meet the demand, the import of the subject goods from the subject countries still continue to take place at dumped prices. Given the level of price undercutting from

subject countries during the review period, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

ii. Volume of imports over the injury period

109. It is noted that volume of imports from Indonesia are significant and have shown consistent increase from 2012-13 till POI and in the post POI period despite anti dumping duties in force. Even though imports from China have declined during the injury period, the same have suddenly increased in post POI period. The current volume of imports during the injury period and post injury period and its prices establishes that the domestic industry is still suffering injury as a result of dumping despite existing ADD. Given that the domestic industry has suffered injury and dumping has continued and the volumes have increased from 2012-13 onwards, these parameters per se establish that the cessation of ADD shall lead to further injury to the domestic industry.

Post POI Analysis (April- September 2015)

110. The data of import of PUC into India in post POI was provided by the petitioner and the co-operative exporters, the same has been analysed to see the trends in imports.

Volume of Imports from Subject Countries into India

Country of Export	2012-13	2013-14	2014-15	Post POI (April to Sept,15)	Post POI Annualised
China	46	-	22	1,172 MT	2,344MT
Indonesia	8080	11,308	15,107	7,935MT	15,870MT

111. The imports have increased during post POI from subject countries in spite of Anti- dumping duties in force. There is a huge jump in imports from China. In case of cessation of Anti-Dumping Duty the dumped imports would further intensify. The imports from Indonesia and China have shown positive dumping and injury during the POI, in fact it is very significant as far as China is concerned.

112. The likelihood of dumping and injury from Indonesia was further analysed for post POI period i.e. April 2015- September 2015.

Indonesian Exports to India - Dumping Margin

Producer/Exporter	Normal Value US\$/Kg	Export price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin %	Range
PT South Pacific Viscose	***	***	***	***	5-15
PT Indo Bharat Rayon	No Exports				

113. Since the weighted average selling price of exporters from Indonesia in the POI and Post POI is by and large same, the Authority considers it appropriate to adopt the cost of production as worked out in detail for the POI with 5% profits as the normal value for the post POI and third country exports as well, which has then been compared with price of exports to India and the other countries.

i. Dumping margin in respect to exports to third countries.

114. It is noted that the exports of product under consideration from subject countries to third countries are also at dumped prices. While the domestic industry has established dumping in third countries on the basis of exports from China and Indonesia to third countries, the questionnaire responses filed before the Designated Authority also shows that the exports to third countries are at dumped prices.

Indonesia - Third Country Exports Analysis in POI and Post POI

Dumping Margin in POI

Producer/Exporter	Normal Value US\$/Kg	Export price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin %	Range
PT South Pacific Viscose	***	***	***	***	1-10
Indo Bharat Rayon	***	***	***	***	10-20

Dumping Margin in Post POI

Producer/Exporter	Normal Value US\$/Kg	Export price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin %	Range
PT South Pacific Viscose	***	***	***	***	1-10
Indo Bharat Rayon	***	***	***	***	15-25

115. The normal value for third country exports has been taken based on cost of production as worked out in detail for the POI with 5% profits as the normal value for the exporters from Indonesia during post POI and third country exports as well. The table above shows that the exports to third countries are taking place at dumped prices. The above table shows that the cost of production for PT South Pacific Viscose and PT Indo Bharat Rayon are very different, even though they are at the same location and using the same technology. The processes of procurements and production are also the same; in fact both the companies are in losses during the POI as per their annual reports.

116. The detailed information furnished by DI, was examined by authority for the weighted average import price in India during POI and post POI, as per the table below:

Country of Export	2012-13	2013-14	2014-15	Post POI (Apr-Sep,15)
Volume				
China (MT)	46	-	22	1,172
Indonesia (MT)	8080	11,308	15,107	7,935
Average price (US\$/Kg)				

China	2.58	-	1.34	1.73
Indonesia	2.11	1.86	1.81	1.74

117. It is seen that the volume of exports to India in post POI period of April-Sept., 2015 has increased, whereas the average import price to India has declined in case of Indonesia during the Post POI as compared to the base year.

118. The authority also examined exports from Indonesia to India and third countries during POI and post POI. Further, exports to third countries were examined cumulatively. The authority also examined pattern of exports from Indonesia to third country in individual transactions and segregated the volume of exports to third countries below the normal value and above the normal value.

S.N.	Particular	Indonesian exports	
		POI (MT)	Post POI (MT)
1	Volume of exports to third countries	63,717	60,135
2	Volumes having dumping margin higher than India	147,207	19,209
3	Total	210,924	79,344

119. Analysis of individual export transactions shows that the dumping margin in respect of export to third countries is higher than the dumping margin for India for a quantity of 63,717 MT during the POI. In post POI, 60,135 MT volumes of exports to third countries have dumping margin higher than dumping margin for India.

ii. Excess Capacities and Export Orientation of the Producers

120. As per the information provided by the petitioner on the basis of information in public domain and also information provided by co-operative exporters, it is clear that the producers in subject countries maintain huge capacities to produce subject goods. It is also noted that the producers are highly export oriented. As per the data furnished by the domestic industry; the producers from subject countries export to the range of as high as 26-47 percent of their total production. The export import statistic of product under consideration in Indonesia and China PR are as follows:

Indonesia

S.N.	Name of Producer/Exporter	Installed Capacity (MT)	Exports (MT)	Share of exports
1.	P.T. South Pacific Viscose	***	***	47%
2.	P. T. Indo Bharat Rayon	***	***	26%
3.	Others	-	-	-
4.	Total	520,000	202,159	39%

121. The exporters have substantial excess capacities and a very high export orientation in Indonesia. Considering significant surplus in Indonesia, should the quantum of present anti dumping duties be reduced, it is evident that those exports to third countries which are at a price lower than price to India would be diverted to Indian market. Thus, should the quantum of anti dumping duties be reduced from the existing levels to the new levels, it is evident that exports to India would significantly increase.

China

S.N.	Name of Producer/Exporter	Installed Capacity (MT)	Exports (MT)
1	Fulida	4,80,000	24,423
2	Tangshan Sanyou group	5,00,000	200,000
3	Aoyang	2,70,000	Not known
4	Yamei	2,60,000	Not known
5	Sateri	3,70,000	48,902
6	Yibin Grace	2,00,000	Not known
7	Lenzing	1,78,000	32,067
8	Others	12,18,000	58,163
9	Total Capacity	3,476,000	363,555

122. In case of China also there are huge production capacities in the country. The total Indian demand is in the range of 300,000 MT which is less than 10% of the total installed capacity in China. In case of cessation of Anti Dumping Duties, the Indian market will become very attractive to the exporters and there is every likelihood that imports at dumped prices from the subject countries will further intensify.

iii. Trade defence actions by other countries.

123. It is noted that the Brazilian government has earlier imposed anti-dumping duty on imports of Viscose Staple Fibre (VSF) from China, Thailand, Indonesia and Austria.

iv. Price attractiveness of the Indian market

124. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the Indian market. Imports are undercutting the domestic industry prices. In case of cessation of duty, the consumers would find the imported product much cheaper than the domestic producers and the producers from the subject countries would further aggressively target the Indian market. Thus, the product is likely to enter in large volumes at dumped prices from the subject countries, should the present anti dumping duty be ceased.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

125. In view of the current volume of imports in the POI from the subject countries despite existence of anti-dumping duty, price undercutting, dumping margin & injury margin; the Authority concludes that there exists likelihood of continued dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty. The import prices would further undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices in the event of cessation of Anti-dumping duties. Surplus capacities available with the subject countries and high export orientation shows likelihood of increase in dumped imports from subject countries.

126. In view of the above, the authority concludes that should the present quantum of anti dumping duties be reduced to the levels of dumping margin and injury margin found in the present POI, the volume of imports shall increase further. The authority therefore concludes that the level of dumping margin and injury margin determined in the present POI in respect of exports to India is not sufficient to establish that dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duties is unlikely to increase. As the the dumping margin and injury margin in respect of individual export transactions to third countries clearly demonstrate that the dumping and consequent injury is likely to intensify in the event of cessation of anti-dumping duties. Thus, the pattern of exports in individual export transactions to third countries in POI and post POI period clearly establishes that it would not be appropriate to reduce the quantum of anti dumping

duties to the level of dumping and injury margin established in the present POI. The authority also notes that the dumping margin and injury margin in POI are only one of the parameters for the purpose of determination of likelihood. These parameters in itself are not sufficient to decide the likelihood situation in the event of cessation of anti-dumping duties. Even in a situation where the dumping margin and/or injury margin in the POI are found to be negative, the anti dumping duties is required to be extended further in case it is found that the product is being exported to third countries at dumped and/or injurious price in the POI, or in case the dumping margin and/or injury margin in the post POI are found positive. Thus, in a situation where dumping margin and injury margin are likely to increase with the cessation of anti-dumping duties, as established by the pattern of export transactions to third countries during POI and exports to India and third countries in post

POI, it would be appropriate to recommend the continuation of the existing quantum of anti dumping duties.

Causal Link

127. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. The investigation has shown that the imports were at dumped prices, the domestic industry has once again suffered injury and the volume is likely to increase if antidumping duty were allowed to be ceased. Notwithstanding, the Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

- a) Imports from third countries: - Imports from third countries are either negligible in volume or higher in prices. Third country imports are unlikely to cause injury to the domestic industry.
- b) Demand for the product:- There is no contraction in demand for the product under consideration and therefore claimed injury to the domestic industry cannot be due to possible contraction in demand.
- c) Changes in the patterns of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
- d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice which can contribute to the injury to the domestic industry.
- e) Developments in technology: - It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury.
- f) Performance of other products produced and sold by the domestic industry: - The domestic industry is a multi-product company. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration only.
- g) Export performance: - the domestic industry has claimed injury only on the account of the domestic operations. The authority has segregated export performance at appropriate places.

O. Post Disclosure Submissions

Submissions by Domestic Industry

128. The submissions by the domestic industry have been summarized and are as below:

- i. The product under consideration also includes Tencel fibre/ Lyocell fibre. These are being imported from third countries (Austria, UK, Germany and USA) and are being produced by Lenzing in its plants other than Indonesia and China. However, it is understood that Chinese producers have also started producing this fibre. The imports of this fibre are being reported under 5504.9090, it is understood that the Chinese are classifying this product under other HS code (5504.1090 and 5504.1029, 5504.90000, and 5504.1021). The authority may therefore clarify that Tencel fibre

/Lyocell fibre are part of the product under consideration and have been included in imports from third countries.

- ii. The full description of the product under consideration should be mentioned in duty table and it should be mentioned that antidumping duty is applicable on all these items irrespective of the custom classification.
- iii. Petitioner has also established that there was no circumvention of anti dumping duty imposed on imports from China/Indonesia by routing products through Thailand.
- iv. The exporters have resorted to excessive confidentiality - (i) as regards inputs, the same are from related party; (ii) as regards financing, the same are from related party; (iii) as regards sales, the same are by related party, (v) management fee which implies services being rendered by parent company towards the same.
- v. The questionnaire response ought to be rejected for misleading and false statements 1) as regard to marketing of products produced by the company, 2) Purchase of Pulp from Market, 3) Services being rendered by the parent company with regard to machinery equipment and spare parts, 4) Sale of Fibre. The related party disclosure in the annual report clearly shows the above transactions are related party transactions
- vi. Petitioner is unaware whether the related party has provided any other services, including corporate services. Thus, neither the revenue nor the expenses of South Pacific Viscose are free from related party transactions and there would have been elaborate scrutiny of the exporter, had it truthfully come out before the Designated Authority with clean hands and had it truthfully disclosed all relevant facts in public version. South Pacific Viscose however had malafide intentions in suppressing such vital facts from the Petitioner and used confidentiality provisions for the purpose. Further, Petitioner has been prevented from defending its interests and effectively participating in the present investigations. Participation by the Petitioner in the present investigation with regard to dumping margin for South Pacific Viscose has been reduced to a mere procedural formality.
- vii. The company has received grant from Govt. of Indonesia in connection with Govt. of Indonesia's program to stimulate capital expenditure in the textile industry. These grants have been amortized by the company over a period of 12 years. This fact also has been suppressed by the exporter.
- viii. In response to the questionnaire part II, SPV has stated that there is no other related firm that produces or has plans to produce the product in India or third countries. This is blatantly false statement, as SPV is a subsidiary of Lenzing AG and who has two plants in Austria, one plant in UK and one plant in USA. Such false and misleading statement has been made by the exporter.
- ix. South Pacific Viscose has not established that its procurement price for inputs, including major raw materials (pulp) reasonably represent costs associated with production and sale of the product under consideration.
- x. Analysis of the annual report of SPV shows that amounts payable to the related pulp supplying company have significantly increased, despite the fact that pulp prices had declined in this period. Further, the average outstanding amounts to the pulp supplying company are at reasonably high levels and represents at least more than 100 days of outstanding. This clearly implies significant interest costs that the company would have incurred in the absence of relationship with the pulp supplying company. Thus, there is a clear subsidisation by the related company to South Pacific Viscose.
- xi. The company has obtained significant loans from its parent company. The interest on these is being charged at Libor plus 2.75%. However, there is no information given by the exporter to establish appropriateness of the interest rate. Had South Pacific Viscose raised loans in Indonesia, the company would have paid interest at @ around 13% per annum, the rate of interest applicable in Indonesia.

The cost of production is required to be adjusted for these in order to reflect the costs reasonably associated with production and sale of the product under consideration. Further, in view of highly incomplete response, the authority should charge full interest on such loans provided by the related company by considering the rate of interest applicable in Indonesia.

xii. The marketing of the product has been undertaken by parent company's marketing arm, it is evident that all expenses relating to such marketing arms, including SGA and profit are required to be considered for determination of dumping margin.

xiii. The authority has determined dumping margin in the range of 1-10 % in the disclosure statement. The Petitioner has assessed dumping margin of the exporter as US\$ 341 per MT based on the exporter's annual report and export price to India. The difference in the dumping margin is TOO SIGNIFICANT.

xiv. In the final findings issued by the authority in the matter of circular weaving machine wherein the authority has adjusted export price for SGA and notional profit for the Indian arm of the holding company of the producer. The exporter has however provided no such information to the authority, the authority never examined these issues due to misleading statements by the exporter and the domestic industry never got opportunity unless recently to highlight these facts in view of suppression of facts and false & misleading statements by the exporter.

xv. The petitioner had earlier submitted in the petition that the exporter gives post invoicing discounts. The questionnaire response of the exporter is clearly indicative of the fact. The exporter has stated that it does not have a price list and the orders are procured based on negotiations. Such being the case, there should be no question of any discounts after procurement of orders. The exporter however has stated that the prices are negotiated depending upon market conditions and "discounts are inevitable". This clearly shows that the exporter indeed is giving discounts after procurement of orders. Petitioner submits that these post invoicing discounts were as high as US\$ 100 pmt.

xvi. The annual report of the company shows that the exporter has suffered exchange losses. The amount in annual report is reported after adjusting the losses to the exchange gains. Gross amount of exchange losses are part of raw material costs whereas exchange gains are part of revenues. The petitioner therefore requests the authority to kindly consider the gross amount of exchange loss for determination of cost of production.

xvii. The petitioner has claimed reply to the question on treatment of by-product/wastage/scrap/damage/ sub-standard goods as confidential. Petitioner submits that this is mala fide for the reason that the treatment of wastage/scrap/ damage/by-product on one hand and sub-standard goods on the other hand is totally different under dumping law. As far as sub-standard goods are concerned, these are required to be considered as part of product. As far as wastage/scrap/ damage/by-product is concerned, since these are NPUC in the present case, production is required to be determined after adjusting the same for the production of wastage/scrap/ damage/by-product. SPV claimed confidentiality in the reply in order to prevent domestic industry making appropriate submission, as the same may be disadvantageous to the exporter.

xviii. Annual report of Lenzing shows that Lenzing has resorted to "inventories write down of Euro 9.88 million. Petitioner submits that inventory write down forms part of cost of production in the same way as forex loss on raw materials is considered as a part of cost of production. Therefore, the inventory write down amounts should be added to raw materials costs to determine cost of production.

xix. Petitioner had raised the issue of significantly lower price reported in Indonesian customs at many times during the investigation. There is however no reply given by the exporter and never established by the exporter how its claim of export price corroborates with the Indonesian customs data. The export price claimed by South Pacific Viscose is required to be rejected on this ground alone.

- xx. The petitioner submits that already annual report of SPV shows that the company has suffered financial losses. Given the claim of the exporter that its export price to third countries are comparable to the India, it follows that all sales transactions in the home market might become loss making. The petitioner thus submits that correct assessment of cost of production is very critical in the present case.
- xxi. Petitioner further submits that the submissions now being made by the petitioner are not from non-confidential version of questionnaire response. In fact, SPV has claimed lot of this information confidential in its questionnaire response. Petitioner has made the submissions on the basis of documents now procured by the petitioner from its market intelligence.
- xxii. At Harihar, the company has largely consumed its own pulp. The pulp has been transferred from pulp division to fibre division through financial accounts. The value of pulp adopted in VSF is on the basis of financial records maintained by the company. Since the valuation of captive pulp by the company is on the basis of records maintained by the company, the value adopted by the company is required to be allowed for the present purposes.
- xxiii. There is HUGE difference in the NIP determined by the Designated Authority and NIP claimed by the domestic industry in its petition. Further, there is nothing stated in the disclosure why the NIP of the domestic industry has been SO DRASTICALLY REDUCED.
- xxiv. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets, or at the least gross value of fixed assets. In any case, adoption of net fixed assets is highly inappropriate and, in fact, unfair to the domestic industry, considering that some of the investments are significantly old and therefore, net fixed assets does not represent true value of investments. In fact, the most appropriate value for the purpose is present value of the investments for determination of NIP.
- xxv. Petitioner submits that the raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past for the reason that the cause of increase in the consumption is not inefficient utilization of such inputs.
- xxvi. Under Annexure-III, only inefficient utilization of raw materials or utilities is required to be normated. Bona fide changes in the raw materials are not required to be normated. Therefore, the Designated Authority is requested to consider the actual consumption of inputs.
- xxvii. Corporate expenses are allocated considering consolidated sales of the company (including overseas). However these corporate expenses relate only to Indian business.
- xxviii. Research and development expenses have not been considered while calculating NIP. The expenses are incurred to improve the quality of the product. Excel, Nagda plant NIP has not been considered while determining weighted average NIP.
- xxix. Imposition of anti dumping has led to improvement in the performance of the domestic industry in terms of production and sales. However, imports of the product under consideration increased in the POI in absolute terms, and have remained significant in relation to production and consumption of the subject goods in India. Increase in imports is much more than the increase in demand.
- xxx. Subject imports hold significant market share despite anti-dumping duty in existence. Price undercutting without anti-dumping duty is significantly positive.
- xxxi. It is evident from the questionnaire response of South Pacific Viscose and its annual report that they are claiming continued deteriorating market condition for year 2014 mainly on account of: excess capacities in China. The Capacity utilization of the exporter declined in the last quarter, which implies further likelihood of injury.

xxxii. The company reported that the market conditions during the year were "brutal" leading to negative profit before interest and taxes. The company expected continuation of very difficult market condition in 2015. The major reason for losses suffered by the company was pre-dominantly lower sales price.

xxxiii. The company has not paid any fees to PTG and LAG and only 50% commission to Erafista. Implications of these on cost of production are not clear.

xxxiv. There is insufficient information provided by South Pacific Viscose both for normal value and export price. Further, South Pacific Viscose has resorted to highly misleading information and has made false statement. Under the circumstances, the authority should not determine dumping margin for South Pacific Viscose based on their data. The authority should determine normal value on the basis of PT Indo Bharat and export price on the basis of Indonesian customs data and thereafter determine dumping margin.

xxxv. The quantum of anti-dumping duty may therefore be enhanced to account for increase in dumping margin and injury margin. Without prejudice, should the authority continue to consider that the dumping margin for South Pacific Viscose is required to be determined based on their questionnaire response, despite these glaring differences, false & misleading information, the authority may consider extension of the existing quantum of anti-dumping duty as was imposed in the original investigation. There is clear likelihood of dumping and injury in case of revocation of anti-dumping duty.

xxxvi. Petitioner has analysed dumping margin and injury margin in case of Indonesia by considering individual export transactions. Dumping & injury margin for third countries cumulatively is higher than dumping & injury margin in case of India. The volume of exports having dumping margin and injury margin higher than India is quite significant. The volume of dumped exports in case of South Pacific Viscose is higher than volume of dumped exports in case of Indo Bharat.

xxxvii. Petitioner has also analysed dumping and injury margin in case of Indonesia by considering post POI data as per Indian customs. The relevant calculations and import data is enclosed. It would be seen that export price has declined by US\$ 72.84 pmt in the post POI period. Thus, even if the dumping margin given in the disclosure statement is considered, the dumping margin in the post POI is higher than the existing anti-dumping duty.

xxxviii. Anti-dumping duty may be imposed in fixed form in the unit of US Dollar.

xxxix. Petitioner submits that while the exporters in subject countries are already having significant surplus capacities, further fresh capacities are being set up in the subject countries.

Submissions by Opposing Interested Parties

129. The submissions by all other interested parties have been summarized and are as below:

- i. The Authority has not dealt with our submissions on the eligibility of the applicant Industry. The applicants have shared their confidential information among themselves and also represented by a common legal representative for the applicant industry and an exporter from both the subject countries. In disclosure statement, the Authority has simply stated that it is "entirely irrelevant" to the present issue without recording any reasons in support thereof.
- ii. The Authority in the disclosure statement has stated that there is likelihood of dumping and injury from both the related entities of applicant industry. If it is the case, the only consequential finding that the Designated Authority ought to have recorded was to consider the applicant as ineligible domestic industry in terms of Rule 2(b). Further, the fact that there were no imports during the period of investigation is absolutely of no consequence in a sunset review investigation as the decision of the Authority is based on likelihood of dumping and injury.

- iii. The Authority should re-examine the eligibility of the applicant industry. Further, the guidelines that are followed by the authority to decide whether to exercise discretion for inclusion or exclusion of industry in terms of Rule 2(b) if it is found to be related to an exporter or an importer or resorts to self imports. The conclusion of the Designated Authority that this issue has attained finality in view of its earlier Final Findings is factually not correct if tested on the touchstone of settled law on the subject. The earlier Final Findings of the Designated Authority were quashed by the Hon'ble Tribunal and remanded for fresh consideration. They could not be said to be effective as they were rendered in breach of natural justice declared by the Hon'ble Supreme Court in the context of anti-dumping law in the case of ATMA.
- iv. The scope of the PUC cannot be changed in sunset review investigations. In view of the above, it is submitted that since “VSF waste” was not excluded in the original investigation and, therefore, very much covered within the product scope.
- v. Disclosure statement records that there is only import of VSF Waste (non product under consideration) from Indonesia while the import data shows that there are several entries for product under consideration alone. Which entry according to Designated Authority is non-product under consideration needs to be clarified.
- vi. In response of the paragraph 56 of the disclosure statement, , it is submitted that SPV are selling directly to users and traders and merely having marketing office of the related entity India does not change the channel of distribution. Further, in relation to purchase of raw material, all details relating to purchases from the related party along with detailed documentary evidence had indeed been submitted to the Authority.
- vii. In relation to calculation of normal value for post POI period the Authority has, in an unprecedented manner, calculated the normal valve based on POI cost plus 5%.The Authority should consider the post POI Appendix-1 of the exporter for calculating normal value for the likelihood purpose which is already on record.
- viii. The applicant industry is having differential pricing for domestic sales vis-à-vis utilization of downstream product for domestic consumption or for export purpose. In this context, the Authority is requested to kindly analyze and considered this factor while doing injury assessment. It may be appreciated that any lower realization due to lower selling price to users who ultimate export the goods cannot be attributed to imports from Indonesia.
- ix. The Authority has not done any analysis after adding anti-dumping duties as per its consistent practice. The Authority is requested to kindly also analyze the injury parameters, price undercutting, price underselling after adding anti-dumping duties so that current position of the applicant industry is analyzed. Current analysis without adding anti-dumping duty tantamount to likelihood analysis only and cannot be considered as injury analysis for POI period.
- x. In relation to increase in inventory of the applicant industry, the Authority in paragraph 88 has noted that “the inventories with the domestic industry increased, which clearly shows that the domestic industry could have sold more, had the exporters not reduced their prices further and absorbed anti-dumping duty”. The Authority should analyze the contribution of imports to increase in inventory.
- xi. It is submitted that the likelihood analysis done by the Authority is incomplete and without any objective assessment. In the disclosure statement, the Authority has reached the likelihood analysis only on the basis of likely dumping, price attractiveness and export intensity of the exporters from subject countries. The dumping margin is barely above the de minimis limit and cannot be considered as significant or material.

- xii. As regards price attractiveness, this is a hollow statement inasmuch as the prices to India and to the rest of the world are almost identical. Thus, there is no basis to suggest that Indian market is particularly price attractive.
- xiii. In relation to the export intensity of the SPV, exports to India are more or less the same over the years. It is also a matter of fact that SPV is selling almost entirely to those customers who are not catered to or refused supplies by the applicant industry. Therefore, there is no occasion for SPV to increase its customer base. SPV is operating at 99% of their capacity and selling almost complete quantities in the market. Therefore, there is no surplus capacity available with SPV as indicated by the Authority in the disclosure statement further demolishing the myth of export intensity.
- xiv. There is no legal or logical basis of extending duties against SPV on the basis of likelihood of injury and dumping. Since the Authority has not calculated the injury margin for post POI period and methodology for calculating post POI dumping is also erroneous, we humbly request the Authority to kindly do not consider any adverse inference of any likelihood analysis against SPV.
- xv. MODAL/Micro MODAL fiber must be excluded from the scope of PUC based on the findings of the DA, the DI has neither produced any modal/micro fibers in India including it's newly commissioned plant in Vilayat in March 2015. The domestic industry does not get unwarranted protection for products which are not produced in India nor have the capacity to produce these products in India.
- xvi. The DA has disregarded the profitability of 5% on total cost, used by the petitioners themselves in application and considers allowing a return on capital employed of 22% without providing sufficient details of the methodology for calculation of such return to opposing interested parties to rebutt this assumption. The association claims that such super normal returns are not justified in the light of the fact that the petitioner is already charging a 16% to 22% premium over the International Fiber Prices and making super normal profits in domestic sales.
- xvii. The DA has completely ignored the fact that the petitioner has continuously increased the prices of the PUC in the domestic market and charged a premium of 16% to 22% thereby establishing that the continued imposition of the duties will only shield the incorrect capital investment decision (to invest in capacities in the Vilayat plant) of the petitioner. Therefore, there is no causal link between the imports and injury and if duties continue the petitioner will continue to charge premium to the domestic consumers beyond the international prices of Viscose Fiber.
- xviii. The DA has erred both in law and fact by including the sales not destined for consumption in India (deemed exports) as domestic sales whereby the actual domestic profit, ROI and price impact has been adversely affected. Exclude the sales destined for consumption outside India from the injury and causal link more particularly the calculation of profit, ROI, cash profit and non injurious price (after exclusion of discounts on such sales). Disregard such rebates and discounts as sales in the course of exports not destined for consumption in India for such purposes.
- xix. Anti-dumping duty levied will deprive the Indian downstream industries of opportunity for low cost raw material and make them uncompetitive industry for export. Further the downstream industries are small, medium scale industry that cannot source international raw material for re-export. This is against the spirit of “MAKE IN INDIA”.
- xx. Further, the importers/users who filed submission/letter without detailed questioner, clearly shows they have threatened by Petitioner Company to send such letter (It may be noted all such letters may be stereotyped and mainly Companies in Namakkal District, Tamil Nadu). The companies do not have resources to import.
- xxi. The Viscose Staple fibre has different end use and Petitioner company does not charge the same price to all the Consumers, there is different price for Non-woven 100% Viscose yarn I Viscose in Polyester yarn, Viscose Cotton yarn etc. and also for viscose in Export of Yarn.

xxii. Tangshan is vitally affected by the dumping margin determined in the Anti-Dumping investigation. The dumping margin is calculated with Proposed CNV and export value of Sanyou. The paragraph 2.4 of ADA requires: "A fair comparison shall be made between the export price and the normal value." And investigating authority should take into consideration all export transactions involving all models exported by investigated producers in the dumping margin calculations. There are different specifications or models for the subject products in this case. But we can't identify from the disclosure that whether the comparison are based on different products specifications or models.

xxiii. As per the Appendix 2 of questionnaire, the total volume of PUC of Sanyou is 267.5MT. However, from the disclosure we noted that the volume of import from China is merely 22 MT during the P01. There is no explanation for the consideration on such conflict.

xxiv. The Ex works export price of Sanyou offered by the Authority is different than the data submitted in questionnaire, the same may be revised accordingly.

xxv. During the POI, the USD-INR was not always stay at a stability number. Quite a long period, the data is higher than 61.69. So the exchange rate using by investigating authority to calculate the CIF price is not reasonable.

xxvi. When browsing consolidated ten year financial summary of the domestic products representation Grasim Industries Limited. We find that Grasim's profit of VSF sale during the POI is at a higher level.

xxvii. As pointed in the disclosure, modal fiber is not competing with the PUC in the same market due to the high price, special producing technology and use. Such evidences have been admitted by the petitioner and the Designed Authority. As per Article 2.6 of ADA, the modalfiber/micro modal fiber should be excluded from the scope of product under investigation.

Examination by the Authority

130. The points raised in the post disclosure submissions have already been dealt with in earlier paragraphs of this finding; however, they are being addressed point-wise as under-

- i. Authority clarifies that there is no change in the scope of product under consideration. The waste was not part of PUC in original investigation or in the present review investigation. The claim of exporter that they have been prejudiced in any way on this count is baseless.
- ii. As regards information concerning channel of distribution in the questionnaire response by SPV, the authority notes that the questionnaire response of SPV did not explain the role of marketing office in India, nor any information has been provided by the company with regard to payments made to this marketing office and sufficiency thereof considering the expenses incurred by the Indian office of Lenzing.
- iii. As regards purchase of raw material, SPV indeed claimed in its questionnaire response that all purchases of inputs were made form unrelated parties, whereas pulp in fact was purchased from related parties.
- iv. As regards determination of normal value for post POI on the basis of cost of production after adding 5% profits, the authority notes that complete information required for determination of normal value for post POI period was not made available and therefore the authority has determined normal value on the basis of cost of production plus 5% profit. Moreover, since the weighted average selling price of PT South Pacific Viscose in the POI and Post POI is by and large same, the Authority considered it appropriate to adopt the cost of production, as worked out in detail for the POI with 5% profits as the normal value for the post POI and third country exports as well. With a view to ensure fair comparison of the normal value for the other exporter from Indonesia the same methodology has been adopted.

v. As regards certain sales made by domestic industry describing as deemed export sales, the petitioner clarified that they have not availed any export benefits on these sales, these sales have been made to the domestic consumers and the goods in these cases were destined for consumption within the Country. Export benefits in these cases have been availed by the consumers of the domestic industry. These sales are rightly treated as domestic sales.

vi. As regards assessment of price undercutting after adding anti-dumping duties, the authority notes that selling price of the domestic industry is almost comparable to the landed price of imports after adding anti-dumping duty. Further, since present investigation is a sunset review investigation, the authority is required to determine price undercutting and injury margin without adding anti-dumping duty for likelihood purposes. Positive price undercutting without adding anti-dumping duty and almost comparable domestic and imported product prices after adding anti-dumping duty implies that in the event of cessation of existing anti-dumping duty, the domestic industry shall be forced to reduce its prices. Further, the price underselling is also required to be considered alongwith price undercutting in order to ascertain the likely effect of dumped imports on the domestic industry.

vii. As regards increase in inventories, the authority notes that the domestic industry could have sold to the extent of inventories. It is noted that the inventories and imports undisputedly increased over the injury period.

viii. As regards quantum of dumping margin for the purpose of likelihood analysis, the authority notes that the dumping margin is only one of the parameters to undertake likelihood analysis. Existing quantum of anti-dumping duty, surplus capacities with the exporters and volume of exports to third countries are also quite relevant and appropriate in this regard.

ix. SPV has contended that since volume of exports over the injury period is comparable, SPV does not have export intensity. Authority notes that there is increase in imports from Indonesia, after decline in 2012-13 despite existing anti-dumping duties. Further, the mere fact that existing capacities are fully utilized does not mean that the exporter does not have freely disposable production capacities. Further, the current volume of exports from Indonesian is significant enough to establish likely adverse price effect in the event of cessation of anti-dumping duty. It is noted in this regard that the annual report of the exporter itself has inter-alia stated as follows which clearly establishes that the exporter is facing the same competition in the market as is being faced by the petitioner.

x. Interested parties being contended that modal/micro modal fiber must be excluded from the scope of PUC. The authority, however, notes that modal/micro modal fiber has been produced by the domestic industry and, imported from third countries, even though not imported from subject countries. Since exporters from subject countries have not exported modal/modal micro fiber, the authority has determined NIP and injury margin after excluding cost of production of modal/micro modal fiber. However, as far as injury analysis is concerned, since modal/micro modal fiber is part of PUC, the same is included in the injury analysis.

xi. It has been contended that the domestic industry has consistently increased prices. Verified information however shows that there was consistent decline in the selling price over the injury period and the profitability of the domestic industry has also declined significantly over the period. The decline in the selling price is despite the increase in the cost of production.

xii. As regards disclosure of various figures such as normal value, export price, NIP etc, it is clarified that these information are confidential and therefore cannot be disclosed publicly. The export values for exporters from China has been calculated as per the established practices in the Directorate.

xiii. As regards contention that the authority should compare cost of production of exporters and the domestic industry, the authority notes that the objective of the present investigation is not to examine competitiveness of the petitioner domestic industry vis-à-vis exporters. The authority is required to

examine whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. Inter-se competitiveness of domestic producer and foreign producer is irrelevant for the purpose.

xiv. The interested parties have contended that the exporter benchmark their prices on the basis of prices declared by the domestic industry. The investigation has however shown that the price undercutting is positive. This implies that even if domestic industry is fixing its prices first, the exporter are selling their product at a price below the selling price of the domestic industry. This also establishes that the cessation of anti-dumping duty shall lead to significant price undercutting and adverse price effect.

xv. As regards competitiveness of the downstream industry in export market, the authority notes that imports of a product for export production in any case do not attract anti-dumping duty and therefore these exports shall not suffer as a result of proposed measures,

xvi. As regards submissions concerning disclosure of methodology and information concerning dumping margin, the authority notes that the disclosure statement explains in detail the methodology adopted for determination of normal value, export price, dumping margin. As far as confidential figures are concerned, the same could not be disclosed in view of the confidentiality provisions. It is, however, clarified that authority has undertaken a fair comparison between normal value and export price based on all parameters laid down under the law and has determined dumping margin after taking into account of known exports from China.

xvii. As regards differences in physical characteristics or specifications, the exporter has not provided any information in the questionnaire response nor made any claim whatsoever to show that there are significant differences in specifications or models and weighted average comparison would not be appropriate. In fact, on the spot verification revealed that in fact there was no significant difference in the cost of production of different product types.

xviii. As regards Para (xx) of the disclosure statement, the interested parties were intimated about inadvertent inclusion of this Para in the disclosure statement.

xix. As regards exchange rate, it is clarified that the authority has mentioned weighted average rate prevailing during POI in the procedure part of the disclosure. However, the import price is based on exchange rate prevailing during the relevant month as declared by the customs authorities.

xx. The authority notes that there is no bar on a legal consultant to represent a domestic industry and a foreign exporter, particularly when two are related entities. In any case, the rules do not proscribe that related parties should not participate in the investigation through a common counsel. Ultimately, the authority has made present determination on the basis of verified facts and after its own satisfaction with regard to information provided by the interested parties.

xxi. As regards contentions concerning eligibility of the Petitioner, the fact that two entities are related entities and the authority has found likelihood of continuation and or recurrence of dumping and injury, it does not imply that the authority should hold the petitioner as an ineligible domestic industry because of its relationship. The authority has in fact reassessed the standing of the petitioner as a domestic industry. The authority has not applied the original determination in this regard. However, the interested parties have failed to establish how the petitioner does not constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b). It is clarified that there are no exports of the product under consideration by such related producers in subject countries and therefore the relationship of petitioner with the producers in subject countries in any case does not attract Rule 2(b). The authority notes that the question of exclusion arises only in a situation where such related producers in subject countries have exported significant volumes in the POI. While in the present case, the related Indonesian company has exported an insignificant quantity of waste in Indian market. The

document provided by petitioner clearly shows that this import was cleared without payment of anti-dumping duty. This fact not only establishes that waste was not included within the scope of product under consideration at the time of original investigation, but also establishes that the related party has not exported PUC in India.

xxii. As regards analysis of ten years financial summary of the petitioner, authority notes that the present determination is based on verified information of the petitioner, which is for product under consideration. Further, profits and return on investment etc. have been determined only for domestic operations.

P. CONCLUSION

131. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;
- b. The domestic industry has suffered injury;
- c. There is a likelihood of recurrence of dumping and injury in case of cessation of Anti-dumping duties.
- d. Under the circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend existing quantum of anti-dumping duties against imports of Indonesia and China. In case of China PR, there was no responding exporter during original investigation however, in the present review investigation one exporter has responded and provided information which has been considered by the Authority and individual dumping margin and injury margin was determined .

Q. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

132 The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.

133. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

R. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

134. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and post Disclosure Statement submissions made by the interested parties, the Authority concludes that:

- i. The subject goods from the subject countries continue to enter the Indian market at dumped prices. Dumping margin and injury margin are positive and significant.
- ii. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of various economic parameters such as inventories, profits, return on investments and cash flow. Market share of domestic industry has declined. The landed price of imports is below the selling price, cost of production and non injurious price of the domestic industry in the POI.

- iii. Price undercutting is likely to be significantly positive in the event of cessation of anti-dumping duty.
- iv. The fact that subject countries have significant surplus capacities, exporters from subject countries are highly export oriented, and exports made are at a price which is showing significantly positive dumping margin and injury margin, the Authority determines that in the event of withdrawal of the anti-dumping duties, there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
- v. Under the circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend existing quantum of anti-dumping duties against imports of subject goods from Indonesia and China PR. In case of China PR, there was no responding exporter during original investigation however, in the present review investigation one exporter has responded and provided information which has been considered by the Authority and individual dumping margin and injury margin was determined. Accordingly, the duties for responding exporter and non cooperative exporter are as per the duty table below. The Authority, thus, in order to remove likely injury to the domestic industry, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods from the subject countries as per column 8 in the duty table below:

Duty Table

Sl. No	Heading / Subheadi- ng	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	P T South Pacific Viscose	P T South Pacific Viscose	0.103	US \$	KG
2	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	Any combination other than as specified at Sr. No.1		0.512	US \$	KG
3.	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Any country other than Indonesia	Any	Any	0.512	US \$	KG
4.	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF)	Any country other than	Indonesia	Any	Any	0.512	US \$	KG

		excluding Bamboo fibre'	Indonesia						
5	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	China PR	Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fibre Co., Ltd	Tangshan Sanyou Group Hongkong International Trade Co. Ltd	0.180		KG
6.	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	China PR	Any combination other than as specified at Sr. No.5		0.194	US \$	KG
7.	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	0.194	US \$	KG
8.	5504 10	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	0.194	US \$	KG

135. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

136. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority